राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 9 अंक 335

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 14 मई, 2026

www.jagran.com
पृष्ठ 12

107 सीटें पाने वाले विजय को विश्वास मत में मिला 144 विधायकों का समर्थन >> 4

जागरण विशेष

बंजर भूमि सूखे कंठ तर कर धरती की प्यास भी बुझाएगी

झाबुआ: झाबुआ जिले के आदिवासी ग्राम राजपुरा में जन सहयोग और श्रमदान से बनाया जा रहा एक विशाल तालाब। कुछ दिन में कार्य हो जाएगा पूरा। • पेज-6

संपादकीय

पहले सरकारी तंत्र बरते किफायत: पहले केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों एवं अधिकारियों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी, उसके बाद ही जनता को उपदेश देना उचित होगा। **राजीव शुक्ला** का आलेख।

असंभव नहीं पेपर लीक होने से रोकना: सरकार को समझना होगा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा है। **संजीव जायसवाल 'संजय'** का दृष्टिकोण। • पेज-8

विमर्श

आर्थिक रणनीति में सामयिक परिवर्तन: पश्चिम एशिया में तनाव से उभरते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील की है। **विक्रांत निर्मला सिंह** का आलेख।

डालर से डगमगाता भरोसा: अमेरिकी डालर के प्रति वैश्विक स्तर पर कम होते भरोसे को विश्लेषित कर रहे हैं **डा. अश्विनी महाजन**। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का

क्यों लगती है एसी में आग!

एआइ से और स्मार्ट हुआ लैपटाप • पेज-11

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस

शाम 7:30 बजे स्थान: धर्मशाला

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

लखनऊ: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बुधवार सुबह ड्राइवर ने प्रतीक को किचन में बेसुध देख उनके साले अमन बिष्ट को सूचना दी। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट होने से मौत बताई गई है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सहित पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। (पेज-5)

सीबीएसई 12वीं में 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी सफल, छह वर्षों में सबसे कम

पिछले साल की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण, पिछले वर्ष 88.39 प्रतिशत था आंकड़ा

रीतिका मिश्रा • जागरण

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 88.39 प्रतिशत था। इस बार परिणाम में 3.19 % की गिरावट दर्ज की गई है। यह गत छह वर्षों का सबसे कम परिणाम रहा है। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान विशेष मूल्यांकन नीति लागू होने के कारण 99.37% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस बार 95 % से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है।

सीबीएसई के अनुसार, परीक्षा में शामिल 17 लाख 68 हजार 968 में से 15 लाख सात हजार 109 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 88.86% छात्राएं और 82.13 % छात्र हैं। छात्राओं का परिणाम छात्रों से 6.73 % अधिक रहा। गत वर्ष 85.70 % छात्र व 91.64 % छात्राएं पास हुईं थी। इस साल भी छात्राओं ने बाजी भले ही मारी है, पर गत वर्ष कि तुलना में छात्राओं के पास होने के प्रतिशत में 2.78 और लड़कों के पास होने में 3.57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का परिणाम 100 प्रतिशत रहा।

तिरुवनंतपुरम रीजन का प्रदर्शन सबसे बेहतर, नहीं जारी की गई मेरिट सूची: क्षेत्रवार परिणाम में तिरुवनंतपुरम रीजन सबसे बेहतर रहा। इसके बाद चेन्नई, बेंगलुरु व विजयवाड़ा रीजन रहे। बोर्ड ने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व मानसिक दबाव कम करने के उद्देश्य से इस बार भी मेरिट सूची जारी नहीं की। हालांकि, इस वर्ष 17 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने 95 व 94 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने 90 फीसद से ज्यादा अंक हासिल किए। (पेज-दो भी देखें)

88.86 प्रतिशत के साथ छात्राओं ने फिर मारी बाजी, 82.13 % छात्र हुए उत्तीर्ण

100 प्रतिशत परिणाम के साथ शत-प्रतिशत सफलता हासिल की ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों ने

2021 में 99.37 % रहा था परिणाम, 95 % अंक लाने वालों की संख्या भी घटी

नई दिल्ली में बुधवार को सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों की घोषणा के बाद प्रसन्न मुद्रा में छात्राएं। प्रेट्र >>

15 जुलाई को कंपार्टमेंट परीक्षा

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपने अंकों से असंतुष्ट होने पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकापी, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, एक या दो विषयों में असफल रहने वाले विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित होगी।

पहली बार ओएसएम प्रणाली से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

बोर्ड ने बताया कि इस वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गई। पहली बार आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया गया, जिसके तहत कुल 98 लाख 66 हजार 222 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। लगभग 70 हजार से अधिक परीक्षकों ने इन कापियों की जांच की।

किस वर्ष कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

वर्ष	पास प्रतिशत
2021	99.37
2022	92.71
2023	87.33
2024	87.98
2025	88.39

परिणाम में गिरावट की शिक्षक बता रहे ये वजहें

- एसएम प्रणाली अव्यवस्थित होने से मूल्यांकन में परेशानी
- कंप्यूटर कभी नहीं छूने वाले शिक्षकों ने भी किया डिजिटल मूल्यांकन
- शिक्षकों को कई जगह स्क्रीन पर उत्तर स्पष्ट नहीं दिखे
- भौतिकी और गणित का परिणाम आया बेहद खराब
- डिजिटल स्कैनिंग में तकनीकी गड़बड़ियों ने भी प्रभावित किया परिणाम
- उर्दू विषय की उत्तर पुस्तिकाएं उल्टी स्कैन होकर शिक्षकों तक पहुंचीं
- रसायन विज्ञान की कापियों में भूगोल के प्रश्न दिखने जैसी त्रुटियां भी सामने आईं

सोना-चांदी खरीदना महंगा, आयात शुल्क अब 15 %

अनावश्यक आयात कम करने के लिए सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट से उपजी चुनौतियों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सोने और चांदी के आयात पर अब छह प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इससे सोना-चांदी खरीदना महंगा हो जाएगा। वहीं, प्लेटिनम के आयात पर 6.4 प्रतिशत की जगह 15.4 प्रतिशत शुल्क लगेगा। बढ़ी दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सरकार चाहती है कि अनावश्यक आइटम के बढ़ते आयात को हतोत्साहित किया जाए, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में मदद मिल सके। गौरतलब है कि वैश्विक संकट के इस समय में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों से एक साल के लिए सोने की खरीदारी टालने की अपील कर चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 72 अरब डालर का सोना तो 12 अरब डालर की चांदी का आयात किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोना-चांदी और प्लेटिनम औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं और इनकी खरीदारी पर विदेशी मुद्रा भी अधिक खर्च होता है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से रुपये पर भी दबाव बढ़ता है। मई के पहले सप्ताह में देश में 690 अरब डालर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है।

सोने के मुकाबले चांदी औद्योगिक सेक्टर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सोलर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में चांदी का इस्तेमाल होता है। अब इस प्रकार के आइटम महंगे हो जाएंगे।

सराफा कारोबारियों का मानना है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के सरकार के फैसले से ज्वेलरी (आभूषणों) की खरीदारी कम हो जाएगी। उनका यह भी कहा है कि सरकार के कदम से ज्वेलरी निर्माण से जुड़े लाखों कारीगरों का परिवार चलता है। जानकार यह भी कह रहे हैं कि आयात शुल्क बढ़ने से सोने की तस्करी बढ़ जाएगी। अभी 10 ग्राम सोने के भाव में आयात शुल्क, कृषि विकास सेस और जीएसटी मिलाकर 14 हजार रुपये शामिल है, जो अब 25 हजार को पार कर जाएगा। राजस्व खुफिया और सीमा शुल्क अधिकारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सोने की तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ा सकते हैं।

आभूषण कारोबार होगा प्रभावित, तस्करी बढ़ने की आशंका पेज>>7

- प्लेटिनम पर शुल्क 15.4 प्रतिशत किया गया, बढ़ी दरें तत्काल प्रभाव से लागू
- वित्त मंत्रालय के इस फैसले से विदेशी मुद्रा का भंडार बचाने में मिलेगी मदद

सोने पर शुल्क वृद्धि का तुरंत दिखा असर

सोने पर आयात शुल्क वृद्धि के बाद गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में सात से आठ प्रतिशत की तेजी देखी गई, लेकिन सोने की बिक्री में गिरावट की आशंका से जेवरात और सराफा के अन्य आइटम बेचने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आयात शुल्क की घोषणा के बाद बुधवार को अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये की स्थिति में सुधार हुआ और यह 95.71 पर बंद हुआ। इससे एक दिन पहले यह रिकार्ड निचले स्तर 95.75 पर पहुंच गया था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है।

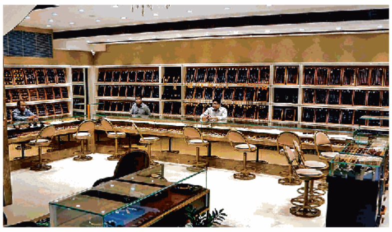

महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को खाली पड़ी आभूषण की दुकान पर ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठे कर्मी। प्रेट्र

घरेलू चीजों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक संकट के इस समय में सरकार का उद्देश्य घरेलू चीजों को बढ़ावा देना है। गैरजरूरी चीजों के आयात को हतोत्साहित करना और आवश्यक सामान के आयात को प्राथमिकता देना है। देश की वृहद अर्थव्यवस्था की मजबूती कायम रखने के लिए विदेशी खर्च कम करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के पास राजस्व की कोई कमी नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूंजीगत खर्च व अन्य सामाजिक विकास के मद में होने वाले खर्च में कोई कटौती नहीं होगी। सरकार के अन्य खर्च भी पहले की तरह जारी रहेंगे। सरकार मुख्य रूप से सिर्फ उन उपायों पर जोर दे रही है, जिससे ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत हो।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआइ के देशव्यापी छापे, पांच गिरफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में एफआइआर दर्ज करने के दूसरे दिन बुधवार को सीबीआइ ने देशभर में छापेमारी की। साथ ही जयपुर, गुरुग्राम, नासिक से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। विभिन्न शहरों में कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। दूसरी ओर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज हासिल करने को सीबीआइ की टीम ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के दफ्तर की तलाशी ली और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अफसरों से बात की।

सूत्रों के मुताबिक, जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जयपुर के मांगीलाल बिवाल, उसका भाई दिनेश बिवाल, विकास बिवाल के साथ-साथ नासिक का शुभम खैरनार व गुरुग्राम का यश यादव शामिल हैं।

यश उत्तरकाशी के मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कालेज में बीएएमएस का प्रथम वर्ष का छात्र है। सीबीआइ के अनुसार, पेपर लीक को लेकर सबसे पहले एनटीए को अलर्ट करने वाले राजस्थान के स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) से लगातार सहयोग लिया जा रहा है।

महिला समेत महाराष्ट्र और राजस्थान में कई लोग हिरासत में पेज>>5

- नासिक व गुरुग्राम से एक-एक व जयपुर से तीन गिरफ्तार
- एनटीए मुख्यालय में दिनभर चलती रही सीबीआइ छानबीन

प्रश्नपत्र पहुंचाने की प्रक्रिया का भी हो रहा विश्लेषण

सीबीआइ के अफसरों के मुताबिक, पेपर लीक से जुड़े सभी आयामों की जांच की जा रही है। इनमें प्रश्नपत्र को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रणालीगत खामी के साथ ही एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता तक शामिल है। कहा, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का विस्तृत तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

कई डिजिटल डिवाइस जब्त

अफसरों ने बताया कि संदिग्धों से मोबाइल फोन, लैपटाप समेत कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। 30 वर्षीय शुभम खैरनार को पूछताछ के लिए नासिक से दिल्ली लाया जा रहा है। शुभम पर लीक पेपर को हासिल करने व बांटने में अहम भूमिका निभाने का शक है। वहीं, सीबीआइ टीम ने एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए 18 आरोपितों से पूछताछ की। उसी के बाद पांच लोगों को पकड़ा।

असम विधानसभा में यूसीसी का मसौदा 26 मई को होगा पेश

गुवाहाटी: असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मसौदा 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहली मंत्रिमंडल बैठक में बुधवार को राज्य में यूसीसी लागू करने को मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूसीसी लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आदिवासी आबादी को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (पेज-5)

चीन ने खींची लक्ष्मण रेखा, ट्रंप बोले ईरान युद्ध में नहीं चाहिए मदद

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीन दिनी बीजिंग दौरे से ठीक पहले चीन ने वार्ता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वह ताइवान, मानवाधिकार व चीन के विकास समेत चार मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करेगा। वहीं ट्रंप ने चीन पहुंचने से पहले कहा, उन्हें ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए चीन की मदद नहीं चाहिए। ट्रंप की राष्ट्रपति शी चिनफिंग संग गुरुवार को शिखर वार्ता होगी। (पेज-7)

मोदी के काफिले में कटौती, कैबिनेट बैठक में जाते वक्त थीं सिर्फ दो गाड़ियां

नई दिल्ली में बुधवार को वाहन संख्या में कटौती के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काफिला। एएनआइ

- "ब्लू बुक" में तय सुरक्षा मानकों को बरकरार रखते हुए कम की गई प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां
- गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने काफिले की आधी गाड़ियां हटाईं
- भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और रेखा गुप्ता ने भी उठाए कदम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए ईंधन की बचत की अपील का असर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पूरे देश में दिखने लगा है। खुद पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों में 50 फीसदी की कटौती कर दी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में जाते समय मोदी के काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां देखने को मिली। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के काफिले की गाड़ियों में कटौती कर दी गई। वहीं, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मप्र के मोहन यादव, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के नायब सिंह सैनी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जैसे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व कई राज्यपालों ने भी इसी तरह गाड़ियों की संख्या में कटौती की घोषणा की।

पीएम की सुरक्षा संभाल रहे एसपीजी के अनुसार, "ब्लू बुक" में दर्ज मानकों से समझौता किये बिना सुरक्षा काफिले को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। "ब्लू बुक" में वीवीआइपी की सुरक्षा के निर्देश होते हैं, जिनका अक्षरशः पालन सुरक्षा एजेंसी को करना पड़ता है। काफिले में ईवी गाड़ियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है, पर इसके लिए नई ईवी गाड़ियों की खरीद नहीं होगी।

एक अधिकारी ने कहा, पीएम की अपील को खर्च कटौती से जोड़कर न देखें पेज>> 3

गाड़ियों के उपयोग को तर्क संगत बनाने की कवायद

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को असम में हिमंत बिस्वा सरमा के शपथग्रहण के लिए पहुंचे पीएम के काफिले में गाड़ियों में कटौती की गई थी। सुरक्षा कारणों से कटौती की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। मोदी समेत शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के काफिले में कटौती के बाद सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों में गाड़ियों के उपयोग को तर्क संगत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कहा है कि वे अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करेंगे।

कैबिनेट का फैसला

मोदी सरकार के निर्णय से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने में मिलगी मदद, सरकार ने कहा- यह रणनीतिक जरूरत, 7.50 करोड़ टन कोयला या लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है योजना के तहत

कोयले से गैस बनाने वाली 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संघर्ष ने देश के समक्ष जिस तरह के ऊर्जा संकट का खतरा पैदा किया है, उससे निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति के तहत बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन (कोयले से गैस बनाने) की परियोजना को मंजूरी दी गई। यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।

पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर तेल-गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। एयरलाइंस सहित कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। भारत एलएनजी का 50 प्रतिशत से अधिक, यूरिया का करीब 20, अमोनिया का 100 और मेथनोल का 80-90 प्रतिशत आयात करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने उक्त उत्पादों के आयात में करीब 2.77 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोयला खदानों से गैस निकालने की योजना वैसे भारत में ढाई दशक पुरानी है लेकिन अभी तक कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है।

सरकार ने कहा है कि कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देना अब रणनीतिक जरूरत बन गया है। कैबिनेट से स्वीकृत योजना के तहत करीब 7.50 करोड़ टन कोयला या लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जो 2030 तक 10 करोड़ टन गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। नई परियोजनाओं में प्लांट और मशीनरी की लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक बतौर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि 5,000-12,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही' सिंथेसिस उत्पादन को कोयला गैसीकरण' उप-क्षेत्र में कोयला लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिससे निवेशकों को लंबी अवधि की नीतिगत निश्चितता मिलेगी। कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट से सिंगैस उत्पादन होता है जो एक तरह की गैस है जिसे कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इससे सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनोल, अमोनिया, यूरिया व अन्य रसायन बनाए जाते हैं।

इस योजना से ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश जुटने की उम्मीद है। कोयला क्षेत्रों में करीब 50,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। 7.5 करोड़ टन गैसीकरण से सरकार को सालाना 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों को बल मिलेगा। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार (करीब 401 अरब टन) व लिग्नाइट भंडार (47 अरब टन) हैं। कोयला देश की ऊर्जा मिश्रण का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है।

प्रतीकात्मक

जानिये क्या है सिंथेसिस गैस

सिनगैस या सिंथेसिस गैस कृत्रिम गैस मिश्रण है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोआक्साइड गैस होती हैं। इस गैस में अक्सर थोड़ी मात्रा कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन की भी होती है। सिंथेसिस अत्यंत ज्वलनशील होती है और आमतौर पर कोयला, बायोमास जैसे कार्बन-युक्त पदार्थों को ऊंचे तापमान पर गर्म करके बनाई जाती है। इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब गैसोलीन की सप्लाई सीमित होती थी, तब इसका इस्तेमाल गैसोलीन के विकल्प के तौर पर किया जाता था।

15 जून तक नालों की सफाई पूरी करने के सख्त निर्देश उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिए। बुधवार को डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नालों के लिए 'गाद हटाने की कार्ययोजना-2026' की समीक्षा की।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार, 14 मई, 2026

आज का मौसम

तेज धूप निकलने से गर्मी में वृद्धि होगी। आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
14 मई	39.0	27.0
15 मई	40.0	27.0
नोएडा		
14 मई	37.0	26.0
15 मई	38.0	27.0
गुरुग्राम		
14 मई	38.0	21.0
15 मई	39.0	23.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम दो रुपये बढ़ाए

नई दिल्ली: अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में दो रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें गुरुवार से लागू होंगी। कंपनियों का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। दिल्ली समेत एनसीआर में अब टोकन, बल्क वेंडेड दूध 56 रुपये से बढ़कर 58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। टोंड मिल्क 60 रुपये, डबल टोंड 52 रुपये, गाय का दूध 62 रुपये, प्रीमियम दूध 68 रुपये और प्रो मिल्क 72 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। (जासं)

आरएमएल के हास्टल में खाने की दाल में निकला काकरोच

नई दिल्ली : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक हास्टल मेस में परोसी गई दाल में काकरोच-कीड़े और खराब सलाद मिलने पर रेजीडेंट डाक्टरों और छात्रों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने मेस में साफ-सफाई तथा भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। आरोप है कि मेस में लंबे समय से सफाई की स्थिति खराब है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही थी। (जासं)

पास मामले में डीडीसीए सचिव समेत तीन को नोटिस

नई दिल्ली: आइपीएल मैचों के काम्प्लीमेंट्री पास और टिकटों को ब्लैक के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा समेत तीन पदाधिकारियों को नोटिस भेजा है। इसमें सीईओ आरआर सिंह और पीए राकेश को गुरुवार को जांच में शामिल होने को कहा गया। (जासं)

अधिकारियों व कर्मियों के विदेश दौरों पर रोक, सप्ताह में एक दिन नो-कार डे होगा

दिशा-निर्देश ▶ ऐसे सभी प्रस्ताव तत्काल रद, विदेशी दौरे के लिए स्वीकृत छुट्टियां निरस्त

निरीक्षणों, उद्घाटन कार्यक्रमों के लिए अधिकारी करेंगे पूल वाहनों का उपयोग

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने की अपील पर दिल्ली सरकार के तीन विभागों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें वाहनों का उपयोग सीमित करने के साथ-साथ विदेश दौरों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनावश्यक यात्रा को कम करने के लिए वर्चुअल (आनलाइन) बैठकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन नो-कार डे होगा, जिस दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन या पूल परिवहन व्यवस्था का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग में मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

निर्देश में कहा गया है अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वाहनों के उपयोग को कम से कम किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन और ईवी को बढ़ावा दिया जाएगा। निरीक्षणों, फील्ड दौरों और कार्यालय यात्रा के लिए जहां भी संभव हो, वाहन पूलिंग, कार पूलिंग अपनाई जानी चाहिए। निरीक्षण, उद्घाटन और सरकारी कार्यक्रमों के लिए अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों, पूल वाहनों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर एक साथ यात्रा करने की कोशिश करेंगे। डीजल से चलने वाले या ट्रैक्टर पर लगे पंपों के स्थान पर इलेक्ट्रिक पंपों और स्थायी पंपिंग स्टेशनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की अपील पर पूरी भावना से काम कर रहे : वर्मा

पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर हम पूरी भावना से काम कर रहे हैं। जारी किए गए दिशा निर्देश का मकसद शासन को ज्यादा कुशल और जमीनी बनाना है। हमने इस बारे में सोच-समझकर फैसला लिया है।

बस व मेट्रो से चल रहे मंत्री, आइआरएस अधिकारी साइकिल से पहुंचे दफ्तर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शुरू किया सार्वजनिक परिवहन से सफर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार के कार्यालय के साथ ही एनडीएमसी ने भी इस अपील को आत्मसात करने के लिए काम शुरू कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मेट्रो और बस से सफर करके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की नागरिकों से अपील की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मंत्री, भाजपा के विधायक, पार्षद भी सार्वजनिक परिवहन व कार पूलिंग को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने विकासपुरी से लेकर दिल्ली सचिवालय तक डीटीसी बस से सफर किया। कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने शामनाथ मार्ग के सरकारी आवास से लेकर दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो से सफर किया।

मेट्रो से सफर करने जाते दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा। सौजन्य : दिल्ली सरकार

दोनों मंत्रियों ने नागरिकों से संवाद भी किया। वहीं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी आइजीआइ एयरपोर्ट ईवी वाहन से पहुंचे। उधर, दिल्ली में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात आइआरएस अधिकारी नरेंद्र यादव साइकिल से दफ्तर पहुंचकर उदाहरण पेश कर रहे हैं।

एक जून से वर्क फ्राम होम मोड में आ जाएंगी ढाई हजार आइटी कंपनियां

आदित्य राज ● जागरण

▶ प्रधानमंत्री की अपील पर आइटी कंपनियों ने शुरू की तैयारी

▶ सड़कों पर हजारों निजी और व्यावसायिक वाहनों में आएगी कमी

गुरुग्राम: पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का व्यापक असर एक जून से साइबर सिटी में दिखाई देगा। लगभग ढाई हजार कंपनियां एक जून से वर्क फ्राम होम मोड में भी आ जाएंगी। इसके लिए कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है। 30 मई तक सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार सिस्टम विकसित होने के बाद जब तक वर्क फ्राम होम मोड में रहना होगा, कंपनियां रहेंगी। इससे लाभ यह होगा कि हजारों निजी एवं व्यावसायिक वाहन (टैक्सियां) सड़कों से गायब हो जाएंगी। इससे न केवल पेट्रो पदार्थों की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण का स्तर और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

साइबर सिटी में लगभग छह हजार आइटी एवं टेलीकाम सेक्टर की कंपनियां संचालित हैं। इनमें से सैकड़ों कंपनियां का 10 से 20 प्रतिशत तक काम कोरोना संकट के समय से ही वर्क फ्राम होम मोड में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद लगभग ढाई हजार कंपनियां अपने उन कार्यों को वर्क फ्राम मोड में लाएंगी, जिन कार्यों को कर्मचारी घर से कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित किसी कार्य को वर्क फ्राम मोड में नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसे वर्क फ्राम होम मोड में नहीं लाया जाएगा। ऐसे कार्यों को कर्मचारी सौ फीसदी कैमरों की नजर में करते हैं।

वर्क फ्राम होम के लिए आवश्यक तैयारी : आइटी प्रोफेशल्स का कहना है कि वर्क फ्राम होम या रिमोट वर्किंग के लिए आइटी कंपनियों को लैपटाप, वीडियो कांफ्रेंसिंग टूल एवं क्लाउड-आधारित प्रोजेक्ट प्रबंधन साफ्टवेयर की व्यवस्था करनी होती है। डाटा सुरक्षा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की सुविधा देनी होती है। ये सुविधाएं विकसित करने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। सुविधाएं विकसित होने के बाद प्रबंधन की एक टीम मौके पर जांच करती है, ताकि कोई डाटा चोरी की गुंजाइश न रहे। एक बार सुविधाएं विकसित करने के बाद फिर आगे दिक्कत नहीं रहती है। वर्क फ्राम होम मोड से उन कर्मचारियों को दिक्कत होती है, जिनके घर में जगह कम है। परिवार डिस्टर्ब होने लगता है। फिर कर्मचारी मोड से बाहर निकलने की मांग शुरू कर देते हैं।

प्रधानमंत्री की अपील राष्ट्रहित में है। इसके ऊपर कंपनियां गंभीरता से विचार कर रही हैं। कंपनियों को वर्क फ्राम होम मोड में भी आने की अपील कर दी गई है। एक जून से लगभग आधी कंपनियां वर्क फ्राम होम मोड में भी आ जाएंगी। इससे सड़कों पर से हजारों वाहनों का दबाव कम होगा। कोरोना के समय काफी कंपनियां वर्क फ्राम होम मोड को अपना चुकी हैं। -**प्रदीप यादव, प्रेसिडेंट, हाइटेक इंडिया (आइटी एवं टेलीकाम कंपनियों का संगठन)**

नीरज ठाकुर और देवेश चंद्र श्रीवास्तव संभालेंगे दिल्ली की कानून-व्यवस्था की कमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई और सख्त पुलिसिंग के लिए पहचाने जाने वाले 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर को विशेष आयुक्त, ट्रैफिक डिवीजन से हटाकर विशेष आयुक्त कानून-व्यवस्था जोन-2 बनाया गया है।

इस जोन में दक्षिणी, पश्चिमी और लुटियंस दिल्ली के अहम इलाके आते हैं। वहीं गैंगस्टर और संगठित अपराध के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई कर चुके 1995 बैच के आइपीएस अधिकारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव को क्राइम डिवीजन से विशेष आयुक्त, कानून-व्यवस्था जोन-1 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जोन में उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी दिल्ली के इलाके आते हैं।

नीरज ठाकुर।

देवेश चंद्र श्रीवास्तव।

▶ दोनों बनाए गए विशेष आयुक्त, कानून-व्यवस्था, नौ वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए चर्चित 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी मनीष कुमार अग्रवाल को इंटेलिजेंस डिवीजन से ट्रैफिक पुलिस का विशेष पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इसी बैच के सख्त अनुशासन और कड़े फैसलों के लिए प्रसिद्ध आइपीएस अधिकारी अजय चौधरी को विजिलेंस डिवीजन से प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन में नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस की कई बड़ी आपराधिक गुत्थियां सुलझाने वाले और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए चर्चित 1997 बैच के आइपीएस अधिकारी हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को विशेष आयुक्त, क्राइम बनाया गया है।

वहीं भ्रष्टाचार और विभागीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने वाले आइपीएस अधिकारी अतुल कटियार को वेलफेयर डिवीजन से विजिलेंस डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, कानून व्यवस्था और फोर्स मैनेजमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाले आइपीएस अधिकारी विजय कुमार को आर्म्ड पुलिस के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और खुफिया सूचनाओं पर तेज काम करने के लिए पहचाने जाने वाले आइपीएस अधिकारी के. जगदेसन को प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन से इंटेलिजेंस डिवीजन भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से दिल्ली पुलिस को लाभ होग और कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी।

बाहरी इलाकों में बनेंगे वेयरहाउस, माल उतारने बाजारों में नहीं आएंगे ट्रक

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: आने वाले समय में बड़े ट्रकों से शहर में सामान लाए जाने की निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। दिल्ली सरकार इसे लेकर जो लाजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति बना रही है उसकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। नई नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में लाजिस्टिक्स वितरण केंद्र (यूसीएलडीसी) विकसित किए जाएंगे, जहां कारोबारी बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर जमाकर जरूरत के हिसाब से छोटे डिलिवरी वाहनों से शहर के भीतर माल मंगा सकेंगे। साथ ही, बाजार स्तर के गोदाम और छोटे पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित हो सकेगी।

विशेषज्ञों का कहना है नीति पर ठीक से काम हुआ और सही तरीके से अमल हुआ तो यह राजधानी में माल ढुलाई व आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल और कम लागत वाला बनाने के साथ-साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

पीएम की अपील के बाद क्रेडाई ने नेटकान 2026 को एम्स्टर्डम से भारत किया शिफ्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने, गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को कम करने, ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत करने की अपील के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की संस्था कान्फेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस आफ इंडिया (क्रेडाई) ने बड़ा फैसला लिया है।

क्रेडाई ने वार्षिक सम्मेलन नेटकान 2026 के 23वें संस्करण को एम्स्टर्डम के बजाय भारत में आयोजित करने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि यह फैसला प्रधानमंत्री के 'नेशन फर्स्ट' विजन और देश की मौजूदा भावनाओं के अनुरूप लिया गया है।

क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पिछले छह महीनों से चल रही थीं लेकिन प्रधानमंत्री की अपील और देश की भावना को देख क्रेडाई ने आयोजन को भारत में कराने का फैसला लिया। वर्तमान समय में रियल एस्टेट सेक्टर कई चुनौतियों से गुजर रहा है। सीमेंट, स्टील और अन्य जरूरी कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से निर्माण लागत बढ़ रही है। श्रमिकों की कमी भी कई परियोजनाओं को प्रभावित कर रही है। ऐसे माहौल में सभी सेक्टर्स के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में योगदान देना और भी जरूरी हो जाता है। हर साल होने वाले इस सम्मेलन में देशभर से एक हजार से अधिक डेवलपर्स, निवेशक, आर्किटेक्ट, नीति निर्माता और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

मनी लांड्रिंग मामले में जारी समन को राबर्ट वाड्रा ने दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: गुरुग्राम के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे में अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को उद्यमी राबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका को गुरुवार को न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है।

अधिवक्ता प्रतीक कृष्ण चड्ढा के माध्यम से दायर याचिका में वाड्रा ने दलील दी कि इसमें कोई गैर-कानूनी काम शामिल नहीं था। वाड्रा ने अपनी याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है और इसे रद किया जाना चाहिए।

मामले में जुलाई 2025 में ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया था और इसके बाद अदालत ने इसका संज्ञान लिया था। अदालत ने वाड्रा को 16 मई को पेश होने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन के एक प्लाट से जुड़ा है।

संजय कपूर की मां की संपत्ति की लड़ाई पर आज सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर के दायर एक आवेदन पर 14 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इसमें उन्होंने संजय की पत्नी प्रिया कपूर और अन्य को 'आरके फैमिली ट्रस्ट' के कार्यों में दखलंदाजी रोकने का निर्देश देने की मांग की है, जब तक कि मध्यस्थता की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के बड़े औद्योगिक घराने के 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद मामले में पीठ ने कहा,"ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां महाभारत बहुत छोटा लगेगा।" पीठ ने कहा, "हम मध्यस्थ से छह अगस्त तक प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद मामला आगे बढ़ाएंगे।"

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मई को 80 वर्षीय रानी कपूर और उनकी दूसरी बहू प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद में मध्यस्थ के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ को नियुक्त किया था। यह मामला मंगलवार को जस्टिस जेबी पार्डीवाला और उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष पेश किया गया।

▶ रानी कपूर की बहू प्रिया को आरके फैमिली ट्रस्ट के कार्यों में दखल से रोकने की मांग

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नए आवेदन में रानी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रिया कपूर और कुछ अन्य कंपनियों और विवादित पारिवारिक संपत्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं।

कपूर परिवार पर पोस्ट मामले में एन्फ्लुएंसर गिरफ्तार : दक्षिणी पश्चिमी पुलिस ने 'द स्किन डाक्टर' के नाम का अकाउंट इस्तेमाल करने वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एन्फ्लुएंसर ने बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार के खिलाफ पोस्ट किए थे।

इलाज के लिए मेदांता पहुंचीं सोनिया गांधी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट से संबंधी समस्या होने पर बुधवार सुबह सात बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथ उनके बेटे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं।

सोनिया गांधी

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, करीब पांच घंटे तक चले उनके इलाज और जांच के बाद अस्पताल से उन्हें दोपहर 12 बजे छुट्टी दे दी गई। मेदांता के गैस्ट्रोएंटरोलाजी विशेषज्ञ डा. रणधीर सूद की देखरेख में उनका इलाज किया गया। गुरुग्राम कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने बताया कि सुबह सोनिया गांधी के मेदांता अस्पताल में लाए जाने की सूचना मिली थी। उन्हें पेट से संबंधी कोई समस्या थी। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और उन्हें वापस दिल्ली ले जाया गया। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इंटरनेट मीडिया पर सोनिया के रूटीन चेकअप की जानकारी दी।

केवी-जेएनवी आगे, सरकारी स्कूलों ने भी बनाई बढ़त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

84.22 प्रतिशत रहा प्राइवेट स्कूलों का परिणाम सबसे कम

▶ सरकारी का 89, निजी स्कूलों का 84 % रहा परिणाम

▶ इस साल सरकारी स्कूलों में 1,63,307 ने परीक्षा दी थी

बोर्ड परीक्षा में संस्थानवार परिणाम में देशभर में सरकारी संस्थानों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय (केवी) और जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) ने सबसे शानदार परिणाम दर्ज किया है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का परिणाम सबसे कम रहा। प्राइवेट स्कूलों के परिणाम में गिरावट ने कई शिक्षा विशेषज्ञों को चौंकाया है। उनका मानना है कि अनुप्रयोग-आधारित और वैचारिक पैटर्न में बदलाव के कारण इस बार पारंपरिक तैयारी माडल वाले कई स्कूल प्रभावित हुए हैं।

सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों का पास प्रतिशत 98.55 रहा, जो सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है। इसके ठीक बाद जवाहर नवोदय विद्यालयों का परिणाम 98.47 प्रतिशत दर्ज किया गया। सरकारी स्कूलों का कुल परिणाम 89.55 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.20 प्रतिशत से काफी अधिक है। वहीं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का परिणाम 86.07 प्रतिशत और एकलव्य माडल रेजिडेंशियल स्कूलों (ईएमआरएस) का परिणाम 85.55 प्रतिशत दर्ज किया गया। प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 84.22 प्रतिशत रहा, जो सरकारी स्कूलों से भी कम है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय व नवोदय विद्यालयों में अनुशासित शैक्षणिक वातावरण, नियमित मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षा की व्यवस्थित तैयारी का असर परिणामों में दिखाई देता है। वहीं सरकारी स्कूलों का परिणाम भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। इस बार अपेक्षाकृत कठोर मूल्यांकन, योग्यता-आधारित प्रश्नों की ओर बदलाव और डिजिटल मूल्यांकन के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) होने के बाद भी सरकारी स्कूलों का परिणाम अच्छा रहा।

नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित सेंट थामस स्कूल में मोबाइल फोन पर सीबीएसई के कक्षा 12वीं के परिणाम देखती छात्राएं। चंद्र प्रकाश मिश्र

संस्थानवार परिणाम

संस्थान	परिणाम (%)
केवी	98.55
जेएनवी	98.47
सरकारी स्कूल	89.55
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	86.07
ईएमआरएस	85.55
प्राइवेट स्कूल	84.22

दिल्ली में आश्रय प्रबंधन एजेंसी के खिलाफ बिल बढ़ाने का मामला दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआइबी) द्वारा रात के आश्रयों के प्रबंधन के लिए अनुबंधित एक कंपनी के खिलाफ फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर बिल बढ़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुहेल खान और अन्य को एक प्राथमिकी में नामित किया है। इसके बाद यह शिकायत मिली कि डीयूएसआइबी को अत्यधिक बिलिंग की गई, जिसमें ऐसे लोग कर्मचारियों के रूप में दिखाए गए जो या तो कहीं और काम कर रहे थे या अन्य व्यवसायों में लगे हुए थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया, "डीयूएसआइबी के तहत रात के आश्रयों के संचालन और प्रबंधन से संबंधित टेंडर धोखाधड़ी से एनजीओ/शेल्टर प्रबंधन एजेंसी को दिए गए थे और रिकार्ड में कई फर्जी कर्मचारियों को शामिल करके गलत लाभ प्राप्त किए गए, जो वास्तव में कभी काम नहीं करते थे।" इससे सरकार के खजाने को गलत नुकसान हुआ।"

▶ डीयूएसआइबी की अत्यधिक बिलिंग पर सीबीआइ ने की जांच, फर्जी कर्मियों को वेतन दिए

यह कार्रवाई लगभग एक वर्ष तक चलने वाली सीबीआइ की जांच के बाद की गई, जिसमें अनियमितताओं के आरोपों की विस्तार से जांच की गई। इसने यह उजागर किया कि कई लोग, जो अन्य स्वतंत्र व्यवसायों में लगे हुए थे या कहीं और काम कर रहे थे, उन्हें रात के आश्रयों में स्टाफ के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया और उन्हें बैंक खातों से वेतन दिया गया।

पार्षद कार्यालय में कैंप लगाकर कर डाली 50 लोगों से ठगी, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: यमुनापार में एक ऐसा मामला आया जिसमें जनप्रतिनिधि के आफिस में ही कैंप लगाकर लगभग 50 लोगों को ठग लिया गया। ठग ने खुद को ग्रामीण विकास मंत्रालय का कर्मचारी बताकर अटल पेंशन योजना के खाते खुलवाकर हर माह तीन हजार रुपये की पेंशन देने का झांसा दिया। फर्जी ई-मेल के जरिए पार्षद कार्यालय को कैंप लगाने की जानकारी दी। हालांकि, जब ठग लोगों से नकद 220 रुपये फीस लेने लगे तो पार्षद को शक हुआ। ठग आलोक जैन को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

झिलमिल कालोनी वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि गत सोमवार को उनके पास एक काल आई और काल करने वाले ने खुद को ग्रामीण विकास मंत्रालय से बताया।

पोर्न एप पर हाई कोर्ट ने कहा, देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की नहीं दे सकते अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पोर्न को बढ़ावा देने वाले एप पर सख्त कार्रवाई करने का गूगल व एपल को आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की अनुमति नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि एपल के एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐसे एप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि गूगल व एपल जैसे मध्यस्थों की जिम्मेदारी है कि प्ले-स्टोर व एपल स्टोर पर अपलोड किए जाने के दौरान वे ऐसे एप के खिलाफ कार्रवाई करें।

पीठ ने कहा कि ऐसे एप की पहुंच को देखते हुए अदालत की राय है कि आइटी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम- 2021 के तहत इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को न केवल ऐसी कोई शिकायत मिलने पर, बल्कि ऐसे एप को अपने प्लेटफार्म पर अपलोड करने की अनुमति देते समय भी पूरी सावधानी बरतते हुए सबसे अहम भूमिका निभानी होगी। उक्त टिप्पणी के साथ पीठ ने निर्देश दिया कि मध्यस्थ यह सुनिश्चित करें कि ऐसे एप का प्रसार तुरंत रोका जाए और 2021 के आइटी नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। साथ ही पीठ ने गूगल, एपल और केंद्र सरकार को मामले पर नोटिस जारी कर जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

▶ हाई कोर्ट का आदेश- पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति में शामिल मोबाइल एप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे गूगल व एपल

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

याचिकाकर्ता रुबिका थापा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गूगल प्ले स्टोर व एपल के एप स्टोर पर कई ऐसे एप मौजूद हैं, जो अश्लील सामग्री, अनैतिक तस्करी, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों के सेवन, हथियारों के अवैध व्यापार और संगठित अपराध की अनुमति देते हैं।

नोएडा हिंसा में दो आरोपितों पर लगा रासुका

जागरण संवाददाता, नोएडा : पुलिस ने फेज दो औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि के लिए 13 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार मजदूर बिगुल दस्ता के सदस्य सत्यम वर्मा और आकृति पर बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर दोनों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस जांच में आंदोलन के दौरान दोनों की हिंसा, आगजनी व अराजक गतिविधियों में अहम भूमिका सामने आई थी। फिलहाल दोनों जेल में हैं। वहीं, आरोपित आदित्य आनंद और रुपेश राय पर भी रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच टीम ने 19 अप्रैल को सत्यम वर्मा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था जबकि आकृति को भी साक्ष्य मिलने पर पकड़ा था। दोनों ने श्रमिक एवं महिलाओं को उकसाकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची थी।

1.61 लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया था भारत ने पिछले साल। विश्व में भारत खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है।

उप्र में 50 से अधिक कर्मियों वाले संस्थानों में सप्ताह में दो दिन हो 'वर्क फ्राम होम'

जागरण टीम, नई दिल्ली

- उप्र, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में छोटा होगा मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला
- सप्ताह में एक दिन वाहन रहित दिवस मनाएंगे कई राज्य, वर्क फार्म होम को देंगे बढ़ावा

योगी आदित्यनाथ। फाइल

संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी की अपील के समर्थन में कई राज्य आगे आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड व हरियाणा ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला छोटा करने का फैसला किया है। उप्र सरकार ने 50 से अधिक कर्मियों वाले संस्थानों में हफ्ते में कम से कम दो दिन 'वर्क फ्राम होम' अपनाने पर जोर दिया है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार व उत्तराखंड ने भी वर्क फार्म होम को बढ़ावा देने के साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया है।

बुधवार को विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों व वरिष्ठ अफसरों से हफ्ते में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वाहन फ्लीट 50 प्रतिशत तक कम करने और अगले छह माह तक विदेश यात्राओं से परहेज करने का आह्वान किया। कहा,मंत्री हफ्ते में एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कार पूलिंग अथवा साइकिल का उपयोग करें। सचिवालय,निदेशालय में एयरकंडीशनर तथा लिफ्ट के आवश्यकता-आधारित उपयोग हो। उन्होंने एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने खाद्य तेल की खपत कम करने, सोने के अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, पीएनजी आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने और वर्षा जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने की अपील की। उप्र विधान सभा की संसदीय समितियों के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में एक दिन बगैर वाहनों के काम चलाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बुधवार को अधिकांश वरिष्ठ आइएएस-आइपीएस अधिकारियों ने स्वयं के अतिरिक्त वाहन मूल विभागों को लौटा दिए। अब वे मात्र एक वाहन ही अपने पास रखेंगे। उत्तराखंड में बुधवार को कैबिनेट बैठक में हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल-डे और सरकारी व निजी क्षेत्रों में वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सरकारी एवं निजी भवनों में एसी के प्रयोग को सीमित किया जाएगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक कार से चलने लगे हैं। बुधवार को कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए वह एक ही वाहन से आए। वर्क फ्राम होम के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग की अपील की है। खाद्य तेल के उपयोग का निर्देश सरकारी कैंटीनों पर लागू कर दिया गया है। बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा,सुरक्षा सलाहकार से चर्चा के बाद काफिले में भी आवश्यकतानुसार वाहन रखे जाएंगे। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड व सिंचाई विभाग ने अफसरों व कर्मियों के लिए वाहनों का उपयोग सीमित करने के साथ विदेश दौरों पर अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी है।

गुरुग्राम में एक जून से वर्क फ्राम होम मोड में आएंगी ढाई हजार आइटी कंपनियां : गुरुग्राम में करीब छह हजार आइटी एवं टेलीकाम सेक्टर की कंपनियां हैं। आइटी एवं टेलीकाम सेक्टर की कंपनियों के संगठन 'हाइटेक इंडिया' के प्रेसिडेंट प्रदीप यादव ने कहा, करीब ढाई हजार कंपनियां एक जून से वर्क फ्राम होम मोड में आ जाएंगी। इसके लिए कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है।

बिहार में साइकिल से कोर्ट पहुंचे जिला जज : बिहार में औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार व परिवार न्यायालय के जज अरुण कुमार बुधवार को साइकिल से न्यायालय पहुंचे।

एक अधिकारी ने कहा, पीएम की अपील को खर्च में कटौती से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए

प्रथम पृष्ठ से आगे

एक अधिकारी ने कहा,पीएम की अपील को खर्च में कटौती से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग तक सीमित है। खर्च में कटौती का आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। संकट के समय सरकारी खर्चे में कटौती का सामान्य तरीका पूंजीगत, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के खर्चे में कटौती से होता है, पर मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। विकास की गति बनाए रखने को पूंजीगत खर्च के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाएं भी पूर्ववत जारी रहेंगी। सिर्फ खर्च को तर्कसंगत बनाकर खजाने पर आए अतिरिक्त बोझ को कम किया जा रहा है। रविवार को हैदराबाद से मोदी की अपील का स्पष्ट असर बुधवार को कैबिनेट बैठक के पहले दिखा। जहां पीएम के काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां देखने मिली। बैठक में मोदी ने मंत्रियों से कहा,पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर उन्हें खर्च कटौती पर ध्यान देना चाहिए। संसाधनों के व्यय को सोच-समझकर कम करना चाहिए।

120 गाड़ियों के काफिले संग पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऊर्जा बचाने की अपील के बाद मध्य प्रदेश में कई स्तर पर प्रयास देखे जा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है, लेकिन भाजपा के कुछ नेता बाज नहीं आ रहे हैं। भिंड में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन यादव बुधवार को समर्थकों के साथ 120 गाड़ियों के काफिले को लेकर ग्वालियर से भिंड पहुंचे। यादव मौ क्षेत्र के सक्रिय भाजपा नेता हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी वंदना यादव मौ नगर परिषद की अध्यक्ष हैं।

सीबीआइ प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया

प्रवीण सूद। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआइ प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया। यह उनका दूसरा विस्तार है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सूद का कार्यकाल 24 मई, 2026 के बाद एक वर्ष बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रवीण सूद 25 मई, 2023 को दो साल के लिए सीबीआइ निदेशक बनाए गए थे। गत वर्ष कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। अफसरों ने कहा, पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति की गत दिवस बैठक के बाद सूद का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस समिति में सीजेआइ सूर्यकांत व लोस में नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। बैठक के बाद राहुल ने सूद के चयन की प्रक्रिया पर असहमति जताई थी।

धान समेत खरीफ की 14 फसलों का बढ़ा एमएसपी

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये की बढ़ोतरी, तिलहन-दलहन पर फोकस

सरकार की खाद्य तेल आयात घटाने और पोषण सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नरेन्द्र मोदी। फाइल

खरीफ सीजन की बोआई से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का निर्णय लिया है। धान के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार का फोकस तिलहन, दलहन और मोटे अनाज पर है। सूरजमुखी, कपास, नाइजरसीड, तिल और अरहर जैसी फसलों के एमएसपी में भारी वृद्धि से स्पष्ट है कि सरकार खेती के पैटर्न में बदलाव कर खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रही है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पीएम नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में खाद्य तेलों की खपत कम करने की अपील की थी। उन्होंने अत्यधिक तेल सेवन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए संयमित उपयोग पर जोर दिया था। सरकार अब इस सोच को कृषि नीति से जोड़ रही है, जिससे किसानों को अधिक तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2461 रुपये होगा। सूरजमुखी बीज में 622 रुपये, कपास में 557 रुपये, नाइजरसीड में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये की वृद्धि की गई है।

किसान के हितों की रक्षा करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए राजग सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि देश के करोड़ों खाद्य उत्पादक को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिले। इससे उनके जीवन में अधिक समृद्धि आएगी। **-नरेन्द्र मोदी, पीएम**

भारत खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है, और पिछले वर्ष 1.61 लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात हुआ था। सरकार का मानना है कि बेहतर एमएसपी से किसान पारंपरिक फसलों से तिलहन और दलहन की ओर बढ़ेंगे, जिससे आयात बिल कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी।

प्रमुख खरीफ फसलों का नया एमएसपी

फसल	एमएसपी (रुपये/क्विंटल)	बढ़ोतरी (रुपये में)
धान (सामान्य)	2441	72
ज्वार (हाइब्रिड)	4023	324
बाजरा	2900	125
रागी	5205	319
मक्का	2410	10
अरहर	8450	450
मूंग	8780	12
उड़द	8200	400
मूंगफली	7517	254
सूरजमुखी	8343	622
सोयाबीन	5708	380
तिल	10346	500
नाइजरसीड	10052	515
कपास (लंबा रेशा)	8667	557

दलहन क्षेत्र में भी सरकार ने मजबूत संदेश दिया है। अरहर का एमएसपी 450 रुपये बढ़ाकर 8450 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार के मुताबिक किसानों को लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य सुनिश्चित किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी नीति अब अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन चुकी है।

स्वदेशी तकनीक से बनेगी देश की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल लाइन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कैबिनेट ने 20,667 करोड़ की लागत वाली अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को दी मंजूरी
- 284 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पांच लाख लोगों को सीधा लाभ होगा, रोजगार सृजन होगा

देश में पहली बार 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के लिए रेल लाइन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी। 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली यह 134 किमी लंबी डबल रेल लाइन स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी, जिसे पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके पूरा होने पर भारत को पहली बार ऐसा रेल कारिडोर मिलेगा, जो बुलेट ट्रेन से कम खर्चीला पर मौजूदा ट्रेनों से ज्यादा तेज होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद कहा, यह सिर्फ नई रेल लाइन नहीं, बल्कि गुजरात के सबसे बड़े औद्योगिक-निवेश क्षेत्र धोलेरा को देश के आर्थिक नक्शे से जोड़ने की तैयारी है। परियोजना पूरी होने पर अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक का सफर सिर्फ 34 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसमें अभी सड़क मार्ग से घंटों लगते हैं। कहा, यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर का अहम हिस्सा बनेगा। इससे पूरे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार, निवेश को नई गति मिलेगी। ट्रेन की डिजाइन स्पीड 220 किमी और परिचालन गति 200 किमी घंटा होगी। इस रेल लाइन से 284 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी और पांच लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। परियोजना को पीएम गति शक्ति योजना के तहत तैयार किया गया है ताकि सड़क, रेल, एयरपोर्ट व औद्योगिक ढांचे को साथ जोड़ा जा सके। इससे सालाना 48 लाख लीटर तेल की बचत होगी और दो करोड़ किलो कार्बन डाई आक्साइड का कम उत्सर्जन होगा, जो 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में दो अहम समझौता करेंगे भारत व संयुक्त अरब अमीरात

प्रतीकात्मक

- निर्बाध एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर होंगे समझौते
- पीएम मोदी कल जाएंगे यूएई, फिर नार्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड का दौरा करेंगे

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली: पीएम नरेन्द्र मोदी की शुक्रवार को होने वाली यात्रा भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण होगा। उस दिन भारत और यूएई के बीच एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्र में दो बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। हाल ही में यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से बाहर निकला है और भारत उसके साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौता करने वाला पहला देश होगा। पीएम मोदी चार यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली के दौरे से पहले यूएई जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद से होगी।

भारत और यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही मजबूत साझेदारी है। यूएई भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, जो भारत की कुल जरूरत का करीब 11 प्रतिशत पूरा करता है। यूएई भारत को सबसे ज्यादा रसोई गैस एलपीजी सप्लाई करने वाला देश भी है, जो भारत की लगभग 40 प्रतिशत मांग को पूरा करता है। इसी वर्ष जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तीन अरब डालर का 10 वर्षीय एलएनजी सप्लाई समझौता हुआ था, जिससे भारत यूएई का सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार बन गया है।

सूत्रों का कहना है कि यूएई भारत में तेल भंडारण की संभावनाओं का पता लगाने को इच्छुक है, जो आपातकालीन स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। वैसे 2017-18 में भारत और यूएई के बीच रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण का समझौता हुआ था। अबू धाबी नेशनल आयल कंपनी और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के बीच मंगलौर स्थित भंडारण सुविधा में 58.6 लाख बैरल तेल स्टोर करने का करार हुआ था। हाल ही में दोनों देश इस समझौते को विस्तार देने और अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में वार्ता हुई है।

हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों देश 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। खाड़ी क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए दोनों तरफ की सरकारें रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष रूप से, सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ती दूरी व क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच भारत-यूएई साझेदारी को लेकर नई संभावनाएं के द्वार खुल रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के दो प्रतिद्वंदी देश सउदी अरब और यूएई के बीच तनावपूर्ण संबंधों का असर दक्षिण एशिया पर भी साफ पड़ता दिख रहा है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना 3.5 अरब डालर का कर्ज वापस मांग लिया, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बैंक में तीन अरब डालर जमा कराकर समर्थन जताया (कुल समर्थन आठ अरब डालर तक)। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी हो चुका है। वहीं, भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा निर्माण, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी समन्वय मजबूत हो रहा है।

'प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता'

आइएएनएस के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को नार्वे की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरे से पहले नार्वे के अखबार डेगेंस नारिंग्सलिव में छपे एक लेख में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई है और उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। नार्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोल्हेम ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि उनके जितना लोकप्रिय नेता कोई नहीं।

एअर इंडिया ने हर हफ्ते 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें की बंद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जून से अगस्त 2026 तक के लिए अमेरिका, एशिया, यूरोप के लिए साप्ताहिक उड़ानों की संख्या घटी
- एयरलाइन ने हवाई क्षेत्र की पाबंदियों और जेट ईंधन कीमतों के आसमान पर पहुंचने को बनाया आधार
- दिल्ली-शिकागो उड़ान अस्थायी रूप से निलंबित, दिल्ली-शंघाई फ्लाइट भी अगस्त तक निलंबित की गई

एयर इंडिया। फाइल

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र की पाबंदियों और जेट ईंधन (एटीएफ) कीमतों के आसमान पर पहुंचने को आधार बनाते हुए टाटा समूह की एअर इंडिया ने जून से अगस्त 2026 तक हर हफ्ते अपनी 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद नेटवर्क की स्थिरता बढ़ाना और यात्रियों को आखिरी समय पर परेशानी से बचाना है।

एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने गत दिनों ही एक संदेश में कहा था कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कई उड़ानों को लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ गई है। साथ ही जेट ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि ने कई रूटों को घाटे का सौदा बना दिया है। इस वजह से एयरलाइन को जून-जुलाई में और कटौती करनी पड़ रही है। इस कटौती के बावजूद कंपनी हर हफ्ते 1,200 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती रहेगी।

एअर इंडिया ने दिल्ली-शिकागो उड़ान को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को की साप्ताहिक उड़ानें अगस्त तक 10 से घटाकर सात की जा रही हैं। दिल्ली-टोरंटो की साप्ताहिक उड़ाने 10 से घटाकर जुलाई तक पांच की जाएंगी, जो अगस्त से दैनिक हो जाएंगी। दिल्ली-वैंकूवर की साप्ताहिक उड़ाने सात से घटाकर पांच की गई हैं। मुंबई-न्यूयार्क की उड़ानों को साप्ताहिक तीन से बढ़ाकर सात किया जाएगा, जबकि दिल्ली-न्यूयार्क (जेएफके) सातों दिन बनी रहेगी। दिल्ली-न्यूयार्क और मुंबई-न्यूयार्क (जेएफके) सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी।

यूरोपीय बाजार में कंपनी ने दिल्ली-पेरिस की साप्ताहिक उड़ानें 14 से घटाकर सात करने, दिल्ली-मिलान पांच से चार करने की घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली-कोपेनहेगन, दिल्ली-वियना, दिल्ली-ज्यूरिख और दिल्ली-रोम की साप्ताहिक उड़ानें चार-चार की बजाय तीन-तीन की गई हैं। दिल्ली-मेलबर्न और दिल्ली-सिडनी दोनों को सप्ताह में सात से घटाकर चार कर दिया गया है।

एशियाई बाजार के लिए कंपनी ने दिल्ली-शंघाई अगस्त तक निलंबित कर दी है जबकि दिल्ली-सिंगापुर साप्ताहिक उड़ानें 24 की बजाय 14, मुंबई-सिंगापुर 14 की बजाय साप्ताहिक सात की जाएंगी। चेन्नई-सिंगापुर उड़ान अगस्त तक निलंबित रहेगी। दिल्ली-बैंकाक साप्ताहिक उड़ानें जुलाई से 28 की बजाय 21 और मुंबई-बैंकाक 13 से सात होंगी। दिल्ली-कुआलालंपुर साप्ताहिक उड़ाने 10 से पांच, दिल्ली-हो ची मिन्ह सिटी जुलाई-अगस्त में साप्ताहिक सात से चार और दिल्ली-हनोई साप्ताहिक पांच से चार की जाएंगी। दिल्ली-काठमांडू की साप्ताहिक उड़ानें जून में 42 की बजाय 28 और जुलाई-अगस्त में 21 रहेंगी। दिल्ली-ढाका साप्ताहिक उड़ानें सात से चार, मुंबई-ढाका निलंबित, मुंबई-कोलंबो सात से चार, दिल्ली-कोलंबो 14 से 12 की जाएंगी। दिल्ली-माले उड़ान अगस्त तक निलंबित रहेगी।

बुकिंग कराने वाले यात्रियों के पास पुन: समायोजन और रिफंड का विकल्प

प्रभावित बुकिंग वाले यात्रियों को वैकल्पिक एअर इंडिया उड़ानों पर पुन: समायोजन, मुफ्त तारीख बदलाव या पूरा रिफंड दिया जाएगा। सनद रहे कि यह कदम सिर्फ एअर इंडिया तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया संघर्ष और ईंधन संकट के कारण दुनिया भर की एयरलाइंस उड़ानें घटा रही हैं। लुफ्थांसा ने छह महीनों में करीब 20,000 उड़ानें कम करने का लान किया है। केएलएम, एयर कनाडा, कतार एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद समेत कई बड़ी एयरलाइनें लाखों सीटें घटा रही हैं। ग्लोबल स्तर पर मई में ही 13,000 से अधिक उड़ानें रद की गई हैं और लाखों सीटें प्रभावित हुई हैं।

सुप्रीम आदेश

लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस बिना सार्वजनिक वाहनों को ना मिले परमिट

केंद्र के वीएलटीडी की अनिवार्यता पर भी 99 प्रतिशत वाहनों में नहीं लगे डिवाइस - बिना स्पीड गवर्नर दौड़ रहे 95 प्रतिशत वाहन, कागजों में सिमटा सड़क सुरक्षा बोर्ड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ाते रहे और देशभर में वाहन नियमों को रौंदते हुए सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। यात्री सुरक्षा से जुड़े कई नियम-कानूनों की अवहेलना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,भारत में लेन में चलने के नियमों का पालन नहीं होने से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक सेवा के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन के मामले में अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र और धारा 66 के तहत परमिट तभी जारी किया जाएं, जब वाहन पोर्टल पर वीएलटीडी की स्थापना और कार्यशीलता का सत्यापन हो चुका हो। कहा, 31 दिसंबर, 2018 तक पंजीकृत पुराने वाहनों में भी वीएलटीडी और पैनिक बटन की रेट्रोफिटिंग सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जस्टिस जेबी पार्डीवाला व केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने बहस की। न्यायालय द्वारा नियुक्त एमीकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने भी पक्ष रखा। तीन सितंबर को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में तथ्य रखे गए कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125एच के अंतर्गत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना वर्षों पहले अनिवार्य किया गया था, परंतु 99 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक वाहन इस नियम का पालन किए बिना चल रहे हैं। एक जनवरी, 2026 से वाहन पोर्टल पर वीएलटीडी की अनिवार्य जांच भी लागू की गई। इसके बावजूद स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें नए व पुराने सभी प्रकार के सार्वजनिक सेवा वाहनों में समयबद्ध एवं सत्यापन तरीके से वीएलटीडी व पैनिक बटन की स्थापना सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार वाहन निर्माताओं को विनिर्माण या वितरण के समय ही वीएलटीडी लगाने के बाध्यकारी निर्देश जारी करे।

95 प्रतिशत वाहनों में स्पीड गवर्नर न होने का मुद्दा भी आया। एक अक्टूबर, 2015 के बाद निर्मित सभी परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) लगाना अनिवार्य है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार सभी वाहन निर्माताओं को निर्माण के समय ही एसएलडी लगाने के अनिवार्य एवं बाध्यकारी निर्देश दे और पर्याप्त दंड के प्रविधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड गठन के लिए अंतिम अवसर

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215बी के अंतर्गत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन अनिवार्य है। पिछले छह वर्षों से यह बोर्ड केवल कागजों पर ही है। न अध्यक्ष, न सदस्य, न कार्यालय, न वेबसाइट। 14 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने नौ महीने का समय मांगा था। न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मात्र छह महीने का समय दिया और कहा था कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा, परंतु छह महीने का समय भी बीत गया। अक्टूबर, 2025 में बोर्ड के नियम तो अधिसूचित हो गए, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अटकी है। न्यायालय ने इसे गंभीर चूक बताते हुए केंद्र को अंतिम अवसर के रूप में केवल तीन महीने का समय दिया है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

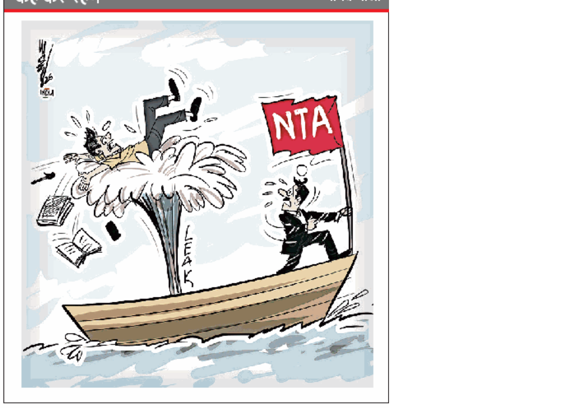

25 बागी अन्नाद्रमुक के विधायकों ने जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया। एक विधायक वाली भाजपा और राजग के एक अन्य घटक पीएमके (4) ने तटस्थ रुख अपनाया।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार, 14 मई, 2026

107 सीटें पाने वाले विजय को विश्वास मत में 144 विधायकों का समर्थन

तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस व वाम दलों के साथ अन्नाद्रमुक के बागियों का समर्थन मिला

22 विधायकों ने विरोध किया, द्रमुक का वाकआउट, पीएमके और भाजपा ने तटस्थ रुख अपनाया

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु में चार दिन पुरानी टीवीके सरकार ने बुधवार को विश्वास मत हासिल कर एक बड़ी राजनीतिक बाधा पार कर ली। विधानसभा चुनाव में 107 सीटें हासिल करने वाली टीवीके को विधानसभा में 144 विधायकों का समर्थन मिला। 22 विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट डाला। मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने वाकआउट किया और अन्नाद्रमुक के 25 बागी विधायकों ने जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया। एक विधायक वाली भाजपा और राजग के एक अन्य घटक पीएमके (4) ने तटस्थ रुख अपनाया। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी।

चेन्नई में बुधवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। आइएएनएस

सरकार की स्थिरता पर उठ रहे सवालों के बीच इस जीत ने पहली बार बनी टीवीके सरकार को कार्यभार संभालने और शासन के संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास दिया है।

बहुमत साबित करने की कवायद में टीवीके सरकार को कांग्रेस, वीसीके, वामपंथी दलों, एएमएमके और अन्नाद्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिला, जिसका नेतृत्व एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक महासचिव के पलानीस्वामी ने सरकार का समर्थन करने वाले सभी बागी नेताओं को निलंबित कर दिया है।

उदयनिधि ने कहा, टीवीके को बहुमत का समर्थन नहीं

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को कहा कि टीवीके सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। अन्नाद्रमुक के विधायकों के समर्थन से सरकार चलाने की आलोचना की, जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उदयनिधि ने कहा कि लगभग 65% मतदाताओं ने टीवीके को अस्वीकार कर दिया है। डीएमडीके महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने सरकार पर हमला बोला और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों को राज्य के लिए शर्मनाक बताया।

मुख्यमंत्री विजय के ओएसडी के पद से ज्योतिषी की नियुक्ति रद

चेन्नई, प्रेट्र: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के ओएसडी के रूप में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित वेट्ट्रीवेल की नियुक्ति का आदेश रद कर दिया। सरकारी आदेश को वापस लेने का यह निर्णय नियुक्ति के 24 घंटे से भी कम समय में लिया गया है। यह निर्णय टीवीके के राजनीतिक विरोधियों और सहयोगियों दोनों की ओर से तीव्र आलोचना के बाद आया है।

इस नियुक्ति को लेकर आज सुबह राज्य विधानसभा में तीखी बहस छिड़ गई। डीएमडीके की महासचिव प्रेमलता विजयकांत समेत विपक्षी नेताओं ने सदन में इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए एक ज्योतिषी को इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने पर सवाल उठाए। विभिन्न पक्षों से बढ़ते दबाव और विरोध का सामना करते हुए विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने तुरंत इस नियुक्ति को रद कर दिया। ज्योतिषी के रूप में ख्यातिप्राप्त वेट्रिवेल को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार ने बाद में इस निर्णय को वापस ले लिया। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि सरकारी आदेश तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है।

चुनावी हार के बाद अब तृणमूल के कई विधायकों के भी बागी तेवर

ममता बनर्जी फाइल

- पार्टी नेतृत्व का प्रत्येक निर्देश मानने के बजाय क्षेत्र की परिस्थितियों के मुताबिक काम करने का लिया निर्णय
- ममता ने आगामी शुक्रवार को जिलों के पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक, कई विधायकों को आमंत्रित नहीं किया

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता

ममता सरकार के 15 वर्षों के शासन के अंत के बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत के स्वर दिन-ब-दिन तेज होते जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता व पार्षदों के बाद अब कई विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल के कुछ विधायकों ने कोलकाता में आपस में बैठक कर तय किया है कि वे अब पार्टी नेतृत्व की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे बल्कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों के मुताबिक काम करेंगे।

बताया जा रहा है कि इनमें पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं, जो हार के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा अपने निवास स्थल पर पार्टी विधायकों के साथ की गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच ममता ने आगामी शुक्रवार को सभी जिलों के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उसमें उन्होंने वहां से निर्वाचित कई विधायकों को आमंत्रित नहीं किया है।

मालूम हो कि तृणमूल की हार के बाद पार्टी प्रवक्ता ऋजु दत्ता ने आरोप लगाया था कि पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के तृणमूल नेताओं ने आम लोगों से जमकर वसूली की। घर का नक्शा पास कराने से लेकर कमोड लगाने तक के लिए पैसे देने पड़ते थे। ऋजु दत्ता को ऐसी बयानबाजी के लिए पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। वहीं, अभिनेत्री व तृणमूल पार्षद अनन्या बनर्जी ने कहा था कि जनता परिवर्तन चाहती थी इसलिए पार्टी का ऐसा हश्र हुआ। उससे पहले पार्षद सुब्रत बंद्योपाध्याय ने पार्टी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह चुनाव के नतीजे आने के बाद डरकर भागे पार्टी कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास करने के बजाय घर पर बैठे हुए हैं।

कई दिनों के सस्पेंस के बाद कांग्रेस आज केरलम के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी

- सतीशन, वेणुगोपाल और चेन्निथला पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल
- यूडीएफ सतीशन के पक्ष में, जिन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : कई दिनों के सस्पेंस और लंबी चर्चाओं के बाद कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह गुरुवार को केरलम में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच हुई 40 मिनट की बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाई कमान ने सभी चर्चाएं पूरी कर ली हैं। केरलम के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला गुरुवार को हो जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) ने केरलम में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया था।

इस पद की दौड़ में एआइसीसी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, केरलम विधानसभा के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन और पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं। कांग्रेस के सहयोगी यूडीएफ सतीशन के पक्ष में है, जिन्हें जनता और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का भी जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। हालांकि, एआइसीसी के महासचिव वेणुगोपाल के भी उम्मीदवारी पेश करने के बाद पार्टी हाई कमान के लिए चुनाव आसान नहीं रह गया है। इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की योजना 'राज्य को पांच साल में पांच मुख्यमंत्री देने की है।' उन्होंने एएनआइ से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वी डी. सतीशन का नाम आगे बढ़ा रही हैं, जबकि राहुल गांधी के. सी. वेणुगोपाल का नाम ले रहे हैं।

वी.डी. सतीशन के.सी. वेणुगोपाल रमेश चेन्निथला। फाइल

वायनाड में राहुल और प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगे : वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य सरकार के गठन में कांग्रेस की देरी पर स्थानीय लोगों ने निराशा व्यक्त की है। एक पोस्टर में लिखा था, राहुल और प्रियंका, वायनाड को भूल जाइए। आप यहां से दोबारा नहीं जीत पाएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, राहुल, केसी भले ही आपका सामान ढोने वाला हो, लेकिन केरलम के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। वहीं, एक पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि वायनाड अगला अमेठी होगा।

पुडुचेरी में पांचवीं बार सीएम बने रंगासामी

- सीएम रंगासामी बोले-पुडुचेरी का विकास सिंगापुर की तरह करेंगे
- अन्य दो कैबिनेट सदस्यों ने भी ली शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई

पुडुचेरी, एएनआइ : अनुभवी नेता और एआइएनआरसी के संस्थापक एन. रंगासामी ने बुधवार को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार शपथ ली और कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और नई गठित राजग सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा, "हम अपने पुडुचेरी का विकास सिंगापुर की तरह करने जा रहे हैं।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रंगासामी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट किया,'रंगासामी ने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और केंद्र शासित प्रदेश की विकास यात्रा को मजबूत किया है।'

एआइएनआरसी के संस्थापक रंगासामी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। अन्य दो कैबिनेट सदस्यों क्षेत्रीय पार्टी के मल्लादी कृष्ण राव और भाजपा के ए. नामसिवायन ने भी एआइएनआरसी के नेतृत्व वाले राजग सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। रंगासामी ने भगवान के नाम पर शपथ ली। उन्होंने समारोह के बाद पत्रकारों से कहा," यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि हम लोगों की भलाई के लिए सभी आवश्यक योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करें। हम निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को उत्कृष्टता के साथ निभाएंगे। हम लोगों की सेवा में हैं। सभी योजनाएं जारी रहेंगी, और हम नई योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। हम पुडुचेरी का बहुत अच्छा विकास करेंगे।" एआइएनआरसी के नेता मल्लादी कृष्ण राव ने बताया, "मैं चौथी बार कार्यभार संभाल रहा हूं। विभाग इस सप्ताह या अगले सप्ताह दिए जाएंगे। और विधायक मंत्री बनेंगे या नहीं, यह मुख्यमंत्री का विषय है।" राजग ने पुडुचेरी में सत्ता बनाए रखी। एआइएनआरसी ने 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में 12 सीटें जीतीं और भाजपा ने चार सीटें जीतीं। अन्नाद्रमुक ने एक सीट जीती। द्रमुक ने पांच सीटें जीतीं और कांग्रेस को एक सीट मिली।

पुडुचेरी में बुधवार को राजग नेता एन. रंगासामी (दाएं) को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन। प्रेट्र

बिहार : विधायक अख्तरुल ने वंदे मातरम् की अनिवार्यता पर उठाया सवाल

जासं, किशनगंज : बिहार सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रमों और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य किए जाने पर एआइएमआइएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। किशनगंज स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी कानून या आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का ध्यान रखना चाहिए। 'वंदे मातरम्' का अनिवार्य गायन उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है और उनकी पार्टी इसका सड़क से सदन तक विरोध करेगी। अख्तरुल ने इसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया। कहा कि सरकार को इस फैसले पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसे लेकर वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व संबंधित मंत्रालय को आवेदन देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने और सोना नहीं खरीदने की अपील को लेकर केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। कहा कि एक तरफ वाहनों को लाइसेंस दे रहे हैं व दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ। साथ ही बिहार सरकार पर उर्दू भाषा की अनदेखी का आरोप लगाया।

पूछताछ के लिए असम पुलिस के सामने पेश हुए पवन खेड़ा

गुवाहाटी, प्रेट्र : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ के लिए असम पुलिस अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। अपराध शाखा कार्यालय में प्रवेश से पहले उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे पुलिस ने तलब किया था। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहां हूं।" खेड़ा ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद वह प्रेस से विस्तार से बात करेंगे। वहीं, हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, खेड़ा क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए और पुलिस उनसे पूछताछ जरूर करेगी। हमें केंद्र सरकार से लिखित में सूचना मिल चुकी है कि खेड़ा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी थे।"

रोहित पवार ने कहा, प्रफुल पटेल और तटकरे अगला चुनाव भाजपा से लड़ेंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

- रोहित ने कहा, राकांपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के असंतुष्ट विधायक भाजपा में जाने को तैयार
- सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने रोहित पवार के गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज किया

राकांपा (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता और विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत 22 विधायक आगामी चुनाव भाजपा के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे। रोहित पवार के इस सनसनीखेज बयान ने अजीत पवार के निधन के बाद से राकांपा के भीतर सुलग रही वर्चस्व की लड़ाई और कलह को पूरी तरह से सतह पर ला दिया है।

प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को पार्टी में किनारे किए जाने की खबरों ने पहले ही असंतोष की आग को हवा दे रखी थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फेरबदल के दौरान इन वरिष्ठ नेताओं के पदों का उल्लेख न किए जाने को बाद में सुनेत्रा पवार ने लिपिकीय त्रुटि बता कर स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन उनके इसी बयान ने शरद पवार की पार्टी को तंज कसने का मौका उपलब्ध करा दिया है।

बुधवार को पुणे में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान रोहित पवार ने सीधे तौर पर प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि इन नेताओं का भविष्य पहले ही तय हो चुका है। कुल 22 विधायक अजीत पवार गुट से और शिवसेना (शिंदे गुट) के भी कुछ असंतुष्ट विधायक भाजपा के पाले में जाने को तैयार बैठे हैं। केवल पाला बदलने की औपचारिक प्रक्रिया को तेज किया गया है। यह पूरी तैयारी आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर की गई है।

प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे। फाइल

लीना गंगोपाध्याय का बंगाल महिला आयोग के प्रमुख पद से इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जानी-मानी लेखिका और प्रोड्यूसर लीना गंगोपाध्याय ने राज्य महिला आयोग (डब्ल्यूबीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल जुलाई तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले पद छोड़ने का निर्णय लिया। लीना गांगुली को जुलाई 2023 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और वे तृणमूल कांग्रेस के करीबी मानी जाती थीं। हालांकि, मार्च में अभिनेता राहुल बनर्जी की मौत के बाद उनके खिलाफ विवाद खड़ा हो गया था।

मालूम हो कि ओडिशा में शूटिंग के दौरान राहुल की समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। यह सीरियल लीना की प्रोडक्शन कंपनी बना रही थी। शुरुआत में लीना ने दावा किया था कि शूटिंग के दौरान पानी का कोई सीन नहीं था, लेकिन बाद में सामने आया कि घटना शूटिंग के दौरान ही हुई। राहुल की पत्नी प्रियंका सरकार ने लीना और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, पावस सत्र के पहले हो सकता है विस्तार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

- मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए होगा विस्तार

लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की टीम यानी मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत मिले हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की समय-सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन यह तय है कि जून या मध्य प्रदेश विधानसभा के पावस (मानसून) सत्र से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव व विस्तार का काम पूरा कर लिया जाएगा। मोहन मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री हो सकते हैं। अभी चार पद रिक्त हैं। बता दें कि लंबे समय से विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं।

यह भी बताया जा रहा है कि संतुलन बनाने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए विस्तार किया जाएगा। माना जा रहा है कि विंध्य, महाकोशल और ग्वालियर-चंबल जैसे क्षेत्रों को नया प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

डा. मोहन यादव। फाइल

विलंब से हो रहा मंत्रिमंडल विस्तार : मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में एक साथ वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफी पहले कैबिनेट विस्तार हो चुका है। छग की विष्णु देव साय सरकार ने प्रशासनिक कसावट और क्षेत्रीय समीकरणों को समय रहते दुरुस्त कर लिया है। वहां अगस्त 2025 में ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुकाबले वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और कई बार के विधायकों की संख्या बहुत अधिक है। महाकोशल, विंध्य, और ग्वालियर-चंबल जैसे अंचलों से कई दिग्गज कतार में हैं, जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व को समीकरण साधने में लंबा समय लगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट के पुनर्गठन का काम तो आरंभ कर दिया गया है, जून अंतिम या जुलाई के पहले पखवाड़े तक इसे पूरा कर दिया जाएगा।

13 मई को मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के ढाई साल पूरे हो गए हैं। पार्टी ने अब मिशन 28 की तैयारी भी आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता 17 मई को मंत्रियों के साथ अलग-अलग बातचीत भी करेंगे। इस आधार पर किन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, उन्हें चिह्नित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ विवादों में रहने वाले वरिष्ठ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है।

व्यक्त की आस्था

सीएम बनने के बाद पहली बार सदन में प्रवेश से पहले अपने कक्ष में की पूजा-अर्चना, भवानीपुर में उन्होंने ममता को मुख्यमंत्री रहते 15 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया

सुवेंदु ने सीढ़ी पर मत्था टेक विधानसभा में रखा कदम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को भावुक अंदाज में विधानसभा में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे सुवेंदु ने सदन की सीढ़ियों पर मत्था टेककर लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया। इसके बाद विधानसभा भवन में प्रवेश किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी संसद पहुंचे थे तो संसद भवन की सीढ़ी पर मत्था टेकने के बाद ही अंदर गए थे। इससे पहले सुवेंदु ने विधानसभा परिसर में डा. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने कक्ष में विधिवत शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की, फिर वह सदन में पहुंचे और सदस्यता की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचने पर सुवेंदु को गार्ड आफ आनर दिया गया।

भवानीपुर सीट को चुना : राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के पहले दिन मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कोलकाता की भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर तापस राय ने सुवेंदु को शपथ दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह नंदीग्राम सीट छोड़ रहे हैं लेकिन वे वहां लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। भवानीपुर में उन्होंने ममता को मुख्यमंत्री रहते 15 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया। चुनाव जीतने के बाद सुवेंदु ने नंदीग्राम में लोगों को धन्यवाद सभा में संकेत दे दिए थे कि वह यह सीट छोड़ेंगे क्योंकि नियम के अनुसार वह किसी एक जगह से ही विधायक रह सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नंदीग्राम के लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वह उनके साथ नहीं हैं।

कोलकाता में बुधवार को विधानसभा में प्रवेश करने से पूर्व सीढ़ियों पर मत्था टेकते बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी। प्रेट्र

हुमायूं कबीर ने की सुवेंदु की तारीफ : आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की तारीफ की है। कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ममता की 'भ्रष्ट सरकार' को हटाना था, जिसे राज्य की जनता ने पूरा कर दिया। उन्होंने इसे बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करार दिया। कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में अनुभव रखने वाले अधिकारी प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करेंगे।

हरियाणा में सोनीपत, रेवाड़ी, धारूहेड़ा सहित छह शहरी निकायों में खिले फूल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

- सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगमों समेत सात निकायों में से छह में भाजपा ने लहराया जीत का परचम

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के करीब डेढ़ साल बाद हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े गए सात शहरी निकायों के चुनाव में छह में भाजपा उम्मीदवार जीते हैं, जबकि हिसार जिले की उकलाना नगरपालिका में कांग्रेस व इनेलो समर्थित 22 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी चुनाव जीतने में सफल रही हैं।

पंचकूला नगर निगम में सोनीपत में राजीव जैन, भाजपा के शाम लाल बंसल, अंबाला में अक्षिता सैनी मेयर का चुनाव जीते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में विनिता पिप्पल, धारूहेड़ा नगर पालिका में सत्य नारायण उर्फ अजय जांगड़ा और सांपला नगर पालिका में भाजपा के ही प्रवीण अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

शहरी निकाय चुनाव में सबसे बड़ी जीत पंचकूला नगर निगम में भाजपा के शामलाल बंसल की हुई है, जिन्होंने कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 36,252 मतों के भारी अंतर से पराजित कर मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया। सोनीपत नगर निगम के चुनाव में भाजपा के राजीव जैन की दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई है। तीसरे नगर निगम अंबाला में भाजपा की अक्षिता सैनी ने कांग्रेस की कुलविंदर कौर सैनी को 21,358 मतों के अंतर से पराजित कर मेयर का चुनाव जीता। अब सभी 11 नगर निगमों में भाजपा के मेयर हो गए हैं।

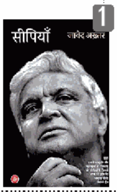

1 सीपियां
लेखक: जावेद अख्तर
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन
तुलसी, कबीर जैसे विद्वान कवियों ने अपने दोहों के माध्यम से ज्ञान और शिक्षाओं को सामने रखा था। जावेद अख्तर ने उनके कुछ प्रमुख दोहों को नए सिरे से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है।

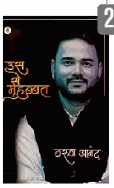

2 उस से मुहब्बत
लेखक: वरुण आनंद
प्रकाशक: अनबाउंड स्क्रिप्ट
इस किताब में महबूब से इजहार है, शिकायतें हैं और जुदाई के लम्हें दर्ज हैं। यहां मोहब्बत का हर रंग देखने को मिलेगा तो कहीं तंज इसे और दिलकश बनाता है। परंपरा व आधुनिकता का संगम है इसमें।

3 चाय-सी मोहब्बत
लेखक: परितोष त्रिपाठी
प्रकाशक: हिंद युग्म
चाय और मोहब्बत दोनों में गर्माहट होती है, जब ये मिल जाएं तो तन-मन नई ऊर्जा और उत्साह से भर उठता है। भावनाओं की यही गर्माहट दिखती है परितोष के इस कविता संग्रह में।

4 इश्क बगावत
लेखक: रितेश रजवाड़ा
प्रकाशक: हिंद युग्म
यह एक युवा लड़के की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो मोहब्बत और क्रांति की जुड़ती हुई हथेलियों के बीचोंबीच से गुजरती है। यह आपको भागमभाग भरी जिंदगी से खींचकर दोबारा कालेज तक पहुंचा देती है।

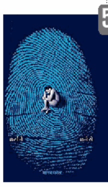

5 कर्ता ने कर्म से
लेखक: मानव कौल
प्रकाशक: हिंद युग्म
यह पुस्तक अकेलेपन, आधुनिक जीवन और अस्तित्व के दर्शन को सरल, लेकिन गहरे शब्दों में बयां करती है। इसमें आत्मचिंतन और जीवन के विषयों को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

नीट-यूजी को फूलप्रूफ बनाने के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव की फिर तेज हुई पहल

हाईपावर कमेटी ने भी परीक्षा को सीबीटी या हाइब्रिड मोड में कराने जैसे दिए थे कई सुझाव

स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्रालयों में फिर शुरू हुई चर्चा, दोबारा परीक्षा को फुलप्रूफ बनाने पर विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेपर लीक होने के बाद नीट-यूजी के परीक्षा पैटर्न पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसे फूलप्रूफ बनाना है तो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करना ही होगा। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। 2024 में जब नीट-यूजी का पेपर लीक हुआ था, तो उस समय परीक्षा में सुधार के लिए जो हाईपावर कमेटी बनाई गई थी, उसने भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव की सिफारिश करते हुए इसे कंप्यूटर के जरिये यानी सीबीटी मोड में या फिर हाइब्रिड मोड में कराने का सुझाव दिया था।

इन सुझावों को दिए हुए डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस परीक्षा का पैटर्न जस का तस यानी जैसे पेन-पेपर मोड में होता था, वैसे ही रखा गया है। इस बीच परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच कई दौर की बैठक भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर सहमत नहीं है। वैसे भी मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी का आयोजन पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय का है। इसे सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला एनटीए आयोजित कराता है। यह भी इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की सभी बड़ी परीक्षाओं के आयोजन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन कर रखा है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रमुखों ने इंटरनेट मीडिया के जरिये सुझाव दिए हैं।

केंद्र सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो पेपर लीक के बाद हाईपावर कमेटी के सुझावों पर अमल नहीं होने को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे है, ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर फिर से विमर्श किया है।

सूत्रों का दावा है कि चर्चा के दौरान दोबारा होने वाली नीट-यूजी परीक्षा को कैसे फूलप्रूफ बनाया जाए, इस पर विमर्श हुआ है। इसमें परीक्षा को हाइब्रिड मोड में कराने के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हुई है। इसमें प्रश्नपत्रों को छपवाने व सुरक्षित परिवहन कराने के स्थान पर इसे जेईई-मेन की तरह परीक्षा से आधे घंटे पहले आनलाइन परीक्षा केंद्रों को भेजने और पासवर्ड से खोलने जैसी व्यवस्था है। बाद में इसे परीक्षा केंद्रों पर ही एक प्रिंटर के जरिये छापकर तुरंत छात्रों में वितरण करने जैसे इंतजाम करने का सुझाव है।

► सुझावों को दिए हुए डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस परीक्षा का पैटर्न जस का तस यानी पेन-पेपर से

<< पेपर लीक के कारण नीट (यूजी) -2026 रद होने से आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। एएनआइ

नीट पेपर लीक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

► कहा, उच्चस्तरीय समिति की कड़ी निगरानी में कराई जाए दोबारा परीक्षा

नीट-यूजी पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर नीट-यूजी में प्रणालीगत विफलता का आरोप लगाते हुए परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की मांग की है। साथ ही मांग है कि नीट-यूजी का दोबारा आयोजन उच्चस्तरीय समिति की कड़ी निगरानी में कराया जाए और समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।

याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग है कि वह नीट आयोजित कराने के लिए या तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को और अधिक मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त निकाय के रूप में प्रतिस्थापित करे या उसका पुनर्गठन करे। कोर्ट नीट-यूजी का दोबारा आयोजन कराने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश दे जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश हों और उसमें साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ व फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञ भी हों। यह समिति परीक्षा की निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि दोबारा पेपर लीक न हो। यह भी मांग की गई है कि सीबीआइ को चार सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया जाए।

नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की हो जेपीसी जांच : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने पेपर लीक के कारण नीट-यूजी रद होने के मामले में सरकार पर हमला तेज करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही एनटीए के क्रिया-कलापों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को सख्त सजा दी जाए। एनटीए को विफल एजेंसी बताते हुए पार्टी ने नए सिरे से होने वाली परीक्षा किसी अन्य विश्वसनीय सरकारी संस्था के माध्यम से कराने की भी मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी का संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व नीट पेपर लीक के कारण छात्रों की बढ़ी परेशानी को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दाग रहा है। पार्टी की ओर से बुधवार को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान चिब एवं छात्र इकाई एनएसयूआइ के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रेस कान्फ्रेंस में पेपर लीक को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जेपीसी गठन की मांग की।

चिब ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं और 48 बार परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। 2017 में एनटीए गठन के बाद से पेपर लीक लगातार जारी है। इससे छात्रों का पूरे सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है। सवाल उठाया कि एनटीए का आडिट कौन करता है और निजी वेंडरों को परीक्षाएं आयोजित करने का काम देने का आधार क्या है? 2024 में जिन एनटीए महानिदेशक के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ था, उन्हें छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया।

विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सिर्फ परीक्षा रद करना समस्या का समाधान नहीं है। पेपर लीक के बाद एनटीए माफी मांगकर खानापूर्ति कर देता है और कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। लगातार ऐसी घटनाओं से छात्रों में भारी हताशा है।

पेपर लीक रोकने के सख्त कानून के बाद भी माफिया के हौसले बुलंद

अरविंद पांडेय, जागरण

► 2024 में नीट-यूजी पेपर लीक के बाद उसी वर्ष 21 जून को आनन-फानन में किया था अधिसूचित

नई दिल्ली : परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार भले ही 2024 में एक सख्त कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बाद भी गहरी जड़ें जमाकर बैठे परीक्षा माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वे पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे तो परीक्षा माफिया ने सरकार के इस कानून को तभी चुनौती दे दी थी, जब संसद से फरवरी में पारित होने के बाद मई, 2024 में आयोजित नीट-यूजी का पेपर लीक कर दिया था। तब नकल रोकने का यह कानून अधिसूचित नहीं हुआ था। हालांकि पेपर लीक के बीच केंद्र सरकार ने 21 जून, 2024 को इसे आनन-फानन में अधिसूचित कर दिया था।

एनटीए से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस कानून के प्रभावी होने के बाद 2024 में ही बिहार और गुजरात में सीबीआइ ने नए कानून के तहत मामला दर्ज किया था। 2026 में जब एक बार फिर नीट-यूजी का पेपर लीक हुआ है, तब भी सीबीआइ ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस कानून के दायरे में एनटीए, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग भर्ती और केंद्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं व भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया था। इस कानून को लाने के समय केंद्र ने दावा किया था कि इससे पेपर लीक व परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। साथ ही राज्यों को भी इसी पैटर्न पर कानून बनाने का सुझाव दिया था।

क्या कहता है नया कानून : नए कानून के तहत पेपर लीक सहित परीक्षाओं की गड़बड़ियों से जुड़ा प्रत्येक मामला गैर-जमानती है। कोई व्यक्ति यदि अकेले पेपर लीक व गड़बड़ियों में शामिल पाया जाता है तो उसे पांच वर्ष की जेल व 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, कोई गिरोह मिलकर इस काम को अंजाम देता है तो इसे संगठित अपराध मानते हुए 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम एक करोड़ जुर्माने का प्रविधान है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी के इसमें शामिल पाए जाने पर एक करोड़ का जुर्माना व अगले चार वर्षों तक ब्लैकलिस्ट करने का प्रविधान है। साथ ही परीक्षा का खर्च भी उससे वसूला जाएगा। इन नए नियमों के तहत जुर्माना नहीं चुकाने पर अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कराने का अधिकार दिया गया है।

नीट का लीक पेपर 10 राज्यों में बेचा गया

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में सामने आया है कि नीट का लीक पेपर 10 राज्यों में बेचा गया था। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, केरलम, उत्तराखंड सहित अन्य राज्य शामिल हैं। एसओजी ने सभी राज्यों के नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताएं हैं। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने स्वीकार किया कि यह पेपर माफियाओं तक परीक्षा से दो से तीन सप्ताह पहले ही पहुंच गया था। सीकर में ई-मित्र संचालकों तक पेपर पहुंच गया था।

कोचिंग संचालकों और एक करियर काउंसलर की भी इसमें भूमिका सामने आई है । एसओजी ने जयपुर, सीकर व गुरुग्राम सहित अन्य शहरों से जिन आरोपितों को पकड़ा है, उनमें जयपुर जिले के जमवारामगढ़ निवासी दो भाई दिनेश बिंवाल और मांगीलाल भाजपा से जुड़े हैं।

सीबीआइ को सौंपी गई एसओजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीट का पेपर नासिक की प्रींटिंग प्रेस से लीक हुआ था।

असम विधानसभा में यूसीसी का मसौदा 26 मई को होगा पेश

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मसौदा 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहली मंत्रिमंडल बैठक में बुधवार को राज्य में यूसीसी लागू करने को मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूसीसी लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आदिवासी आबादी को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी मुख्य रूप से चार विषयों को कवर करेगी, विवाह की न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, माता-पिता की संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूसीसी लागू है, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया है। हमने आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है।

उन्होंने कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित होगा। यह अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों के लिए कानूनों का एक समान सेट तैयार करेगा। साथ ही समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रमुख कानूनी शब्दों को परिभाषित करने और विभिन्न रीति-रिवाजों और आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता देने के लिए विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक सामान्य कानूनी ढांचे से प्रतिस्थापित करेगा।

► पहली मंत्रिमंडल बैठक में यूसीसी लागू करने को दी गई मंजूरी

► सीएम ने कहा, आदिवासी आबादी को इससे बाहर रखा जाएगा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा।

महिला समेत महाराष्ट्र व राजस्थान में कई हिरासत में

प्रथम पृष्ठ से आगे

शुभम से पूछताछ के बाद सीबीआइ ने महाराष्ट्र में अहिल्यानगर से तीन व्यक्तियों और पुणे से एक महिला को हिरासत में लिया है। राजस्थान एसओजी ने भी सीकर, जयपुर ग्रामीण (जमवा रामगढ़ सहित), अलवर और आसपास के इलाकों से कई लोगों को हिरासत में लिया है।

जयपुर संवाददाता के अनुसार, राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया है कि नीट का लीक पेपर 10 राज्यों में बेचा गया था। एसओजी के आइजी अजयपाल लांबा ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक का मूल केंद्र नहीं है। नीट का पेपर राजस्थान पहुंचने से पहले ही लीक हो चुका था। करीब 150 छात्रों के पास पेपर पहुंचा था। जांच और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में सामने आया कि दो मई को सीकर के दो कोचिंग संचालकों एवं एक करियर काउंसलर राकेश मंडावरिया तक पेपर पहुंचा।

मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

जागरण टीम, लखनऊ

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार सुबह ड्राइवर ने उनको किचन में बेसुध देखकर उनकी पत्नी अपर्णा के भाई अमन बिष्ट को सूचना दी। सिविल अस्पताल से बुलाए गए डाक्टर ने देखा तो प्रतीक बेसुध थे। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया। आइसीयू में ईसीजी और अन्य जांच के बाद डाक्टरों ने सुबह छह बजे मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों का कहना था कि वह मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से होने से मौत बताई गई। 38 वर्षीय प्रतीक के शरीर पर छह और सिर पर पांच चोटों के निशान भी पाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव सुबह पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे। अंतिम संस्कार 14 मई को बैकुंठधाम में सुबह 11 बजे होगा।

प्रतीक यादव की सेहत खराब हुई उस समय उनकी पत्नी अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में सोमनाथ गई थीं, घर पर केवल नौकर ही थे। अपर्णा के भाई अमन और ड्राइवर अनुभव सुबह जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर अनिल ने निदेशक डा. जीपी गुप्ता से बात कर डा. प्रिंस को प्रतीक के घर भेजा।

डाक्टर ने प्रतीक को देखकर सिविल अस्पताल ले चलने को कहा था। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए पोस्टमार्टम में फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने के कारण कार्डियक अरेस्ट होने को मौत का कारण बताया गया है।

पिछले कुछ महीने से प्रतीक फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। डाक्टरों का मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण वह रात में किचन में गिरे होंगे और इसी वजह से चोटें आईं। अपर्णा के इंतजार में पोस्टमार्टम के बाद भी प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम हाउस में ही रोके रखा गया।

अपर्णा दोपहर में घर पहुंचीं तो उनके पिता अरविंद बिष्ट और भाई अमन बिष्ट शव लेकर घर आए। इससे पहले अपर्णा की मां अंबी बिष्ट और उनके भाई के साथ दोनों बेटियां घर पहुंची थीं। चाचा शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी सरला, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और आदित्य यादव सहित पूरा परिवार एकत्र हो गया।

अखिलेश बोले, मैंने कहा था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो : प्रतीक के आवास पर पहुंचे अखिलेश ने कहा- "प्रतीक आज हमारे बीच नहीं है, जो बहुत दुःखद है। वह नौजवान था बचपन से ही आगे बढ़ना चाहता था। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी-कभी कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे आदमी टूट जाता है। परिवार के लोग जो कहेंगे हम वही मानेंगे।"

इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय थे : इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले प्रतीक ने तीन अप्रैल को ईए 300 विमान के काकपिट में बैठकर फोटो खींचने के बाद अंतिम पोस्ट किया था। लिखा था- "इंजन दहाड़ रहा है आसमान खुला हुआ है, मैंने कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है।

► पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की कही गई बात, घर पर मौजूद नहीं थीं पत्नी अपर्णा

लखनऊ में बुधवार को प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर देखकर रोती बेटी को संभालतीं अपर्णा यादव। जागरण >>

हक की बात

पंजाब ने यमुना बेसिन से जुड़ा राज्य होने के कारण मांगी हिस्सेदारी, दिल्ली ने आबादी के अनुसार कम पानी की उपलब्धता का उठाया मुद्दा

समझौते की समीक्षा से पूर्व पंजाब ने यमुना जल में मांगा हिस्सा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर 1994 में हुए अंतरराज्यीय समझौते की पुनर्समीक्षा से पहले पंजाब ने अपने लिए भी हिस्सेदारी का दावा पेश किया है। यह मुद्दा पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में उठा। पंजाब ने तर्क दिया कि जैसे हरियाणा संयुक्त पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य होने के आधार पर रावी-ब्यास के पानी में हिस्सा लेता है, उसी तरह पंजाब को भी यमुना जल बंटवारे में अधिकार मिलना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने बैठक में कहा कि 1994 के समझौते में उसे शामिल नहीं किया गया था, जबकि वह भी यमुना बेसिन से जुड़ा राज्य है। पंजाब का दावा है कि 1954 में अविभाजित पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच हुए समझौते के तहत पंजाब को यमुना के पानी का दो-तिहाई हिस्सा मिलने का अधिकार था। इसके अलावा 1972 के सिंचाई आयोग ने भी पंजाब को यमुना बेसिन का हिस्सा माना था।

दिल्ली ने कहा- मौजूदा कोटा किसी कीमत पर कम न हो : बैठक में दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि यमुना जल बंटवारे की नई व्यवस्था बनाई जाती है तो राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा हिस्से में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजधानी पहले ही तय हिस्से से कम पानी प्राप्त कर रही है। 1994 के समझौते के अनुसार मूनक नहर के जरिए दिल्ली को 1,149 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बावाना तक केवल 924 क्यूसेक पानी ही पहुंच रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार राजधानी में रोजाना करीब 1,250 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्धता करीब 1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। दिल्ली अपनी 86.5 प्रतिशत कच्चे पानी की आपूर्ति पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होकर पूरी करती है। अधिकारियों का कहना है कि 1994 में दिल्ली की आबादी करीब एक करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग ढाई करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिससे पानी की मांग भी लगातार बढ़ी है।

यमुना जल बंटवारे का मौजूदा समझौता 12 मई 1994 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ था। इस समझौते की अवधि 30 वर्ष की थी और अब इसकी पुनर्विचार प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी कारण विभिन्न राज्य अपने-अपने दावे रख रहे हैं।

प्रतीकात्मक

भाखड़ा, एसवाईएल को लेकर पहले भी रहे विवाद

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच जल बंटवारे को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से कानूनी व राजनीतिक टकराव जारी है। इसी तरह भाखड़ा बांध से मिलने वाले पानी के वितरण को लेकर भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच मतभेद उभरते रहे हैं।

प्रयागराज में 46 वर्ष पूर्व हत्याकांड में पूर्व विधायक समेत चार को उम्र कैद

► एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया

► कोर्ट परिसर में रही गहमागहमी, विजय मिश्रा ने बोला-आल इज वेल

जागरण संवादाता, प्रयागराज : 46 वर्ष पूर्व कचहरी परिसर में दिनदहाड़े हुई हत्या में बुधवार को जिला अदालत ने दोषी पाए गए पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने सजा सुनाते हुए सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। निर्णय सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। कचहरी में ही सजा को लेकर मीडिया के सवाल पर पूर्व विधायक ने मुस्कुराते हुए 'आल इल वेल' बोलकर हाथ जोड़ लिए। फैसले के समय चारों दोषी अदालत में मौजूद रहे, लेकिन वादी मुकदमा श्याम नारायण वहां नहीं थे।

नवाबगंज क्षेत्र के हथिगहां गांव निवासी मुकदमा वादी श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाना में अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोप था कि उनका छोटा भाई प्रकाश नारायण पांडेय 11 फरवरी 1980 की दोपहर कचहरी के दीवानी परिसर में अपनी जमानत कराने के लिए गया था। तभी संतराम, बलराम, विजय मिश्रा, जीत नारायण अपने हाथों में असलहा लेकर आए और प्रकाश के सीने में गोली मार दी। दिनदहाड़े गोलीबारी में एक वकील समेत चार अन्य लोग घायल हुए थे। भाई को पुलिस स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले गई थी, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जमीन विवाद में संतराम, बलराम ने प्रकाश नारायण के खिलाफ आइपीसी की धारा 324 (गंभीर चोट पहुंचाने) का मुकदमा दर्ज कराया था।

100 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से बुधवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी चली। सबसे अधिक असर प्रयागराज मंडल में दिखा, जहां 10 लोगों ने जान गंवाई है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार, 14 मई, 2026

न्यूज गैलरी

महाराष्ट्र में प्रशिक्षण विमान की क्रैश-लैंडिंग, प्रशिक्षु सुरक्षित

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास रेड बर्ड एविएशन के एक ट्रेनिंग विमान ने क्रैश-लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान में सवार प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित बच गया। विमान कंपनी ने घटना की जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों से मिली जानकारी के अनुसार क्रैश-लैंडिंग के दौरान विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद विमान जमीन पर आ गिरा। (प्रेट्र)

केंद्रीय मंत्री के बेटे बंदी भागीरथ को पाक्सो मामले में समन

हैदराबाद : तेलंगाना पुलिस की एसआइटी ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ को बुधवार को पाक्सो के एक मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। पुलिस ने बंदी साई भागीरथ के मामा डा. सीएच वामशिकृष्ण को भी इस मामले में नोटिस दिया। वहीं, बंदी साई भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनके वकील ने आरोप लगाया है कि भागीरथ को हनी ट्रैप कर उनसे पांच करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश की गई। (एएनआइ)

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका खारिज

हाथरस : बूलगढ़ी प्रकरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका बुधवार को खारिज हो गई। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति विशेष की मान्हानि करने के आशय से विवादित टिप्पणी की थी। बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर, 2020 को अनुसूचित जाति की युवती पर हमला हुआ था. जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में बरी हुए तीनों युवकों ने राहुल गांधी के खिलाफ मान्हानि याचिका दायर की थी। (जासं)

आइ-पैक मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई 22 को

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके राज्य के अधिकारियों के आठ जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में 22 मई को सुनवाई करेगा। (प्रेट्र)

आरटीई कानून से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की नहीं होनी चाहिए अनिवार्यता

कई राज्यों व शिक्षक संघों ने टीईटी की अनिवार्यता के फैसले पर पुनर्विचार का किया अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं, बाद में सुनाएगा फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकार और देशभर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है, उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होना चाहिए।

यह भी दलील दी गई है कि उनकी नियुक्ति भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और अब वे दो दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीई कानून को बच्चों के लिहाज से देखा जाना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए कोर्ट ने दो वर्ष का समय दिया है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम नहीं लागू होने चाहिए क्योंकि उनकी भर्ती के समय टीईटी नहीं था। उन शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू नियम कानूनों के मुताबिक हुई थी। हालांकि, कोर्ट दलीलों से बहुत संतुष्ट नहीं दिखा।

कोर्ट ने वकीलों का ध्यान कानून के उपबंध की ओर खींचा, जिसमें पांच वर्ष में शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने को कहा गया था और बाद में समय बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को स्वयं को अपग्रेड करना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां के आंकड़े बताते हुए कहा कि ज्यादातर शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं, अगर कोर्ट का आदेश लागू किया गया तो ज्यादातर शिक्षक बाहर हो जाएंगे।

मेघालय और कुछ अन्य राज्यों ने कोर्ट से टीईटी करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा बढ़ा कर चार वर्ष करने का आग्रह किया। कोर्ट ने मांग पर विचार करने की बात कही।

बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए। अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी।
-सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता का फैसला दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का फैसला दिया था। उसके अनुसार, कक्षा एक से आठ तक को पढ़ाने वाले सभी शिक्षक जिनकी नौकरी पांच साल से ज्यादा बची है, उनके लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन जिनकी नौकरी पांच साल से कम बची है उन्हें टीईटी से छूट दी थी, परंतु उन्हें भी प्रोन्नति पानी है तो उसके लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। जो शिक्षक दो वर्ष के भीतर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई राज्य सरकारों और संगठनों की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश से पूरे देश में लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

बंगाल में भर्ती घोटाले के 'दागी' शिक्षकों से वेतन वसूली की शुरू हुई प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने का दिया निर्देश
- 25,735 लोगों की नौकरियां चली गई थीं, इनमें 18,418 शिक्षण कर्मचारी व बाकी गैर-शिक्षण कर्मचारी थे

बंगाल की नई भाजपा सरकार ने 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) शिक्षक भर्ती घोटाले में 'दागी' करार दिए गए शिक्षकों से वेतन वसूलने को बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उनकी सूची तैयार करने को कहा गया है। उन्हें यह गणना करने को भी कहा गया है कि दागी शिक्षकों को सेवा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन और उस पर ब्याज के रूप में राज्य सरकार को कितनी राशि वापस करनी होगी। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों को मिला वेतन लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को कायम रखा था।

भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और राज्य सरकार इसे मानने के लिए बाध्य है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अदालत जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, पूर्ववर्ती सरकार ने अधिसूचना जारी की थी लेकिन वेतन वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार इस मामले में सक्रिय हुई है। शिक्षा विभाग जिलों से विस्तृत जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वेतन लौटाने की बात कही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर विशेष रूप से सक्षम को कुछ राहत दी थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी की 2016 की भर्ती समिति को रद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 25,735 लोगों की नौकरियां चली गई थीं। इनमें 18,418 शिक्षण कर्मचारी व बाकी गैर-शिक्षण कर्मचारी थे।

कोलकाता में 'बुलडोजर एक्शन'

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब कोलकाता में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मंगलवार को तिलजला इलाके में एक अवैध कारखाने में लगी आग में दो लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और केएमडीए ने संयुक्त अभियान चलाकर इलाके की दो अवैध बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

मणिपुर में चर्च से जुड़े तीन पदाधिकारियों की हत्या, चार अन्य घायल

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर के कांगपोकपी में बुधवार को उग्रवादियों के हमले में चर्च से जुड़े तीन पदाधिकारियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह घटना कोट्जम और कोटलेन के बीच हुई, जब थाडौ बैपटिस्ट एसोसिएशन के सदस्य एक धार्मिक सभा में भाग लेने के बाद चूड़चंदपुर से लौट रहे थे। मृतकों में मणिपुर बैपटिस्ट कन्वेंशन के पूर्व महासचिव रेवरेंड वी. सितल्हौ सहित रेवरेंड काइगौलेन और पास्टर पाओगौलेन शामिल हैं। मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इस तरह की असंवेदनशील हिंसा मणिपुर में शांति के लिए खतरा है। घटना के बाद जिले में कुकी समुदाय की बहुसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में तीन दिनों के लिए पूर्ण बंदी लागू की गई है।

'हिंदुत्व एक जीवनशैली, हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं'

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-धार्मिक अनुष्ठान करना जरूरी नहीं, घर में दीपक जलाना भी आस्था साबित करने के लिए पर्याप्त
- सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव मामले की सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंदुत्व को जीवनशैली मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदू बने रहने के लिए किसी को मंदिर जाना या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है। घर में दीपक जलाना भी आस्था साबित करने के लिए पर्याप्त है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ जजों की संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा सहित विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

सुनवाई के 15वें दिन बहस शुरू होने पर एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जी मोहन गोपाल ने कहा कि धार्मिक समुदायों के भीतर से सामाजिक न्याय की मांग उठ रही है। हिंदुत्व को एक धार्मिक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया था। उसके बाद 1966 में यह माना गया कि हिंदू वह है जो धर्म और दर्शन के मामलों में वेदों को सर्वोच्च मानता है। पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा-इसीलिए हिंदुत्व को जीवनशैली कहा जाता है। किसी को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सीजेआइ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी झोपड़ी में दीपक जलाता है तो यह भी उसके धर्म को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

उप्र में आंधी-बारिश का कहर, 47 लोगों की मौत

जागरण टीम, लखनऊ

- पेड़, दीवार और बिजली गिरने से कई जिलों में हादसे, दर्जनों घायल
- बिजली व्यवस्था प्रभावित, रेल और सड़क यातायात घंटों बाधित रहा

प्रयागराज में बुधवार को आई आंधी में कार पर गिरा पेड़। प्रेट्र

प्रदेश में बुधवार को आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर बने चक्रवाती परिसंचरण व दक्षिणी राजस्थान से आ रही पुरवा हवा से कई जिलों में 100 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से आंधी चली। इस कारण अलग-अलग जिलों में पेड़, दीवार और बिजली गिरने से कुल 47 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आंधी के कारण रेल और बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित रही।

सबसे अधिक असर प्रयागराज मंडल में देखने को मिला। प्रयागराज में 16, प्रतापगढ़ में चार और कौशांबी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा 10 लोगों ने जान गंवाई। तेज चक्रवाती आंधी के दौरान दो हजार से अधिक पेड़ उखड़ गए। रेल लाइनों पर पेड़ गिरने से कई ट्रेनें रास्ते में खड़ी रहीं। प्रयागराज-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भी करीब सवा घंटा रुकी रही।

कानपुर और आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के दौरान 12 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में निर्माणाधीन भवन गिरने, पेड़ टूटने और हादसों में सात लोगों की जान चली गई। उन्नाव में पेड़ और बिजली का खंभा गिरने से एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में युवती और बालिका की जान चली गई, जबकि 33 बकरियां भी मर गईं। सरकार ने मृतकों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। बरेली, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ और दीवार गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई। कई बच्चे और अन्य लोग घायल हुए। हाईवे और मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा।

दो वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करा भारत लाने में मिली सफलता

- एनआइए ने इकबाल सिंह को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराने के बाद गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय जांच एजेंसियों को दो वांछित अपराधियों को विदेश से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने में सफलता मिली है। इनमें वांछित नार्को-आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा और प्रभदीप सिंह शामिल हैं।

एनआइए ने बुधवार को इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वह 2020 में पुर्तगाल भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से पंजाब ले जाने के लिए एनआइए को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति मिल गई। एनआइए ने जांच के दौरान इकबाल को भारत स्थित नार्को-टेरर माड्यूल का प्रमुख साजिशकर्ता और संचालक पाया था, जो पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी में शामिल था। वहीं, इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रहे भगोड़े नशीले पदार्थों के तस्कर प्रभदीप सिंह को बुधवार को अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया। प्रभदीप दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में एक मामले में वांछित था। दिल्ली पुलिस की तीन सदस्यीय एस्कार्ट टीम प्रभदीप सिंह को लाने के लिए अजरबैजान के बाकू गई थी और बुधवार को दिल्ली पहुंची।

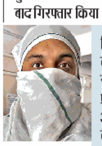

प्रभदीप सिंह।

दिल्ली पुलिस की तीन सदस्यीय टीम प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से वापस लाई

महाराष्ट्र में निदा खान को संरक्षण देने वाले पार्षद के घर और कार्यालय पर चला बुलडोजर

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

600 वर्ग फीट के आवास, व अन्य परिसर को ध्वस्त किया गया

- मतीन पटेल का पार्षद पद रद किए जाने का भी मंडरा रहा है खतरा

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बुधवार को नगर निगम पार्षद मतीन पटेल का अवैध निर्माण ढहाता बैकहो लोडर। एएनआइ

महाराष्ट्र के बहुचर्चित नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न एवं जबरन मतांतरण मामले में बुधवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम (सीएसएमसी) ने एआइएमआइएम के पार्षद मतीन पटेल का आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। मतीन पटेल पर यह कार्रवाई इस मामले की मुख्य आरोपित निदा खान को कई दिनों तक अपने परिसर में अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगने के बाद की गई है।

इस मामले में निदा खान करीब 40 दिनों से फरार चल रही थी, जिसे सात मई को छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव से गिरफ्तार किया था। छत्रपति संभाजी नगर के महापौर समीर राजुरकर ने तीन दिन पहले ही संकेत दे दिए थे कि मतीन पटेल की संपत्तियों की जांच की जा रही है। बुधवार सुबह करीब 6:15 बजे नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता तीन जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ नारेगांव के कौसर बाग इलाके में पहुंचा। मतीन पटेल के करीब 600 वर्ग फीट के आवास, कार्यालय और कुछ व्यावसायिक दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मतीन पटेल पर चुनाव के दौरान अवैध निर्माण की जानकारी छिपाकर झूठा हलफनामा देने के मामले में उनकी पार्षद सदस्यता रद किए जाने का खतरा भी मंडरा रहा है।

अबूझमाड़ के जंगलों से तीन माह में 19 करोड़ नकद बरामद, स्रोत अज्ञात

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर

- बस्तर में माओवादी अर्थतंत्र पर चोट, फंडिंग नेटवर्क की तलाश जारी
- अब माओवादियों के मददगार ठेकेदार, सप्लायर भी जांच के दायरे में

अबूझमाड़ के जंगलों में एक करोड़ रुपये नकद, सोने के बिस्किट और भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी ने माओवादी नेटवर्क के उस चेहरे को फिर सामने ला दिया है, जो बंदूक से ज्यादा पैसे के सहारे खड़ा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2026 के शुरुआती तीन माह में अब तक करीब 19 करोड़ रुपये, सोना और हथियार बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 65 लाख रुपये बुधवार को बीजापुर में बरामद हुए हैं। इससे यह संकेत मिला है कि माओवादी पुराने आर्थिक ढांचे के सहारे टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंगलों तक यह पैसा पहुंचाता कौन था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उन ठेकेदारों, सप्लायरों और कारोबारियों की पड़ताल कर रही हैं, जिन पर वर्षों तक लेवी नेटवर्क को जिंदा रखने का संदेह है। पहले गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडर फंडिंग नेटवर्क की अहम जानकारी दे देते थे, लेकिन अब कड़ियां भी बिखर गई हैं।

जंगलों में छिपाए गए करोड़ों रुपये की नकदी और हथियारों की बरामदगी का अभियान जारी है। अब तक बरामद अधिकतर रुपये लेवी वसूली से होने की पुष्टि हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब इस रकम और उससे जुड़े नेटवर्क पर है।
- सुंदरराज पी., आइजीपी बस्तर

बंजर भूमि सूखे कंठ ही तर नहीं करेगी धरती की प्यास भी बुझाएगी

झाबुआ जिले के आदिवासी ग्राम राजपुरा में जनसहयोग और श्रमदान से बनाया जा रहा तालाब, कुछ दिन में कार्य हो जाएगा पूरा

इस तरह हो रहा राजपुरा स्थित तालाब का निर्माण • नईदुनिया

जागरण विशेष

प्रेम विजय पाटिल • नईदुनिया

झाबुआ: पानी की कमी, बंजर भूमि और पलायन की मार झेलने वाला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी ग्राम राजपुरा अब जल संरक्षण की नई उम्मीद बनकर उभरा है। क्षेत्र में जनसहयोग एवं श्रमदान से बंजर भूमि पर विशाल तालाब बनाया जा रहा है। इसको राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद व उनके माता-पिता (जगरानी देवी व सीताराम तिवारी) को समर्पित किया गया है।

किसान संजय भूरिया बताते हैं कि राजपुरा और आसपास के गांवों में वर्षों से पानी बड़ी समस्या रहा है। यही वजह है कि उपजाऊ खेती सीमित थी, रोजगार के अवसर कम थे और गर्मी के मौसम में पानी का विकराल संकट खड़ा हो जाता था। ऐसे हालात में ग्रामीणों ने खुद ही समाधान तलाशने का निर्णय लिया। श्रमदान की पहल हुई, मगर धनराशि बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई। ऐसे में पिछले दिनों दिल्ली के दानदाता द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बाद अप्रैल 2026 में निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। खास बात यह भी है कि जिस काम पर 50 लाख रुपये तक खर्च हो सकते थे, वही कार्य जनसहयोग और श्रमदान से लगभग 12 लाख रुपये में पूरा हो रहा है। इसके कार्य में शिवगंगा अभियान की भी अहम भूमिका है।

महिला और पुरुष सहित 60 लोगों ने पानी सहेजने को बहाया पसीना

श्रमदान में जुटे ग्रामीण • नईदुनिया

क्षेत्र के चार गांवों राजपुरा, हत्यादेली, खालखंडवी व मालखांडवी की 28 महिलाओं, 20 पुरुषों एवं 12 बच्चों ने करीब एक माह तक श्रमदान किया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व शिवगंगा अभियान से जुड़े भंवर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण निर्माण स्थल पर पानी भरने लगा, जिससे कार्य रुक गया है। जल्द ही कार्य फिर से शुरू होगा। वर्तमान में तालाब निर्माण का केवल एक सप्ताह का कार्य शेष है। तालाब का लाभ उक्त चारों गांवों को मिलेगा।

- **10** करोड़ लीटर पानी संग्रहण है तालाब की क्षमता
- **50** लाख रुपये खर्च हो सकते थे यदि सहयोग के बिना कार्य किया जाता
- **12** लाख रुपये ही आया तालाब पर खर्च
- **200** परिवारों के लगभग 800 लोग होंगे इससे लाभांवित
- **4** गांव के किसानों को खेती में भी इस तालाब से होगा लाभ

30 हेक्टेयर बंजर क्षेत्र में हलमा शुरू

भंवर सिंह

भंवर सिंह बताते हैं कि तालाब निर्माण के लिए दिल्ली के एक दानदाता ने नाम गोपनीय रखने के आग्रह पर आर्थिक सहयोग किया। इसके बाद करीब 30 हेक्टेयर बंजर क्षेत्र में उपयुक्त स्थान चुना गया और फिर आदिवासी समाज की पारंपरिक हलमा पद्धति के जरिये श्रमदान आरंभ किया गया।

इस तरह शुरू हुआ शिवगंगा अभियान, बना दिए 130 तालाब

2002 में झाबुआ में हिंदू संगम आयोजन के दौरान शिव जल अभियान शुरू हुआ, जिसे 2004 में शिव गंगा समग्र ग्राम विकास परिषद के रूप में विस्तार दिया गया। शिवगंगा अभियान के तहत अब तक करीब 130 तालाब बनाए जा चुके हैं।

तालाब बन जाने से करीब 200 परिवारों के लगभग 800 लोग सीधे लाभांवित होंगे। भूजल स्तर सुधरेगा और भविष्य में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। गांव में ही रोजगार और खेती के अवसर उपलब्ध होने से पलायन पर रोक लगेगी।
प्रेम भाभर, सरपंच, ग्राम राजपुरा

निर्माण में तकनीकी समझ भी दिखी

संजय भूरिया कहते हैं कि कई ग्रामीण शिवगंगा अभियान के इंजीनियरिंग प्रशिक्षण वर्ग से पहले से प्रशिक्षित थे, इसलिए तालाब निर्माण में तकनीकी समझ भी दिखाई दी। किस क्षेत्र से मिट्टी हटाई जानी है, कितनी हटाई जानी है और किस तरफ मिट्टी डाली जानी है, इसका निर्णय वैज्ञानिक आधार पर किया गया। तालाब की पाल करीब 150 फीट लंबी और 35 फीट ऊंची बनाई जा रही है। तालाब में लगभग 10 करोड़ लीटर पानी संग्रहित हो सकेगा।

संजय भूरिया

यह है हलमा : आदिवासी समाज की पारंपरिक सामूहिक श्रमदान व्यवस्था को हलमा कहा जाता है। इसमें गांव के लोग बिना मजदूरी के मिलकर तालाब, मेड़बंदी, जलस्रोत व पर्यावरण संरक्षण के कार्य करते हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

हरभजन की सुरक्षा में आठ के बजाय 23 पुलिसकर्मी कैसे लगे

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, 15 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किसके आदेश पर किए तैनात

हरभजन सिंह। फाइल

वीआइपी सुरक्षा के नाम पर पुलिस के उपयोग की व्यापक समीक्षा की कही बात

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार से सवाल पूछते हुए पूरे राज्य में वीआइपी सुरक्षा संस्कृति पर बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप किया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने प्रारंभिक तौर पर पाया कि रिकार्ड में हरभजन की सुरक्षा के लिए केवल आठ पुलिसकर्मियों की स्वीकृति दिखाई दे रही है, जबकि 23 पुलिसकर्मी तैनात पाए गए। पूछा कि आखिर 15 अतिरिक्त पुलिसकर्मी किसके आदेश पर सरकारी खर्च पर लगाए गए।

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकृत आदेशों से परे अतिरिक्त पुलिस बल जोड़ा गया, जो सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला बन सकता है। अदालत ने पंजाब के एडीजीपी (सिक्योरिटी) और एसएसपी मोगा को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला-वार जांच कराने को कहा गया है कि कितने लोगों को सुरक्षा कवर मिला हुआ है और उनमें कितने पुलिसकर्मी आधिकारिक व कितने अनौपचारिक रूप से तैनात हैं। यह मामला अब केवल हरभजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पंजाब में वीआइपी सुरक्षा के नाम पर पुलिस के उपयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने 20 मई को अगली सुनवाई तय करते हुए चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हरभजन ने याचिका में दावा किया है कि खतरे के बिना किसी नए आकलन, नोटिस या सुनवाई के उनकी सुरक्षा वापस ली गई। वह 2022 में आप के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे। पार्टी छोड़ने की घोषणा के तुरंत बाद उनकी सुरक्षा हटाई गई।

पीएफसी का का शुद्ध लाभ बढ़कर 8,598 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 8,597.61 करोड़ रुपये रहा है। यह वृद्धि खर्चों में कमी के कारण हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी ने 8,357.88 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया था। जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 28,856.60 करोड़ रुपये रह गई।

भारत को विदेशी पूंजी पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दीर्घकालिक घरेलू जोखिम पूंजी का मजबूत आधार विकसित करना चाहिए।

- उदय कोटक, संस्थापक, कोटक महिंद्रा बैंक

संसेक्स	74,608.98	▲ 49.74	
निफ्टी	23,412.60	▲ 33.05	
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 1,65,350	▲ ₹ 8,550	
चांदी (प्रति किलो ग्राम)	₹ 2,97,500	▲ ₹ 20,500	
डालर	₹ 95.66	▼ ₹ 0.02	
क्रूड (प्रति बैरल)	$ 107.27		

आभूषण कारोबार होगा प्रभावित, तस्करी बढ़ने की आशंका

रत्न एवं आभूषण संवर्धन निर्यात परिषद ने कहा-शुल्क बढ़ाने से सोने का आयात नहीं घटता, सिर्फ कीमतों में होती है वृद्धि

- आयात शुल्क बढ़ाने का सबसे गंभीर असर एमएसएमई मैन्यूफैक्चरर्स पर पड़ेगा
- शुल्क मुक्त सोना लेने के लिए निर्यातकों को देनी पड़ रही 28-30 लाख रुपये की बैंक गारंटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने कहा है कि सोने पर शुल्क बढ़ाने से आयात पर अंकुश नहीं लगता बल्कि कीमतें बढ़ती हैं। स्थायी समाधान के लिए सरकार से उद्योग के हितधारकों के साथ बातचीत करने की अपील की है। जीजेईपीसी ने कहा, 'आयात शुल्क बढ़ाने से शायद ही कभी सोने का आयात घटता है। यह केवल कीमतें बढ़ाता है। हाल के समय में सोने की कीमतें दोगुनी होने के बावजूद आयात उसी अनुपात में नहीं घटा है।'

परिषद के अनुसार, उच्च शुल्क तस्करी को बढ़ावा देते हैं और निर्यात लागत बढ़ाते हैं। वहीं निर्यातकों को अब नामित एजेंसियों से शुल्क-मुक्त सोना लेने पर प्रति किलोग्राम 28-30 लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी पड़ रही है जिससे कार्यशील पूंजी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसका सबसे गंभीर असर एमएसएमई विनिर्माताओं पर पड़ेगा। परिषद में ऐसे 80 प्रतिशत सदस्य हैं जो 'गंभीर नकदी संकट' का सामना कर रहे हैं। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर बुधवार को 15 प्रतिशत कर दिया। प्लैटिनम पर कर 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप सोने/चांदी के डोरे, सिक्के, अन्य वस्तुएं आदि पर भी कर में बदलाव किए गए हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

पिछले वित्त वर्ष 72 अरब डालर का सोना आयात किया गया

भारत का सोना आयात 2025-26 में 24 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 71.98 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, मात्रा के आधार पर आयात 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रह गया।

आयात नियंत्रित करने को उपाय सुझाए

- 18 और 14 कैरेट जैसे कम शुद्धता वाले आभूषणों को बढ़ावा देकर आयात में 20-30 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है।
- पुराने सोने के विनिमय (अदला-बदली) को प्रोत्साहित किया जाए।
- 25,000 टन घरेलू सोना भंडार को उपयोग में लाने के लिए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को फिर से शुरू किया जाए।
- छड़ों, 'बिलेट' एवं सिक्कों में निवेश मांग को हतोत्साहित किया जाए और आभूषण निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

क्या बोले खुदरा विक्रेता

खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय सोने-चांदी के आयात पर मात्रात्मक अंकुश लगाना देश के चालू खाते के घाटा (कैड) को नियंत्रित करने का अधिक प्रभावी तरीका होगा।

अब सीमा शुल्क, जीएसटी और कृषि उपकर को मिलाकर आयात शुल्क के कारण सोना पहले के 13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर लगभग 27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो सकता है। **-राजेश रोकड़े,** चेयरमैन, अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद

ज्वेलरी स्टाक में रहा मिला-जुला रुख

बुधवार को ज्वेलरी स्टाक में मिला-जुला रुख देखने को मिला। आयात शुल्क बढ़ने से मांग कम होने की आशंका के बीच स्काई गोल्ड सात प्रतिशत से ज्यादा गिरा। हालांकि, सेनको गोल्ड 3.77 प्रतिशत, टाइटन कंपनी 0.95 प्रतिशत और पीसी ज्वेलर का शेयर 0.12 प्रतिशत ऊपर गया। पिछले दो कारोबारी सत्रों में ज्वेलरी स्टाक पर भारी बिकवाली का दबाव रहा। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 49.74 प्रतिशत बढ़कर 74,608.98 पर बंद हुआ। निफ्टी 33.05 अंक चढ़कर 23,412.60 पर बंद हुआ।

सोना 8,550 रुपये चढ़ा, चांदी 20,500 उछली

बहुमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत करने के बाद बुधवार को सोना 8,550 रुपये या पांच प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,65,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसका पिछला बंद भाव 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत 20,500 रुपये बढ़कर 2,97,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। स्थानीय कारोबारियों ने कहा कि बढ़े हुए शुल्क का वास्तविक प्रभाव आने वाले दिनों में तब दिखाई देगा जब यह खरीद लागत में परिलक्षित होने लगेगा। विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर रुपये ने भी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों को बढ़ाया है।

दुबई से बढ़ सकता है सोने-चांदी का आयात

सोने पर शुल्क बढ़ाने से दुबई से आयात बढ़ सकता है। आर्थिक शोध संस्थान 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव' (जीटीआरआइ) के अनुसार, शुल्क बढ़ोतरी से भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई के जरिये होने वाले बहुमूल्य धातुओं के आयात से आर्थिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत ने शुल्क दर कोटा प्रणाली के तहत दुबई से सोने के आयात को सामान्य सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र दर से एक प्रतिशत कम शुल्क पर अनुमति दी थी। यह कोटा 2022 में 120 टन वार्षिक से शुरू हुआ था और 2027 तक बढ़कर 200 टन होने वाला है, जो भारत के कुल वार्षिक सोना आयात का लगभग एक-चौथाई है।

रुपया 95.80 तक टूटने के बाद 95.66 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, प्रेट्र : रुपया बुधवार को कारोबार के दौरान डालर के मुकाबले रिकार्ड निचले स्तर 95.80 पर पहुंच गया। हालांकि मामूली सुधार के साथ अंत में 95.66 प्रति डालर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है।

रुपया इस साल एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है और इसमें अब तक छह प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत डालर और पश्चिम एशिया संकट को लेकर बढ़ती चिंताएं इसकी मुख्य वजह हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.52 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान यह एक समय 95.80 डालर तक गिर गया। अंत में रुपया 95.66 प्रति डालर पर रहा जो पिछले बंद स्तर से दो पैसा अधिक है। रुपया मंगलवार को 40 पैसे टूटकर 95.68 प्रति डालर के रिकार्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 17,258 करोड़ का रिकार्ड लाभ कमाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 17,258 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया है। यह 2024-25 के 7,271.32 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के 14,694 करोड़ रुपये के मुनाफे से भी अधिक है।

जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का एकल शुद्ध लाभ 46 प्रतिशत बढ़कर 4,901.50 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 3,354.98 करोड़ रुपये था। रिकार्ड तिमाही लाभ ऐसे समय दर्ज किया गया है जबकि मार्च में कंपनी को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने से भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी के सीएमडी विकास कौशल ने कहा कि चालू तिमाही (2026-27 वित्त वर्ष की पहली तिमाही) के 'कठिन रहने के आसार हैं।

नवंबर-अप्रैल में वनस्पति तेल का आयात 13 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश का वनस्पति तेल आयात 2025-26 तेल वर्ष के पहले छह महीनों में 13 प्रतिशत बढ़कर 79.4 लाख टन हो गया। पाम तेल की खेप में तेज उछाल इसकी मुख्य वजह रही। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल उपभोक्ता भारत ने पिछले वर्ष की समान अवधि (नवंबर-अप्रैल) में 70.4 लाख टन आयात किया था। भारत का तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। मूल्य के संदर्भ में, नवंबर-अप्रैल अवधि के दौरान आयात सालाना आधार पर 73,000 करोड़ रुपये से 19 प्रतिशत बढ़कर 87,000 करोड़ हो गया।

इस दौरान 87 हजार करोड़ रुपये का तेल आयात किया गया, पाम तेल का आयात दोगुना होकर 39.7 लाख टन हो गया

साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) के अनुसार, कुल आयात में खाद्य तेलों की हिस्सेदारी 78.2 लाख टन जबकि गैर-खाद्य तेल की 1.21 लाख टन रही। पाम तेल का आयात लगभग दोगुना होकर 27.4 लाख टन से बढ़कर 39.7 लाख टन हो गया जबकि सोया तेल तथा सूरजमुखी तेल सहित नरम तेलों की खेप 41.3 लाख टन से घटकर 38.5 लाख टन रह गई। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

अर्जेंटीना सोया तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है।

संकट जारी रहा तो सरकार को बढ़ानी पड़ेंगी ईंधन की कीमतें

ज्यूरिख (स्विटजरलैंड), आइएएनएस : आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है, लेकिन अगर यही हालात बने रहे तो वह कीमतों में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है।

आइएमएफ और स्विस नेशनल बैंक द्वारा मिलकर बुलाई गई इंटरनेशनल मानेटरी सिस्टम पर आयोजित एक कांफ्रेंस में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के बीच काम करने के ज्यादा आदी हो गए हैं। आपूर्ति के झटकों को लेकर भारत की कमजोरी का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि देश अभी खतरे में है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट में खाने की चीजों का हिस्सा अभी भी 40%है। मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया पर भारत की आर्थिक निर्भरता पर चिंता जताई।

केंद्र को आरबीआइ से मिलेगा रिकार्ड लाभांश

- सरकार को पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मिलेगी वित्तीय मदद
- आरबीआइ ने 2024-25 में सरकार को 2.69 लाख करोड़ का रिकार्ड लाभांश दिया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरबीआइ इस वर्ष सरकार को अब तक का सबसे अधिक लाभांश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे केंद्र को पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। आरबीआइ ने 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड लाभांश दिया था, जो इससे पिछले वर्ष 2023-24 के 2.11 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक था।

आरबीआइ इस महीने होने वाली अपनी निदेशक मंडल की बैठक में लाभांश की राशि पर फैसला ले सकता है। किसी भी वित्त वर्ष के लिए हस्तांतरण योग्य अधिशेष (सरप्लस) का निर्धारण आरबीआइ के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के आधार पर किया जाता है। संशोधित ढांचे के अनुसार, आकस्मिक जोखिम बफर के तहत जोखिम प्रावधान आरबीआइ के बही-खाते के 4.50 से 7.50 प्रतिशत के बीच बनाए रखना होता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, केंद्र को 2026-27 में आरबीआइ, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश और सरप्लस के रूप में 3.16 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3.75 प्रतिशत अधिक है।

सार्वजनिक बैंकों का लाभ ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा

बैंकों का कुल परिचालन लाभ 3.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि कुल शुद्ध लाभ 11.1 प्रतिशत बढ़कर 1.98 लाख करोड़ के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। लगातार चौथे वर्ष पीएसबी ने समग्र लाभ अर्जित किया है।

गैर कर राजस्व की श्रेणी में आता है आरबीआइ लाभांश

लाभांश और आरबीआइ के सरप्लस हस्तांतरण गैर-कर राजस्व की श्रेणी में आते हैं। केंद्र को कुल मिलाकर 2026-27 में गैर-कर राजस्व के रूप में 6.66 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जो 2025-26 के 6.67 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।

एयरटेल का शुद्ध लाभ 7,325 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 33.5 प्रतिशत घटकर 7,325 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 11,021.8 करोड़ रुपये था।

समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय 15.6 प्रतिशत बढ़कर 55,383.2 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 47,876.2 करोड़ रुपये थी। कंपनी की भारत से आय सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 39,566 करोड़ रुपये हो गई। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारती एयरटेल का शुद्ध लाभ 20.4 प्रतिशत घटकर 26,695 करोड़ रुपये रह गया, जबकि 2024-25 में यह 33,556 करोड़ रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की आय 21.9 प्रतिशत बढ़कर 2,10,972.8 करोड़ रुपये हो गई।

अंतरराष्ट्रीय

चीन ने खींची लक्ष्मण रेखा तो ट्रंप बोले- ईरान युद्ध में नहीं चाहिए बीजिंग की मदद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- चीनी दूतावास ने कहा, चार ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दखल की गुंजाइश नहीं
- ताइवान, मानवाधिकार व चीन के विकास पर नहीं होगी कोई बात
- बीजिंग पहुंचे ट्रंप, चिनफिंग के साथ आज होगी शिखर वार्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से ठीक पहले चीन ने वार्ता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वह ताइवान, मानवाधिकार और चीन के विकास समेत चार मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करेगा। जबकि ट्रंप ने चीन पहुंचने से पहले कहा कि उन्हें ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए चीन की मदद नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को बीजिंग पहुंचे। उनकी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ गुरुवार को शिखर वार्ता होगी।

रायटर के अनुसार, बीजिंग के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि उन्हें ईरान में युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान की पकड़ कमजोर करने के लिए चीन की मदद की जरूरत पड़ने की उम्मीद नहीं है। कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान मामले में किसी मदद की जरूरत है। हम इसे किसी न किसी तरह जीत लेंगे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से या किसी और तरीके से।" इससे पहले अमेरिका में चीनी दूतावास ने दो टूक कहा कि ताइवान पर चीन के रुख और उसके विकास के अधिकार समेत चार ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दखल की गुंजाइश नहीं है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "चीन-अमेरिका संबंधों में चार रेड लाइन को चुनौती नहीं दी जाए।" इस पोस्ट के साथ एक ग्राफिक भी है, जिसमें ताइवान का मुद्दा, लोकतंत्र व मानवाधिकार, राजनीतिक प्रणाली और चीन के विकास के अधिकार बताए गए हैं, जिन पर बीजिंग कोई समझौता नहीं करेगा। चीनी दूतावास ने कहा, चीन और अमेरिका को एक रणनीतिक, रचनात्मक व चीन-अमेरिका संबंध के निर्माण की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। उसने कहा, आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और लाभकारी सहयोग ही चीन व अमेरिका के बीच बेहतर संबंधों के लिए सही रास्ता है।" चिनफिंग ने नवंबर, 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के साथ वार्ता के बाद इन चार रेड लाइन की घोषणा की थी।

बीजिंग हवाईअड्डे पर बुधवार को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग (बाएं से चौथे) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। रायटर

ट्रंप-चिनफिंग वार्ता पर भारत की सतर्क नजर

जयप्रकाश रंजन • जागरण, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच गुरुवार से बीजिंग में शुरू हो रही दो दिवसीय शिखर वार्ता में क्रिटिकल मिनरल्स (रेयर अर्थ सहित) पर चर्चा एजेंडे का अहम हिस्सा होगी। इस मुद्दे पर भारत की भी सतर्क नजर है, क्योंकि अमेरिका व भारत के बीच क्रिटिकल मिनरल्स समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है। ट्रंप-चिनफिंग वार्ता से क्वाड में शामिल तीन देशों (जापान, आस्ट्रेलिया व भारत) की असहजता भी बढ़ेगी, क्योंकि इस संगठन में भी क्रिटिकल मिनिरल्स पर व्यापक सहयोग को लेकर वार्ता हो रही है। क्वाड में अमेरिका भी है। मार्च में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-यूएस क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट को लेकर कहा था कि यह बहुत ही जल्द होने वाला है। उन्होंने कहा था, "अगले कुछ महीनों में बड़ी घोषणा होने वाली है, जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिस्टम्स और उभरती टेक्नोलाजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगा।" जनवरी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात में भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। जुलाई 2025 में वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में "क्वाड क्रिटिकल मिनिरल्स इनिसिएटिव" की शुरुआत की गई थी। क्वाड के चारों देश (अमेरिका, भारत, जापान, आस्ट्रेलिया) 30-40 निजी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश, प्रसंस्करण क्षमता को बेहतर करने, गुणवत्ता के मानकों को तर्कसंगत बनाने पर काम कर रहे हैं। यह पहल स्पष्ट रूप से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से चीन के साथ क्षेत्र में सहयोग को लेकर क्वाड के अन्य देशों के असहज होने की बात सामने आ रही है।

दोनों देशों के बीच ताइवान है सबसे प्रमुख मामला

ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है। अमेरिका की तरफ से इसे सैन्य साजो-सामान मुहैया कराए जाने पर वह कई बार नाराजगी जता चुका है। यह माना जा रहा है कि ट्रंप-चिनफिंग वार्ता के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने गत दिसंबर में ताइवान के लिए 11 अरब डालर के हथियारों की बिक्री की घोषणा की थी। चीन को इस बात पर भी आपत्ति है कि अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दे पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है।

कर्ज में डूबता अमेरिका, ईरान युद्ध ने हिला दी डालर की बादशाहत

- अमेरिका का कर्ज 31.27 लाख करोड़ डालर पहुंचा जबकि जीडीपी 31.22 लाख करोड़ डालर रही

टोरंटो, द कन्वर्सेशन : दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत से डराने वाला अमेरिका अब खुद भारी संकट में फंसता दिख रहा है। पहली बार अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो गया है। मार्च के आखिर तक अमेरिका पर करीब 31.27 लाख करोड़ डालर का कर्ज पहुंच गया, जबकि उसकी जीडीपी 31.22 लाख करोड़ डालर रही। यानी अमेरिका जितना कमा रहा है, उससे ज्यादा कर्ज में डूब चुका है।

अब डर सिर्फ कर्ज का नहीं, बल्कि उस खतरे का है जो अमेरिका की नींव हिला सकता है। खाड़ी देशों का भरोसा अमेरिका से कमजोर पड़ने लगा है। खाड़ी देश अपने निवेश पर दोबारा विचार कर रहे हैं। खाड़ी देशों ने अमेरिका में करीब दो लाख करोड़ डालर का निवेश कर रखा है।

मच सकता है आर्थिक भूचाल : अमेरिका किसी भी विदेशी देश को पैसा निकालने से रोक नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। अमेरिकी बाजार की ताकत यह है कि कोई भी कभी भी पैसा लगा सकता है और निकाल सकता है, लेकिन अब यही खुलापन खतरा बन गया है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर खाड़ी देशों ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी संपत्तियां बेचनी शुरू कर दीं, तो शेयर बाजार और बांड बाजार में भारी गिरावट आ सकती है।

डालर बचाने के लिए अमेरिका ने चला नया दांव : इस खतरे से बचने के लिए अमेरिका अब स्वैप लाइन का सहारा ले रहा है। इसके तहत अमेरिकी फेडरल रिजर्व दूसरे देशों को डालर देता है ताकि वे अपनी अमेरिकी संपत्तियां बेचने पर मजबूर न हों। 2008 की मंदी में भी अमेरिका ने यही तरीका अपनाया था।

अमेरिकी ओपीटी वीजा जांच के दायरे में, भारतीय छात्रों के लिए खड़ी हुई नई चुनौती

- ओपीटी धोखाधड़ी मामले में अमेरिकी आइसीई की निगरानी में भारतीयों सहित 10 हजार विदेशी छात्र
- आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने कहा, ओटीपी कार्यक्रम धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) वीजा कार्यक्रम के जांच के दायरे में आने के बाद अमेरिका में पढ़ाई और काम करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आइसीई) ने ओपीटी कार्यक्रम पर एक व्यापक कार्रवाई शुरू की है।

आइसीई के कार्यवाहक निदेशक टाड लायंस ने ओपीटी कार्यक्रम के बारे में प्रहार करते हुए इसे "धोखाधड़ी का अड्डा" बताया। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को संदिग्ध नियोक्ताओं से जुड़े 10,000 विदेशी छात्रों से संबंधित अनियमितताएं मिली हैं। इनमें भारत के कई छात्र भी शामिल हैं।

इस बारे में लायंस और अन्य अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांचकर्ताओं ने किस प्रकार घटनास्थल का दौरा किया और अन्य बातों के अलावा ऐसे मामलों की पहचान की जहां भारत में स्थित कर्मचारियों द्वारा ओपीटी लाभार्थियों का "प्रबंधन" किया जा रहा था।

ओपीटी कार्यक्रम क्या है

ओपीटी विदेशी नागरिकों को, जो छात्र वीजा पर अमेरिका में प्रवेश करते हैं, 12 या कुछ मामलों में 24 महीनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। यह छात्रों को नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित एच-1बी वीजा में परिवर्तित होने की सुविधा भी देता है।

फेंटानिल मामले में अमेरिका ने लगाया भारतीय कंपनी से जुड़े 13 लोगों पर वीजा प्रतिबंध

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका ने कहा है कि वह भारतीय आनलाइन फार्मेसी केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स से जुड़े 13 लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है, जिन पर फेंटानिल युक्त नकली दवा की गोलियां बेचने का आरोप है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता के बयान के अनुसार, केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स और उसके सहयोगियों पर अवैध फेंटानिल से युक्त लाखों नकली दवाओं के वितरण का आरोप है, जिसके कारण पूरे अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

बयान में कहा गया है, "अवैध फेंटानिल से बहुत से अमेरिकियों की मौत हो रही है। भारत स्थित केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स जैसी प्रतिबंधित आनलाइन फार्मेसियों ने पूरे अमेरिका में भोले-भाले पीड़ितों को अवैध फेंटानिल से युक्त लाखों नकली दवाइयां बेची हैं, जिससे देशभर में परिवार और समुदाय तबाह हो गए हैं।

महंगाई से बेहाल पाकिस्तान, कब्र तक के लिए तरस रहे लोग

- गरीबों के लिए अपने परिजनों को दफनाना तक मुश्किल हो गया है

रावलपिंडी, एएनआइ : पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था अब उस भयावह मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां गरीबों के लिए अपने परिजनों को दफनाना तक मुश्किल हो गया है। आसमान छूती महंगाई ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि अंतिम संस्कार और कब्र की व्यवस्था भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी में दशकों पुरानी वह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, जिसमें लोग सेवा भाव से मुफ्त में कब्र खोदते थे। अब कब्रिस्तान भी कमाई का जरिया बन गए हैं। कब्र की जगह, खोदाई और ईंटों की तैयारी के लिए लोगों से 40 से 45 हजार पाकिस्तानी रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो चुकी है : हालत यह है कि शहर के कई बड़े कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो चुकी है। जगह-जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि अब दफनाने के लिए कोई प्लाट खाली नहीं बचा। गरीब परिवार अपनों को दफनाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। महंगाई ने कफन तक को महंगा बना दिया है। जो कफन पहले मामूली रकम में आ जाता था, उसकी कीमत अब तीन हजार से चार हजार पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई है।

वहां की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक : शर्मनाक बात यह सामने आई है कि कुछ कब्रिस्तान कर्मियों पर पुराने कब्र हटाकर पैसे लेकर नई दफन की जगह देने के आरोप लगे हैं। यानी पाकिस्तान में अब इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र भी सुरक्षित नहीं रह गई है। पाकिस्तान लंबे समय से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के लिए जीना ही नहीं, मरना भी महंगा पड़ रहा है।

इस्लामिक नाटो बनाने की फिराक में पाक

इस्लामाबाद, एएनआइ : नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) की तर्ज पर पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने की फिराक में है। इसी कवायद में उसने पहले सऊदी के साथ रणनीतिक रक्षा समझौता किया और अब इसमें कतर व तुर्किये को भी शामिल करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इन दोनों देशों के साथ क्षेत्रीय रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

आसिफ ने कहा, इस व्यवस्था पर चर्चा विभिन्न चरणों में चल रही है और भविष्य में इन देशों को शामिल किया जा सकता है।" पाकिस्तान ने पिछले वर्ष सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस बात का संकल्प है कि उनमें से किसी के खिलाफ आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। कतर और तुर्किये को भी समझौते में शामिल किए जाने के बारे में संकेत से जाहिर है कि इस्लामिक नाटो के गठन की कोशिशें चल रही हैं।

दैनिक जागरण

अनुभव के साथ ज्ञान और समृद्ध होता जाता है

फिजूलखर्ची की संस्कृति

यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वे जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं, उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। उनकी ओर से अपनी कारों के काफिले को छोटा किए जाने के बाद कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया है। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे, लेकिन ऐसा ही गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी दिखना चाहिए। इसी के साथ ही सांसदों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ नौकरशाहों को भी ऐसा ही करना चाहिए। किफायत का परिचय देना किसी सरकार या दल विशेष का विषय नहीं। यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और केवल वर्तमान की ही नहीं। चूंकि हम एक विकासशील देश हैं, इसलिए मितव्ययिता का परिचय तो सदैव ही दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक नेताओं और नौकरशाहों की ओर से दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बीच किफायत की जगह फिजूलखर्ची की संस्कृति ने जड़ें जमा ली हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि जो जितने लंबे काफिले से चलता है, वह उतना ही धमक-हनक वाला माना जाता है। दिखावे वाली इस मानसिकता से मुक्ति पाने की सख्त जरूरत है।

आज यदि ऊर्जा संकट के चलते मंत्रीगण दो-तीन कारों के साथ चलने को उपयुक्त समझने लगे हैं, तो इसके पहले वे इसकी जरूरत क्यों नहीं समझ रहे थे? आखिर ऐसा तो है नहीं कि ऊर्जा संकट के पहले पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन देश में ही हो रहा था या फिर उनका आयात बहुत सस्ता था। सरकारी तंत्र को तो इससे कहीं अच्छे से अवगत होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक खपत पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ही होती है। सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी लाने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने वाले अन्य दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान देना होगा। विदेशी मुद्रा की एक बड़ी खपत पर्यटन के लिए विदेश यात्राओं के चलते होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि देश में वैसे पर्यटन स्थल और पर्यटकों के अनुकूल माहौल विकसित नहीं हो पाया है, जैसा मालदीव, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों ने विकसित कर लिया है। यह तब है, जब भारत पर्यटन स्थलों की दृष्टि से कहीं अधिक समृद्ध है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि अब लोग शादियां, पार्टियां आदि करने के लिए भी विदेश जाने लगे हैं। विदेशी मुद्रा की एक बड़ी खपत विदेश पढ़ने वाले जाने वाले छात्रों के कारण भी होती है। हमारे छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने इसलिए जाते हैं, क्योंकि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा हो कि सामान्य दिनों में भी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने एवं विदेशी मुद्रा बचाने की संस्कृति विकसित की जाए।

देरी पर लगेगा अंकुश

बिहार सरकार द्वारा सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि किसी आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। यह स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही और अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। कई बार अधिकारी आवेदन को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था को भूमि विभाग में सफलतापूर्वक लागू करवाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वस्तुतः हाल के दिनों में जमीन के म्यूटेशन के मामले में जब आवेदन के निपटारे की समय सीमा तय की गई तो दस्तावेज की कमी की नोटिंग के साथ कई के आवेदन लौटा दिए गए। इससे जनता में निराशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है। ऐसा न हो, यह ध्यान रखना होगा। विभागों में संसाधन, कर्मचारियों की उपलब्धता और तकनीकी व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। आमतौर पर जनता की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि सरकारी कार्यालयों में आवेदन देने के महीनों भर बाद भी सुनवाई नहीं होती। अब समय सीमा तय कर देने और इसकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर होने से इस पर अंकुश लगेगा। इससे जनता को राहत मिल सकती है।

आवेदन निपटारे की समय सीमा तय करने और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर डैशबोर्ड बनाने से सुधरेगी व्यवस्था

पहले सरकारी तंत्र बरते किफायत

राजीव शुक्ला

पहले केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों एवं अधिकारियों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी, उसके बाद ही जनता को उपदेश देना उचित होगा

गांधीजी के आश्रम पहुंची एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, लेकिन यदि आप उसे गुड़ खाने से मना कर देंगे तो वह उसे छोड़ देगा। गांधीजी ने महिला और उसके बेटे की तरफ देखा और कहा कि आप अगले महीने इस तारीख को मुझसे मिलने आना। एक महीने बाद नियत तिथि पर महिला बेटे को लेकर गांधीजी के पास गई। गांधीजी ने उसके बेटे से कहा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। बेटे ने वहीं कसम खाई कि वह गुड़ नहीं खाएगा। इस पर महिला बोली कि मैं इतनी दूर से चलकर आपके पास आती हूं। यही बात आप महीने भर पहले भी बोल सकते थे। तब गांधीजी ने महिला से कहा कि मैं किसी को भी नसीहत तभी दे सकता हूं, जब मैं उसका खुद पालन करूं। इस एक महीने के दौरान मैंने पहले खुद गुड़ छोड़ा और तब मेरा अधिकार बना कि बच्चे को बोल सकूं कि तुम गुड़ छोड़ दो। इसके पहले मुझे इसे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। महिला की आंखों में आंसू आ गए और वह बेटे को लेकर गांव चली गई। यह किस्सा प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंह राव ने अमेरिकी संसद में सुनाया था। मैं भी प्रधानमंत्री के साथ उस यात्रा पर गया था। यह उस समय की बात है, जब अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा था कि वह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ झुककर समझौता करे। राव ने अमेरिकी सरकार की बात चुपचाप सुनी और उसका जवाब उन्होंने अमेरिकी संसद में सभी सदस्यों के सामने दिया कि आप मुझे कश्मीर पर झुकने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप मेक्सिको पर कोई समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं? मेक्सिको की जमीन आपने हड़पी हुई है और हमें उपदेश दे रहे हैं। पहले यह आप अपने ऊपर लागू करें, जैसे गांधीजी करते थे। तभी आप मुझे यह सलाह दे सकते हैं। मैंने देखा कि राव की बात सुनकर खुद अमेरिकी सांसद ताली बजा रहे थे।

आज भारत सरकार लोगों को नसीहत दे रही है कि आप पेट्रोल-डीजल कम खर्च करें, विदेश यात्राएं न करें, सोना न खरीदें, गैस का कम इस्तेमाल करें, ज्यादा वाहन न चलाएं, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करें। खाने के तेल का कम इस्तेमाल करें। किसान खाद का प्रयोग घटाएं। सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल न करें, विदेशी वस्तुओं को न खरीदें। अनावश्यक खरीद न करें। याद रहे कि सोना केवल धातु या आभूषण ही नहीं, बल्कि हमारी शादियों में जुड़ी एक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें सोने के जेवर सम्मान के लिए दिए जाते हैं। यहां तक कि सरकार ने भी सोने को स्त्रीधन कहा है और अब वह कह रही है कि खरीदो ही मत। ठीक है कि एक बार जनता यह मान भी ले कि वह यह सब कुछ न करे, लेकिन उसके सामने जो उदाहरण पेश किया जाता है, उससे उसे बड़ी बैचेनी होती है कि खुद सरकार और सरकार में बैठे लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। खरीदारी कर रहे हैं। विदेश यात्राएं कर रहे हैं और ज्ञान जनता को दिया जा रहा है। अभी जिन राज्यों में चुनाव थे, वहां सत्तारूढ़ दल के लोगों ने देश के तमाम निजी विमानों और हेलीकाप्टरों को किराये पर ले लिया था ताकि विपक्ष उनकी सुविधा का लाभ न उठा सके। इन पर अंधाधुंध खर्च किया गया। चुनावी रैलियों के लिए अंधाधुंध बसें और अन्य अनेक साधन-संसाधन लगाकर लोगों को जुटाया जा रहा था। कहीं कोई बचत न तो सरकार में बैठे अफसर दिखा रहे थे और न ही सरकारें। अब अचानक सारा ज्ञान और भाषण जनता को दिया जा रहा है, जबकि संकट अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ते ही उभर आया था व डालर के मुकाबले रुपया कमजोर होना शुरू हो गया था।

यह ठीक नहीं कि बड़े नेता गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं। इसी तरह मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राएं हो रही हैं और वहां विदेशी मुद्रा खर्च पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। अब तो साधु-संत और कथावाचक तक निजी जहाजों में घूम रहे हैं। उनमें भी सादगी नाम की कोई चीज नहीं रह गई, लेकिन दूसरों को सादगी की सलाह सब दे रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों के यहां शादी-ब्याह पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता को नसीहत कि वह खर्च कम करे। नसीहत की बारिश किसानों पर भी हो रही है कि वे खाद का उपयोग आधा कर दें। यह कहने से पहले सोचना चाहिए कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर हो गई है और उपज बढ़ाने के लिए किसान को खाद डालनी ही पड़ती है। प्राकृतिक खेती से पैदावार कम होती है तो इन करोड़ों लोगों के लिए खाने-पीने का संकट आ जाएगा।

सरकार को खाने-पीने की तमाम चीजें खासतौर से खाद्य तेल बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। अब यदि पैदावार कम होगी तो फल, फूल, दालों सभी का संकट आएगा। आज तेल और गैस की किल्लत जैसी स्थिति बन रही है, उसकी एक बड़ी वजह हमारी गलत विदेश नीति भी है, क्योंकि पारंपरिक मित्र रहे तेल उत्पादक देशों से हमने रिश्ते बिगाड़ लिए। एक इजरायल को खुश करने के चक्कर में दुनिया के तमाम देशों से हमारे रिश्ते खराब हो गए। अब रूस से भी सस्ता तेल मिलना बंद हो गया। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक के दौर में जिस विदेश नीति का पालन किया गया, उसे आज हमने उलट दिया और हम एक छोटे गुट के साथ हो गए, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया और वह उन सबका मित्र बन बैठा, जिन्हें हमने नाराज कर दिया।

यह दिख रहा है कि हम दुनिया से अलग-थलग हो गए हैं। अमेरिका भी अब हमें आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस वजह से हमारे यहां तेल संकट, गैस संकट, खाने पीने का संकट, खाद्य उत्पादों का संकट पैदा होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को उपदेश देने के पहले सरकार को अपने खर्चे घटाने होंगे। पहले ये सारी पाबंदियां अपने ऊपर लागू करनी होंगी। दिनों-दिन बढ़ रहे सरकारी खर्चे नियंत्रण में लाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों और अफसरों को पहले अपने ऊपर लगाम लगानी होगी। तभी जनता को उपदेश देना उचित होगा।

(लेखक राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

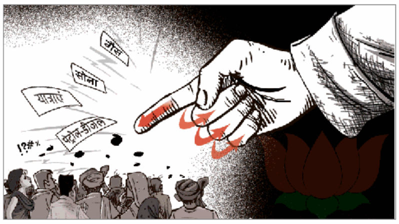

अवधेश राजपूत

असंभव नहीं पेपर लीक होने से रोकना

संजीव जायसवाल 'संजय'

सरकार को समझना होगा कि नीट का पेपर लीक होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा है

देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण पूरी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इस पेपर लीक कांड ने लाखों युवाओं के सपनों और उनके अभिभावकों के भरोसे को तोड़कर रख दिया। नीट निरस्त होने से 22 लाख से अधिक छात्रों को यह परीक्षा फिर से देनी होगी। इन छात्रों और अभिभावकों के कष्टों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यह खेद की बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर फेल हो गई।

यह केवल एक परीक्षा का पर्चा बाहर आना नहीं है, बल्कि देश की मेधा और भविष्य के साथ किया जाने वाला क्रूर मजाक है। क्या वास्तव में एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना असंभव है? पेपर लीक कांड के माफिया भली-भांति जानते हैं कि कुछ दिनों तक शोर मचेगा, जांच की घोषणाएं होंगी, धरना-प्रदर्शन होंगे और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। इसी का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी बेखौफ होकर अगली परीक्षा में सेंधमारी की तैयारियों में जुट जाते हैं। हमें 'कैट' जैसी परीक्षाओं की ओर भी देखना चाहिए, जिसमें भी लाखों छात्र बैठते हैं, परंतु वहां पेपर लीक की घटनाएं लगभग शून्य हैं। असल समस्या प्रबंधन की नहीं, बल्कि उस 'पूंजी' की है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। मेडिकल कालेजों विशेषकर निजी संस्थानों की सीटों में करोड़ों-अरबों का खेल चलता है। जब दांव पर इतना धन होता है, तो शक्तिशाली लोग और रसूखदार तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए वह संजीदगी नहीं दिखाई जाती, जो दिखाई जानी चाहिए। प्रश्नपत्र तैयार करने, प्रिंट करने, फिर जिला स्तर के ट्रेजरी तक और वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की वर्तमान व्यवस्था में इतनी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं शामिल हैं कि उसे फूलप्रूफ बना पाना बहुत मुश्किल है।

यदि हम पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, तो वर्तमान कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। इसके लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया एक आदर्श उदाहरण हो सकती है। जिस तरह केंद्रीय बजट पेश होने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को बाहरी दुनिया से काटकर क्वारंटाइन कर दिया जाता है, वैसा ही माडल यहां भी अपनाया जाना चाहिए। परीक्षा से तीन-चार दिन पहले 10-12 विशेषज्ञों को एक गोपनीय और सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया जाए। इनसे कम से कम 20 अलग-अलग प्रश्नपत्रों के सेट तैयार कराए जाएं, जिनमें सभी प्रश्नों के अंक एकसमान हों। मान लीजिए किसी परीक्षा में सौ प्रश्न पूछे जाने हैं तो 20 प्रश्नपत्रों के सेट के आधार पर 2,000 प्रश्नों का एक विशाल 'क्वेश्चन बैंक' तैयार किया जाए। परीक्षा शुरू होने से मात्र दो-तीन घंटे पहले कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर इन 2,000 प्रश्नों में से सौ प्रश्नों का चयन किया जाए। इसकी पीडीएफ फाइल तुरंत तैयार कर पासवर्ड और डिजिटल सुरक्षा के साथ सभी केंद्रों को ईमेल कर दी जाए। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय पहले तक किसी को भी, यहां तक कि परीक्षा कराने वाली संस्था के प्रमुख को भी नहीं पता होगा कि कौनसे प्रश्न आने वाले हैं। जब जानकारी ही नहीं होगी, तो लीक होने की आशंका स्वतः शून्य हो जाएगी। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटर खराब होने या बिजली चले जाने के कारण प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग में समस्या आ सकती है। इसका समाधान यह है कि हर परीक्षा केंद्र पर प्रिंटर और जेनरेटर का डबल नहीं, ट्रिपल बैकअप तैयार रखा जाए, ताकि एक के खराब होने पर दूसरे और दूसरे के खराब होने पर तीसरे से प्रश्नपत्र को तत्काल प्रिंट किया जा सके।

छात्रों के साथ छल है पेपर लीक की घटनाएं। फाइल

चूंकि कई मामलों में परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक ही धांधली में शामिल पाए गए हैं, इसलिए कानून में सख्त प्रविधान की आवश्यकता है। यदि किसी केंद्र पर ट्रिपल बैकअप के बावजूद प्रश्नपत्र प्रिंट नहीं हो पाते, तो इसे केंद्र की साजिश माना जाना चाहिए। ऐसे विद्यालय के प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, भारी आर्थिक दंड और अनिवार्य जेल का प्रविधान होना चाहिए। जब जिम्मेदारी तय होगी, तभी व्यवस्था सुधरेगी। आलोचक कह सकते हैं कि देश के हजारों केंद्रों पर डबल-ट्रिपल बैकअप की व्यवस्था खर्चीली होगी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में प्रश्नपत्रों की केंद्रीकृत छपाई, उनके देशव्यापी परिवहन और सुरक्षा के लिए तैनात हजारों पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक अमले पर जो भारी-भरकम खर्च होता है, उसकी तुलना में डिजिटल वितरण और बैकअप की लागत काफी कम होगी। असंभव कुछ भी नहीं है। आवश्यकता केवल दृढ़ इच्छाशक्ति की है। सरकार को समझना होगा कि पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक प्रकार की राष्ट्रीय आपदा है, जो युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट रही है।

(लेखक रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक और साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भावों का संतुलन

मनुष्य केवल देह और आत्मा का संयोगमात्र ही नहीं, अपितु भावनाओं का एक सजीव संसार भी है। प्रेम, क्रोध, करुणा, ईर्ष्या, उत्साह, भय, आशा और निराशा जैसे अनेक भाव उसके जीवन को दिशा देते हैं। संतुलित अवस्था में ये भाव जीवन के आलेखन में रंग भर देते हैं, किंतु जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तब यही भाव व्यक्ति के लिए विविध समस्याओं का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए जीवन में भावों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। भावों की अस्थिरता दृष्टिगोचर होती है, जैसे कहीं क्रोध का विस्फोट दिखाई देता है तो कहीं अवसाद की गहरी खामोशी। ऐसे परिवेश में भावों का संतुलन एक अनिवार्य आवश्यकता है।

भावों के संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य भावशून्य हो जाए। इसका अर्थ है-प्रत्येक परिस्थिति में मनोभावों को नियंत्रित और संयमित रखना। जबकि अत्यधिक मोह व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देता है। इसी प्रकार असीम महत्वाकांक्षा तनाव को जन्म देती है और अत्यधिक निराशा व्यक्ति को जीवन से विमुख कर सकती है। भारतीय संस्कृति ने सदैव 'समत्व' की शिक्षा दी है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी यही संदेश दिया कि सुख-दुख और लाभ-हानि से परे सोचकर कर्म में रमो।

यदि व्यक्ति सफलता में अहंकार से बच जाए और असफलता में धैर्य बनाए रखे, तो वह हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकता है। भावों के संतुलन के लिए आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और धैर्य चाहिए। भावों का संतुलन ही सार्थक जीवन की आधारशिला है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन की आधी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली। आज आवश्यक है कि हम आधुनिकता की दौड़ में आंतरिक संतुलन को न खोएं, क्योंकि शांत और संतुलित मन ही जीवन को सही अर्थों में सुंदर बनाता है।

प्रेरणा अवस्थी

कृत्रिम बुद्धि और चेतना का सवाल

प्रदीप

क्या एआइ सिर्फ इंसानों जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की नकल कर रहा है, या कुछ महसूस भी कर सकता है?

हाल में विख्यात विकासवादी जीवविज्ञानी रिचर्ड डाकिंस ने अमेरिकी कंपनी 'एंथ्रोपिक' द्वारा विकसित एक एआइ चैटबाट 'क्लाउड' से लगातार तीन दिनों तक बातचीत (चैट) करने के बाद कहा कि यह मानना कठिन है कि इतनी संवेदनशील और सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं देने वाली मशीन पूरी तरह 'अचेत' हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी मशीन से नहीं, बल्कि किसी समझदार और संवेदनशील इंसान से बात कर रहे हों। डाकिंस जैसे संशयवादी विज्ञानी के इस वक्तव्य के बाद कृत्रिम बुद्धि (एआइ) और चेतना पर चल रही पुरानी बहस अचानक दार्शनिक विमर्शों से निकलकर आम चर्चा का केंद्र बन गई है। इससे एक बड़ा सवाल फिर सामने आ गया है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता-युक्त मशीनें वास्तव में कभी 'चेतन' हो सकती हैं?

अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि एआइ के पास असली भावनाएं नहीं होती हैं। मौजूदा एआइ प्रणालियां खासकर 'लार्ज लैंग्वेज माडल' (एलएलएम) अरबों शब्दों और संवादों के आधार पर प्रशिक्षित होती हैं। वे अगले संभावित शब्द का अंदाजा लगाकर जवाब तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया में वे इतनी स्वाभाविक भाषा उत्पन्न करती हैं कि यूजर को लगता है जैसे सामने कोई संवेदनशील व्यक्ति मौजूद हो। लेकिन अधिकांश विज्ञानियों का मत है कि यह 'चेतना' नहीं, बल्कि अत्यंत उन्नत सांख्यिकीय अनुकरण है। एआइ के पास न अनुभव है, न दर्द, न खुशी और न ही आत्म-जागरूकता, वह तो महज पैटर्न पहचानती है और उसी के आधार पर प्रतिक्रिया देती है। फिर भी भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है।

वर्तमान एआइ बाट्स 'मैं', 'मुझे लगता है', 'मैं समझ सकता हूं' जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यूजर्स को लगता है कि मशीन के भीतर कोई इंसान है। इंसान की चेतना उसके जैविक अनुभवों, भावनाओं, स्मृतियों और शरीर से जुड़ी होती है। प्यार, दर्द, डर और करुणा केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभूतियां हैं। विज्ञानियों के मुताबिक इंसानी दिमाग में चलने वाली जटिल तंत्रिका प्रक्रियाओं से चेतना उत्पन्न होती है। हालांकि यह अब भी विज्ञान का सबसे पेचीदा सवाल बना हुआ है कि आखिर 'अनुभूतियां' पैदा कैसे होती हैं? जब हम स्वयं मानव चेतना को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, तब मशीन की चेतना को मापना और भी कठिन हो जाता है। विज्ञानियों ने एआइ में चेतना की जांच के लिए नई कसौटियां विकसित करनी शुरू की हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे मानदंडों की एक सूची बनाई है, जिसके आधार पर यह परखा जा सकता है कि किसी एआइ प्रणाली में चेतना जैसी विशेषताएं किस हद तक मौजूद हैं। फिलहाल चैटजीपीटी जैसे माडल इन कसौटियों पर नहीं खरे उतरते हैं। इसलिए अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान एआइ सचेत नहीं हैं।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

प्रश्नों के घेरे में परीक्षा प्रणाली

'परीक्षार्थियों से खिलवाड़' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में परीक्षा प्रणाली की विसंगतियों और उसके दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया है। नीट का प्रश्नपत्र लीक होना केवल एक परीक्षा की त्रुटि नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, सपने और मानसिक संतुलन ऐसे मामलों से प्रभावित होते हैं। परीक्षा रद होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन छात्रों पर पड़ता है, जिन्होंने ईमानदारी और कठिन परिश्रम से तैयारी की होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए का गठन पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न करती हैं। प्रश्नपत्र लीक, अव्यवस्था और तकनीकी कमजोरियां दर्शाती हैं कि परीक्षा प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के दौर में भी पुराने तरीकों से प्रश्नपत्रों का प्रबंधन किया जाना चिंताजनक है। सरकार और संबंधित एजेंसियों को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। इसलिए इनके संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्यार्थियों के विश्वास को बनाए रखना ही किसी भ परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी सफलता है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

मेलबाक्स

भयमुक्त और भरोसे की सरकार

बंगाल में जंगलराज का खात्मा- केवल एक राजनीतिक नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कानून के शासन, लोकतांत्रिक सहिष्णुता और प्रशासनिक पारदर्शिता की स्थापना का संकल्प बनना चाहिए। बंगाल ने भारतीय राजनीति और संस्कृति को दिशा दी है, अब समय है कि वह लोकतांत्रिक परिपक्वता का भी उदाहरण बने। जनता ने परिवर्तन का अवसर दिया है। अब यह सत्ता में आने वालों पर निर्भर है कि वे इसे लोकतांत्रिक सुधार में बदलते हैं या केवल एक नई राजनीतिक लड़ाई में। भारत के संघीय लोकतंत्र में किसी भी राज्य की स्थिरता पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। बंगाल जैसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में यदि राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति जारी रहती है, तो उसका प्रभाव सामाजिक सौहार्द और विकास दोनों पर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों को बदले की भावना के बजाय लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा जाए।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

छात्रों के साथ अन्याय

बुधवार को प्रकाशित 'परीक्षार्थियों से खिलवाड़' अग्रलेख पढ़ा। पेपर लीक की आशंका से नीट की परीक्षा रद कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा जो इस तीन मई को हुई थी, रद कर दी। इस परीक्षा के पेपर लीक की जांच सीबीआइ को करने के आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर से इस परीक्षा को देने वाले मेहनती और ईमानदार छात्रों के साथ धोखा हो गया। इस मामले की सच्चाई क्या है यह तो उचित और निष्पक्ष जांच से ही पता चल सकेगा? सवाल यह है कि एंटी पेपर लीक कानून लागू अर्थात 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' अमल में आने के बावजूद पेपर लीक के मामले क्यों नहीं थम रहे? वस्तुतः शिक्षा प्रणाली के दोष देश के लिए दीमक होते हैं। जिस देश की शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रवेश और दूसरी बहुत सी परीक्षाओं में भी दोष आ जाएं तो उस देश की सारी व्यवस्था में ही दोष आ जाएंगे और यह दोष देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। अगर सरकारों ने इस बीमारी का इलाज शुरू में ही करने के लिए रुचि दिखाई होती तो आज यह पेपर लीक की बीमारी मेहनतकश युवाओं के मुसीबत न बनती। अब समय आ गया है कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया जाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

16.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है सोने का हिस्सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वर्तमान में, जो वर्ष 2010 में मात्र छह से सात प्रतिशत ही था। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में भी सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है।

विक्रांत निर्मला सिंह
शोधार्थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

आजकल

आर्थिक रणनीति में सामयिक परिवर्तन

पश्चिम एशिया में तनाव से उभरते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने, सोने की खरीद कम करने, स्वदेशी उत्पाद अपनाने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50 प्रतिशत तक घटाने का आग्रह किया है। पहली नजर में यह सामान्य राजनीतिक या नैतिक अपील लग सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लंबे समय से स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर जोर देते रहे हैं। लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इन अपीलों का अर्थ गहरा है

सार्वजनिक परिवहन नीति में व्यापक बदलाव करने से ईंधन की खपत में कमी लाई जा सकती है। फाइल

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले लगभग ढाई महीने से जारी सैन्य संघर्ष के कारण समूचा पश्चिम एशिया दुष्प्रभावित है। इससे भारत में ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने की एक व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनमिक) रणनीति का हिस्सा है। दरअसल, मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार आयात पर निर्भरता कम करके विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को घटाना चाहती है।

अब देश के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से आई इस अपील को सही संदर्भ में समझने के लिए हमें तीन प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को समझना आवश्यक है। पहली चुनौती है 'बाह्य निर्भरता'। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यानी ऊर्जा के मामले में भारत की विदेशी निर्भरता बहुत अधिक है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डालर प्रति बैरल की वृद्धि भारत के आयात बिल पर लगभग 13 से 14 अरब डालर (लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये) का अतिरिक्त बोझ डालती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपये की कीमत घटती है।

दूसरी बड़ी चुनौती है 'आयातित महंगाई'। जब वैश्विक बाजार में तेल, गैस और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। आयात महंगा होने से ऊर्जा लागत अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है, रुपया कमजोर पड़ता है और नतीजतन घरेलू बाजार में वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, रुपये में हर एक प्रतिशत की गिरावट से थोक महंगाई दर लगभग 0.15 से 0.20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यानी वैश्विक संकट का असर धीरे-धीरे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगता है।

इसी क्रम में तीसरी बड़ी चुनौती है 'राजकोषीय दबाव'। ऊर्जा, उर्वरक और खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ लगातार सरकारी बजट पर बढ़ रहा है। केवल रासायनिक उर्वरकों के लिए ही वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान था। यदि वैश्विक बाजार में तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ती हैं, तो सरकार के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। नतीजतन विकास योजनाओं, सार्वजनिक निवेश और कल्याणकारी खर्चों में कटौती की नौबत आ सकती है।

लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका प्रभाव केवल भारत पर नहीं पड़ रहा। यह एक व्यापक वैश्विक संकट है, जिसकी पृष्ठभूमि पिछले कई वर्षों से बन रही थी। पहले डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध व तनाव ने दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। इसी कारण यूरोप से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक कई अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुसार, इस वर्ष वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.8 से 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2000 से 2019 के बीच इसका औसत लगभग 3.7 प्रतिशत था। दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है। क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कम समय में वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना आसान नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत फिलहाल आर्थिक मंदी की स्थिति में नहीं है। देश की जीडीपी वृद्धि दर अभी भी छह से सात प्रतिशत के बीच बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार, बाहरी कर्ज, विकास दर और महंगाई नियंत्रण जैसे भारत के व्यापक आर्थिक आधार अभी अपेक्षाकृत स्थिर और मजबूत हैं। लेकिन चिंता यह है कि यदि मौजूदा वैश्विक संकट लंबे समय तक बना रहा, तो आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। भारत का लगभग 690 अरब डालर का विदेशी मुद्रा भंडार निश्चित रूप से एक मजबूत सुरक्षा कवच है, लेकिन वह असीमित नहीं है। इसके साथ ही खाड़ी देश, जो भारत के लिए सबसे बड़ा रेमिटेंस स्रोत हैं, वहां की आर्थिक सुस्ती का असर भारत आने वाले धन पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि अब भारत के आर्थिक ढांचे पर संभावित दबाव को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे 'आर्थिक संवेदनशीलता' कहा जाता है। यानी देश औपचारिक रूप से मंदी में नहीं है, लेकिन बाहरी झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। प्रधानमंत्री की अपीलों को भी इसी व्यापक आर्थिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

अब यदि प्रधानमंत्री की इन अपीलों को राजनीतिक नजरिये से हटकर एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखा जाए, तो इसके पीछे एक स्पष्ट 'मांग प्रबंधन रणनीति' दिखाई देती है। इसका मूल उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू अर्थव्यवस्था और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करना है। सबसे पहले सोने की खरीद में कमी की अपील को समझना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का स्वर्ण आयात बढ़कर लगभग 72 अरब डालर (करीब छह लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक था। आर्थिक दृष्टि से सोना ऐसी संपत्ति है जो न उत्पादन बढ़ाती है, न बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है। इसके विपरीत, सोने पर खर्च होने वाला धन विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

ईंधन बचत की अपील के पीछे भी यही सोच है। भारत प्रतिदिन लगभग 53 लाख बैरल तेल की खपत करता है। यदि सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और ऊर्जा-कुशल वाहनों के उपयोग से इसमें केवल पांच प्रतिशत की कमी आए, तो प्रतिदिन 2.6 लाख बैरल तेल बचाया जा सकता है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से सब्सिडी का बोझ घटेगा। यानी सरकार आयात-आधारित उपभोग को कम करके घरेलू उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचे को दिया जाए विस्तार

आर्थिक इतिहास बताता है कि राष्ट्रों के विकास के दो प्रमुख माडल रहे हैं। पहला माडल 'आयात आधारित उपभोग और तेज विकास' का है। इसमें देश आयातित विदेशी ऊर्जा, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। जब तक वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, यह माडल आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही युद्ध, तेल संकट, व्यापारिक प्रतिबंध या आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आती है, इसकी कमजोरियां सामने आने लगती हैं। दूसरा माडल इससे अलग है। इसमें घरेलू उत्पादन, बचत, निवेश, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को विकास का आधार बनाया जाता है। ऐसे देश शुरुआत में भले धीमे दिखें, लेकिन लंबे समय में अधिक स्थिर और मजबूत बनते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने अलग-अलग रूपों में इसी रणनीति के सहारे अपनी आर्थिक शक्ति विकसित की है।

आज भारत भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। यदि भारत को आने वाले दशकों में वास्तविक आर्थिक शक्ति बनना है, तो उसे आयात-निर्भर उपभोग की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादन-आधारित और आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ दीर्घकालिक तेल एवं गैस समझौतों के माध्यम से परिस्थितियों को काफी हद तक संतुलित किया है। लेकिन अब केवल आपूर्ति स्रोत बदलना पर्याप्त नहीं होगा, देश को अपनी खपत की संरचना भी बदलनी होगी। सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता और ऊर्जा दक्षता को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना होगा।

इसके साथ ही सरकार को नागरिक संयम को ठोस नीतिगत प्रोत्साहनों से जोड़ना होगा। केवल अपीलों से व्यवहार नहीं बदलता, उसके लिए सस्ती, सुविधाजनक और विश्वसनीय व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक वाहन, घरेलू तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और स्थानीय विनिर्माण को व्यापक नीति समर्थन देना होगा। 'मेक इन इंडिया' को अब वास्तविक औद्योगिक परिवर्तन का आधार बनाना होगा। इलेक्ट्रानिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, बैटरी निर्माण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशाल घरेलू क्षमता निर्माण भारत के लिए अनिवार्य हो चुका है। इसके लिए देश को हर हाल में विशाल गीगा फैक्ट्रियों और उच्च क्षमता वाले औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण करना होगा। आज चीन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसकी कम समय में विशाल स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता है। यही क्षमता उसे वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाती है। भारत भी 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए यहां छोटे पैमाने की उत्पादन व्यवस्था लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रह सकती। देश को ऐसे औद्योगिक ढांचे की जरूरत है, जो संकट के समय घरेलू मांग पूरी कर सके और सामान्य समय में वैश्विक बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर सके।

(विक्रांत निर्मला सिंह)

खरी-खरी

दद्दा की इच्छाशक्ति और देशभक्ति

विनोद कुमार विक्की

दद्दा सवा सौ प्रतिशत खांटी देशभक्त हैं। यह और बात है कि सवा चार फीट की लंबाई और 35 किलो की पार्थिव काया के कारण उन्हें सेना में भर्ती होकर सीमा पर देशभक्ति दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए देश के लिए रक्त बहाने का सपना जब अधूरा रह गया, तो उन्होंने देशहित में रक्तदान करने का निश्चय किया। लेकिन अंडरवेट शरीर और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तदान शिविर में दान देने पहुंचे दद्दा को ही डाक्टरों ने दो यूनिट रक्त चढ़ा दिया।

फिर भी दद्दा ने हार नहीं मानी है। देशभक्ति के क्षेत्र में वे निरंतर सक्रिय रहे। राष्ट्रहित में राष्ट्रप्रधान द्वारा दिए गए हर निर्देश का वे अक्षरशः पालन करते हैं। सोने के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं कि दद्दा ने आजीवन एक ग्राम सोना नहीं खरीदा है और अब मृत्यु तक खरीदने का इरादा भी नहीं रखते। हालांकि इसका कारण त्याग नहीं, बल्कि 'सोना खरीदने की औकात' का अभाव है। वैसे दद्दा को सोने से अधिक 'सोने' यानी नींद और सपनों में विश्वास है।

डीजल-पेट्रोल के उपयोग के वे शुरू से विरोधी रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वे वर्षों से पैदल चल रहे हैं। तले-भुने भोजन के प्रति भी उनका दृष्टिकोण अत्यंत सात्विक है। मंदिरों और लंगरों में जो कुछ भी मिल जाए, उसे बिना किसी मीन-मेख के राष्ट्रप्रसाद समझकर वह ग्रहण कर लेते हैं।

वर्क फ्राम होम का प्रचलन भले ही कोरोना काल में बढ़ा हो, लेकिन राजनीति शास्त्र से स्नातक करने के बाद बेरोजगार दद्दा बचपन से ही इसका पालन करते आ रहे हैं। उन्हें कभी किसी आफिस में जाकर किसी बास के अधीन काम करने का दुर्भाग्य नहीं झेलना पड़ा। घर बैठे मोबाइल पर इंटरनेट मीडिया में राष्ट्रहित से जुड़े पोस्ट डालना, मित्रों की पोस्ट पर तीखी टीका-टिप्पणी करना और हर मुद्दे पर विशेषज्ञ राय देना ही उनका कर्मक्षेत्र है।

कुल मिलाकर दद्दा विशुद्ध देशभक्त हैं। देश के लिए उन्होंने भले ही कुछ किया हो या नहीं, लेकिन देशभक्ति पर प्रतिदिन कम-से-कम चार पोस्ट अवश्य करते हैं।

X पोस्ट

नीट प्रश्नपत्र लीक होने से शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा अधिकारियों की जवाबदेही और तैयारियों पर गंभीर सवाल उठते हैं। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। यह लाखों छात्रों के वर्षों के परिश्रम, दबाव, त्याग और आशा का प्रतीक है। छात्रों को एक सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का अधिकार है।
नीतीश राजपूत@nitishrajput

पीएम मोदी ने अपना काफिला दो गाड़ियों तक सीमित कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं। भारत कोई स्विट्जरलैंड नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह सही है कि मोदी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब आदेश जारी करने का समय आ गया है। राज्य सरकारें कुछ उद्योगों को वर्क फ्राम होम के लिए निर्देश दे सकती हैं। हमें निजी ईंधन उपभोग से अधिक उसके वाणिज्यिक उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी।
तुषार गुप्ता@Tushar15

उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मां मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए नियमित रूप से जाती हैं। जो बेटा अपने घर से ही सनातन को बाहर नहीं कर सका, वह उसे पूरे तमिलनाडु से कैसे मिटा सकता है।
एस. गुरुमूर्ति@sgurumurthy

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

देश हित में खींचनी होगी बड़ी लकीर

वैश्विक संघर्ष के हालात में संकेतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने का आह्वान किया, लेकिन यह संदेश निगम-मंडलों में नवनियुक्त पदाधिकारियों के सैकड़ों वाहनों के काफिलों के आगे बेअसर दिखा। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक लगभग 200 गाड़ियों का काफिला लेकर आए। जब किरकिरी हुई तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जोशी और उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ई-रिक्शा से पद संभालने पहुंचे, लेकिन उनके पीछे चल रहे सैकड़ों वाहनों ने जाम लगाया। इसमें संदेह नहीं कि सत्ता और संगठन में इस अपील का व्यापक असर दिखाई पड़े।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की पहल पर अपने काफिले को छोटा करते हुए मंत्रियों से भी यही अपेक्षा की है, लेकिन प्रयासों के दायरे को अधिक विस्तार देना जरूरी है। अपील के बाद पहले कार्यक्रम के लिए निकले डा. मोहन यादव के काफिले में वाहनों की संख्या कम दिखाई दी। कुछ मंत्रियों के लिए भी ऐसे ही दावे सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी अपना कारकेड लौटा दिया। याद रहे कि कोरोना संकटकाल में कैबिनेट की आनलाइन बैठकें सफल थीं।

इस बीच सरकार की पहले से वर्तमान में कैबिनेट की बैठक को पेपरलेस किया जा चुका है। ऐसे में आनलाइन बैठक अधिक सुगम होगी। आनलाइन बैठक पुनः शुरू करने से सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के दर्जनों वाहनों से मंत्रालय पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजधानी भोपाल में मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय सहित तमाम विभागों के मुख्यालय हैं, वहीं जबलपुर और

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्कूटी से (पीछे बैठे) अपने मंत्रालय जाते हुए। फाइल

इंदौर में भी कई मुख्यालयों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं और उनके साथ भी कई गाड़ियां होती हैं। एक ही समय पर मुख्यालय जाने के लिए यदि सरकार किसी बस की व्यवस्था कर दे या कार पूल पर जोर दिया जाए, तो वाहनों में संख्या में कमी आ सकती है।

वाहनों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने करीब 11 हजार किराए की गाड़ियां भी ली हुई हैं। इनसे भी बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल की खपत होती है। सरकार यदि इन वाहनों की संख्या में कमी लाए और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे, तो भी पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के प्रयासों को गति मिल सकती है। मोहन सरकार ने ऐसे प्रयासों को जमीन पर उतार दिया, तो नागरिकों से सरकार की अपेक्षाएं पूरी हो सकेंगी और पेट्रोल की खपत कम करने के जो अनुमान हैं, संभव है कि उससे ज्यादा लक्ष्य प्राप्त भी हो जाए।

वैश्विक हालात देखें तो नरेन्द्र मोदी की अपील स्वेच्छा का विषय नहीं हो सकती है, बल्कि यह नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। युद्ध की स्थिति लंबी चली, तो पेट्रोलियम का संकट भी गहरा सकता है। इसकी कीमत पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ऐसे में अभी से पेट्रोल-डीजल की फिजूलखर्ची रोकने से भविष्य के आसन्न संकट से आसानी से निपटा जा सकेगा। हालांकि पेट्रोल-डीजल की कमी बिलकुल नहीं है, देश में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जहां तक पीएम मोदी की एक अन्य अपील एक वर्ष तक सोना न खरीदने की है तो यह समझना होगा कि आठ हजार टन सोना प्रति वर्ष भारत में आयात किया जाता है। इसका भुगतान डालर में ही होने से बड़ी विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। यह अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान राष्ट्रहित और राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन का विषय है, इसमें राजनीतिक मतभेद और दलों की भिन्नता को गौण रखना होगा। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रहित की बात हो और विश्व में अपनी उपलब्धि के रूप में कोई उदाहरण प्रस्तुत करना हो, तो ऐसे मतभेद मायने नहीं रखते। हमारे देश का इतिहास रहा है कि प्राकृतिक आपदा, संकटकाल, युद्ध और कोरोना जैसी भयावह स्थिति में भी हमने एकता का परिचय दिया है। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा रहा है। यदि हम समय रहते इस एकता को नया आयाम देंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले संकट से जूझने के बजाय पहले ही उबर जाएंगे। यही दृष्टिकोण विश्व में भारत की अलग पहचान बनाएगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या नीट पेपर रद होना शिक्षा मंत्रालय की छवि को भी चोट पहुंचाने वाला है?

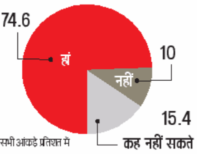

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने से उनकी मांग में कमी देखने को मिलेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

रस्सी आधी जल गई किंतु गई ना ऐंठ,
चोट सनातन पर करें उदय सदन में बैठ।
उदय सदन में बैठ अभी सरकार गंवाई,
हार गया है बाप सीट तक बच ना पाई।
करो सनातन संग उदयनिधि रस्साकस्सी,
पक्का अगली बार जलेगी पूरी रस्सी!
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विवि

डालर से डगमगाता भरोसा

इस सदी के आरंभ से अमेरिकी डालर की महत्ता घट रही है। हाल के दशक में वैश्विक लेनदेन में डालर की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। यानी डालर के प्रति वैश्विक भरोसा कम हो रहा है

सऊदी अरब अब डालर के साथ-साथ अन्य करेंसियों में भी तेल का व्यापार करेगा। यह वैश्विक आर्थिक जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक आश्चर्यजनक खबर भी थी। दरअसल पिछले कई दशकों से दुनिया के तेल व्यापार में डालर का प्रभुत्व बना हुआ है और अभी विश्व के कुल तेल व्यापार का 80 प्रतिशत डालर के माध्यम से होता रहा है। वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद, 1974 के मध्य में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आगामी 50 वर्षों के लिए एक रणनीतिक समझ बनी कि सऊदी अरब तेल की कीमत डालर में तय करेगा। वह तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई को अमेरिकी संपत्तियों (जैसे ट्रेजरी बांड इत्यादि) में निवेश करेगा। इसके बदले में अमेरिका ने उसे सैन्य सहायता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। वर्ष 2024 में उस समझ या यूं कहें तो समझौते की अवधि की समाप्ति होने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने उस समझौते का नवीनीकरण नहीं किया, जिस कारण सऊदी अरब अब स्थानीय करेंसियों में तेल बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है, और उसके लिए चीनी युआन, जापानी येन और भारतीय रुपये सहित कई अन्य करेंसियों में तेल का व्यापार करने के मार्ग खुला है।

गौरतलब है कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब का 50 वर्ष का वह समझौता उस समय समाप्त हुआ, जब ब्रिक्स देश डालर के स्थान पर स्थानीय करेंसियों को वरीयता देने की ओर प्रयास कर रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलनों में रूस और चीन सहित कुछ देश अब डी-डालराईजेशन की बात करने लगे हैं। विश्व में, पिछले लंबे समय से अमेरिकी डालर का प्रभुत्व कम होने के संकेत मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले दो

प्रतीकात्मक

वर्षों में डालर पर दुनिया का विश्वास कुछ अधिक तेजी से डगमगाया है। हालांकि आज भी डालर दुनिया के लिए प्राथमिक करेंसी के रूप में कायम है, लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया डालर से लगातार विमुख हो रही है।

आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया के 90 प्रतिशत विदेशी मुद्रा लेनदेन डालर में होते हैं और 54 प्रतिशत वैश्विक निर्यात के बिल डालर में व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन डालर जिसकी वैश्विक रिजर्व करेंसी में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में लगभग 72 प्रतिशत होती थी, यूरो के प्रादुर्भाव के चलते वर्ष 2010 तक वह 61 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, और 2019 तक यह उसी स्तर पर बनी रही। लेकिन वर्ष 2020 से यह निरंतर घटती जा रही है और वर्ष 2023 में डालर का वैश्विक रिजर्व करेंसी में योगदान घटकर 58 प्रतिशत और 2025 में 56.3 प्रतिशत तक पहुंच गया, और यह घटता ही जा रहा है।

इस बात को समझने की जरूरत है कि डालर पर दुनिया का विश्वास पूर्व की तुलना में क्यों डगमगाया हुआ है? क्यों अब दुनिया के देश डालर को त्याग अन्य करेंसियों को वरीयता देने लगे हैं? इसको समझने के लिए हमें वैश्विक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम, अमेरिका द्वारा वित्त के हथियारीकरण के कारण दुनिया भर का अमेरिकी प्रशासन पर विश्वास कमजोर हुआ है। अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और विदेशी (रूसी) रिजर्व परिसंपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया ने एक प्रकार से खतरे की घंटी जैसा काम किया और विरोधी एवं सहयोगी दोनों देशों को ऐसा लगने लगा कि डालर आधारित व्यवस्था कोई तटस्थ व्यवस्था नहीं है और अमेरिका द्वारा उसे हथियार के रूप में कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिन पूर्व फ्रांस द्वारा अमेरिका के पास रखे अपने सोने के भंडार को वापस स्वदेश लाने का निर्णय भी इसी अविश्वास का परिणाम है।

दूसरे, अमेरिकी राजकोष जिसमें पहले काफी स्थायित्व रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिकी सरकार का कर्ज लगातार बढ़ते हुए 35 खरब (ट्रिलियन) डालर तक पहुंच गया है, जो उसकी जीडीपी का 122.6 प्रतिशत है। इसलिए भी दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में डालर की स्वीकार्यता घट रही है। तीसरे, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्वायतत्ता के चलते डालर के स्थायित्व पर दुनियाभर का विश्वास था। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन द्वारा फेडरल रिजर्व की स्वायतत्ता को लगातार चुनौती दी जा रही है, जिसके चलते फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। दुनियाभर के आर्थिक विशेषज्ञ इस वजह से भी डालर की प्रतिष्ठा गिरने की बात प्रमुखता से कर रहे हैं।

अब देशों के केंद्रीय बैंक डालर के बजाय सोने में भी रिजर्व रखने लगे हैं। उदाहरण के लिए 2010 में चीन के रिजर्व में सोना मात्र एक से 1.5 प्रतिशत ही होता था, आज चीन के विदेशी मुद्रा रिजर्व में सोने का हिस्सा सात प्रतिशत पहुंच चुका है। भारत में भी सोने का हिस्सा 2010 में मात्र छह से सात प्रतिशत था, जो अभी तक 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुनिया में एक ओर जहां डालर का प्रभुत्व कम हो रहा है, वहीं दुनिया एक ध्रुवीय प्रणाली से बदलकर बहुध्रुवीय होती जा रही है। डालर के महत्व की कमी अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया के कारण हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका आज एकमात्र बड़ी महाशक्ति नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है। बहुध्रुवीय प्रणाली अब एक वास्तविकता बन चुकी है।

दैनिक जागरण धूम धड़ाका आइपीएल 19
www.jagran.com गुरुवार 14 मई, 2026

बल्लेबाज	रन
हेनरिक क्लासेन	508
साई सुदर्शन	501
अभिषेक शर्मा	481

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	22
कैगिसो रबादा	21
अंशुल कंबोज	19

रघुवंशी के साथ रिंकू ने जमाया रंग

केकेआर ने गत चैंपियन आरसीबी को दिया 193 रन का लक्ष्य, अंगकृष रघुवंशी ने जड़ा अर्धशतक

आरसीबी के विरुद्ध मुकाबले में पारी के दौरान शाट खेलते केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ● एएफपी

स्कोर बोर्ड

टास: रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (गेंदबाजी)

कोलकाता नाइट राइडर्स: 192/4 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रहाणे का. एंड बो. हेजलवुड	19	13	3/1
एलन का. जितेश बो. भुवनेश्वर	18	8	3/1
अंगकृष रन आउट	71	46	7/3
ग्रीन बो. रासिख	32	24	3/1
रिंकू अविजित	49	29	3/2

अतिरिक्त : 3 (नोबा : 1, वा : 2)

विकेटपतन : 1-23 (एलन, 2.3), 2-48 (रहाणे, 4.4), 3-116 (ग्रीन, 12.2), 4-192 (अंगकृष, 19.6)

गेंदबाजी : भुवनेश्वर 4-0-34-1, डफी 4-0-48-0, हेजलवुड 4-0-35-1, रासिख 4-0-35-1, क्रुणाल 4-0-39-0

	अंक तालिका	मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	गुजरात	12	8	4	0	+0.551	16
2	आरसीबी	11	7	4	0	+1.103	14
3	हैदराबाद	12	7	5	0	+0.331	14
4	पंजाब	11	6	4	1	+0.428	13
5	चेन्नई	11	6	5	0	+0.185	12
6	राजस्थान	11	6	5	0	+0.082	12
7	दिल्ली	12	5	7	0	-0.993	10
8	कोलकाता	10	4	5	1	-0.169	9
9	मुंबई (E)	11	3	8	0	-0.585	6
10	लखनऊ (E)	11	3	8	0	-0.907	6

33 विकेट भुवनेश्वर ने केकेआर के विरुद्ध लिए हैं। वह सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चहल (33) के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि : वर्षा रुकने के बाद करीब एक घंटा 45 मिनट देरी से शुरू हुए मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की चुनौतीपूर्ण पिच पर संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विरुद्ध 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसी मैदान पर हाल ही में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच लो-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस बार पिच अलग जरूर थी, लेकिन फिर भी 192 का स्कोर औसत से काफी ऊपर नजर आ रहा है।

बारिश और गीले आउटफील्ड के कारण मुकाबला एक घंटे से अधिक देर से शुरू हुआ। टास जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पिच पर तेज गेंदबाजों को वैसी मदद नहीं मिली जैसी इसी मैदान पर पिछले मैच में देखने को मिली थी। केकेआर की शुरुआत आक्रामक रही। कप्तान अजिंक्य रहाणे (19) और फिन एलन (18) ने शुरुआती ओवरों में तेजी से रन जुटाए, लेकिन दोनों पावरप्ले के भीतर ही आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने एलन को विकेट के पीछे कैच कराया, जबकि जोश हेजलवुड ने रहाणे को शार्ट गेंद पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नंबर तीन पर उतरे अंगकृष रघुवंशी ने पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 21 वर्षीय बल्लेबाज ने 46 गेंदों में 71 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे। उन्होंने पहले कैमरन ग्रीन (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े और फिर रिंकू सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 76 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रघुवंशी पूरे मैच में शानदार लय में नजर आए। उन्होंने आफ साइड में बेहतरीन कट शाट लगाए, जबकि मिडविकेट के ऊपर खेला गया उनका शार्ट-आर्म पुल और क्रुणाल पांड्या पर लगाया गया लंबा छक्का दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम गेंद पर रन आउट होने से पहले उन्होंने टीम को बड़े स्कोर की नींव दे दी थी। कैमरन ग्रीन ने भी 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। वहीं रिंकू सिंह एक बार फिर फिनिशर की भूमिका में नजर आए और 29 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए। वह केवल एक रन से अपना अर्धशतक चूक गए। रिंकू ने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए।

आरसीबी की फील्डिंग इस मुकाबले में बेहद साधारण रही। टीम ने कई मिसफील्ड किए और गेंदबाज भी अपनी लाइन-लेंथ में निरंतरता नहीं रख सके। खासकर डेथ ओवरों में आरसीबी के गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह विफल रहे, जिसका फायदा केकेआर के बल्लेबाजों ने जमकर उठाया।

अर्श से फर्श पर पहुंची पंजाब किंग्स

- मुंबई इंडियंस के विरुद्ध धर्मशाला में आज होगा मुकाबला
- एक और हार प्लेऑफ की दौड़ कर देगी मुश्किल

दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध मुकाबले के दौरान पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ● प्रेट्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : दो सप्ताह पहले तक पंजाब किंग्स आइपीएल 2026 की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम नजर आ रही थी। सात मैचों में छह जीत, शानदार नेट रनरेट और आत्मविश्वास से भरी टीम को देखकर लग रहा था कि प्लेआफ में उसकी जगह लगभग तय है, लेकिन क्रिकेट में लय जितनी तेजी से बनती है, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी जाती है। पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। लगातार चार हार ने टीम को अंक तालिका में शीर्ष से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है और अब प्लेआफ की राह भी मुश्किल होती दिख रही है। गुरुवार को पंजाब की टीम का सामना धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस से होगा। अगर पंजाब को प्लेआफ की उम्मीदों को पुख्ता करना है तो उसे हर हाल में जीत चाहिए होगी, लेकिन पिछले चार मुकाबलों में श्रेयस अय्यर की टीम का प्रदर्शन देखें तो उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है।

दरअसल, पंजाब किंग्स की गिरावट केवल हार तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम के खेल में कई गंभीर कमियां सामने आई हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों के दौरान सबसे बड़ी समस्या फील्डिंग रही है। पूरे सत्र में पंजाब ने 19 कैच छोड़े हैं, जो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध भी टीम ने आसान मौके गंवाए, जिसका सीधा असर नतीजे पर पड़ा। 71.43 प्रतिशत का कैच सफलता प्रतिशत इस बात का संकेत है कि दबाव के क्षणों में टीम बिखर रही है।

दिल्ली कैपिटल्स के पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी हार के बाद साफ कहा कि पिछले मैचों में गेंदबाजी और फील्डिंग ने टीम को निराश किया। गेंदबाजी में भी पंजाब की धार कमजोर पड़ती दिख रही है। राजस्थान रायल्स के विरुद्ध 222 रन बचाने में नाकामी, गुजरात टाइटंस के सामने केवल 163 रन बनाना और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 235 रन लुटाना बताता है कि गेंदबाज दबाव संभाल नहीं पा रहे। धर्मशाला में दिल्ली के खिलाफ 210 रन बनाने के बावजूद हार जाना इसी कमजोरी का ताजा उदाहरण है। सबसे हैरान करने वाला फैसला युजवेंद्र सिंह चहल का सीमित इस्तेमाल करना रहा। आइपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज को धर्मशाला की सीमिंग पिच पर लगभग नजरअंदाज किया गया। टीम प्रबंधन ने इसे रणनीतिक फैसला बताया, लेकिन जब तेज गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाए तो यह दांव उल्टा पड़ गया।

हालांकि पंजाब के लिए उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। टीम के पास अब भी 13 अंक हैं और तीन मुकाबले बाकी हैं और दो जीत उसे प्लेआफ में पहुंचा देगी। पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानसिक मजबूती की है। शुरुआती सफलता के बाद टीम शायद थोड़ी सहज हो गई, जबकि अब दबाव बढ़ते ही गलतियां बढ़ रही हैं। यदि पंजाब को प्लेआफ में जगह बनानी है तो उसे फील्डिंग में सुधार, गेंदबाजों की स्पष्ट भूमिका और दबाव में बेहतर फैसले लेने होंगे। वरना शानदार शुरुआत के बावजूद यह सीजन अधूरी कहानी बन सकता है।

टीम में नहीं चल रहा है सबकुछ ठीक : लगातार चार हार के बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीम में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच कुछ तल्खियां बढ़ी हैं। सूत्रों के अनुसार, कैच ड्राप करने वाले एक खिलाड़ी पर ब्लाग बनाने पर एयरपोर्ट पर दो सीनियर खिलाड़ियों के बीच बहस हुई थी।

वर्षा बिगाड़ सकती है पंजाब का खेल

धर्मशाला में बुधवार की शाम तेज हवाओं के साथ वर्षा शुरू हो गई। इस वजह से पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को अभ्यास रोकना पड़ा। गुरुवार को भी मौसम विभाग ने तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अगर धर्मशाला में वीरवार को वर्षा की वजह से मैच न हुआ तो उसे बचे हुए दोनों मैच में लगातार जीत दर्ज करनी होगी जिससे उस पर दबाव और बढ़ेगा।

खेल डायरी

भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने जीते दो पदक

ज्ञानेश्वरी यादव ● साई

गांधीनगर, प्रेट्र : भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने बुधवार को 2026 एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 53 किग्रा वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच वर्ग में रजत और फिर इसी स्पर्धा में कुल 194 किग्रा का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। चीन की जिनलान झाओ ने कुल 216 किग्रा भार उठाकर इस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि वियतनाम की होआई हुओंग गुयेन को कुल 195 किग्रा वजन उठाने पर रजत पदक मिला। कोमल कोहर ने सोमवार को महिलाओं की 48 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोला था।

पेगुला को हराकर स्वियातेक सेमीफाइनल में

इगा स्वियातेक ● रायटर

रोम, एपी : तीन बार की चैंपियन इगा स्वियातेक ने बुधवार को अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। विश्व रैंकिंग में स्वियातेक चौथे और पेगुला उनसे एक स्थान नीचे पांचवें नंबर पर थीं, लेकिन मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच बड़ा अंतर नजर आया। पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ने सिर्फ 67 मिनट में 6-1, 6-2 से जीत दर्ज की। स्वियातेक का शानदार फार्म आगामी फ्रेंच ओपन से पहले उनके लिए अच्छे संकेत माना जा रहा है। वह इस ग्रैंड स्लैम को चार बार जीत चुकी हैं। अब सेमीफाइनल में उनका सामना एलेना रिबाकिना या एलिना स्वितोलिना से होगा।

मोहनबगान के पूर्व अध्यक्ष बोस का निधन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : मोहन बगान के पूर्व अध्यक्ष स्वपन साधन बोस, जिन्हें कोलकाता के फुटबाल हलकों में प्यार से 'टुटु बाबू' कहा जाता था, का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। भारतीय फुटबाल प्रशासन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रहे बोस का कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11.45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

जसप्रीत बुमराह ● फाइल फोटो

दुबई, प्रेट्र : भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआई जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को जारी आइसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः आठवें और नौवें स्थान पर हैं जबकि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट 880 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। यशस्वी के 750 अंक हैं। गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उनके 730 अंक हैं। हैरी ब्रूक इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं जबकि उनके बाद आस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का नंबर आता है। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है।

टीम ने अपनी पिछली सीरीज स्वदेश में नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेली थी। गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर चल रहे बुमराह के 879 अंक हैं। सूची में अगला सर्वश्रेष्ठ भारतीय मोहम्मद सिराज हैं जो 12वें पायदान पर हैं। रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर हैं।

आलराउंडर ओवरटन चोट की जांच के लिए घर लौटे

आइपीएल डायरी

मैकनील नोरोन्हा

चेन्नई, प्रेट्र : चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को घोषणा की कि उनके आलराउंडर जेमी ओवरटन दाहिनी जांघ की चोट का आकलन कराने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर ब्रिटेन लौट रहे हैं। ओवरटन ने आइपीएल 2026 में पांच बार की चैंपियन सीएसके के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 10 मैचों में 14 विकेट लेने के साथ 136 रन भी बनाए हैं। सीएसके ने इंटरनेट मीडिया पर कहा कि ओवरटन को दाहिनी जांघ में चोट लगी है और आगे की जांच तथा उपचार के लिए वह ब्रिटेन लौट रहे हैं। 32 वर्षीय इंग्लैंड के इस आलराउंडर की चोट उन खिलाड़ियों की लंबी सूची में नया नाम है, जो या तो बीच सीजन में बाहर हो गए हैं या फिर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके हैं। वहीं, बुधवार को ही सीएसके ने चोटिल महाराष्ट्र के आलराउंडर रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के आलराउंडर मैकनील नोरोंहा को टीम में शामिल करने की घोषणा की थी।

गुजरात ने सनराइजर्स को चारों खाने चित किया : विटोरी

अहमदाबाद, प्रेट्र : सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्वीकार किया कि यहां खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस की मजबूत टीम ने अपने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन से उनकी टीम को चारों खाने चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साई सुदर्शन (61) और वाशिंगटन सुंदर (50) के अर्धशतकों की बदौलत गुजरात ने पांच विकेट पर 168 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स की टीम 86 रन पर आउट हो गई। गुजरात की तरफ से कैगिसो रबादा और जेसन होल्डर ने तीन-तीन जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दो और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया। विटोरी ने कहा कि गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन वास्तव में शानदार रहा। उन्होंने गेंदबाजी में हम पर दबाव बनाया। उनके बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हम जानते थे कि हमें उनकी मजबूत गेंदबाजी का सामना करना है। पांच तेज गेंदबाजों के साथ राशिद का सामना करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि हमें वैसी शुरुआत नहीं मिली जैसी हम चाहते थे और उन्होंने इसका फायदा उठाया। उनकी गेंदबाजी शानदार थी। विटोरी ने कहा कि गुजरात की टीम मजबूत है और उनके खेलने की एक अलग शैली है जिसे वे जरूरत पड़ने पर अपना सकते हैं। हमारे लिए मुख्य चुनौती उनके गेंदबाजों का सामना करना था और उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। गुजरात के स्पिनर साई किशोर ने पावरप्ले में रबादा और सिराज के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की।

श्रीकांत, सिंधू व लक्ष्य दूसरे दौर में पहुंचे

पीवी सिंधू ● बैडमिंटन फोटो

बैंकाक, प्रेट्र : स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में बुधवार को सीधे गेम में जीत दर्ज करके दूसरे दौर में पहुंच गए, जबकि इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिन मिश्रित सफलता वाला रहा।

महिला सिंगल्स में दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता सिंधू ने चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग को 21-9 21-12 से हराया, जबकि सातवें वरीय और आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दो बार के फाइनलिस्ट लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को 21-16 21-17 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत ने सिंगापुर के आठवीं वरीयता प्राप्त लो कीन यू को 21-14, 21-15 से हराकर उलटफेर किया। श्रीकांत का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपै के सू लि यांग से होगा, जबकि सिंधू डेनमार्क की अमेली शूल्ज से खेलेंगी। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता थामस कप के दौरान लगी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। वह चीनी ताइपे के वांग पो वेई और चीन के झू शुआन चेन के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेंगे। वहीं, एक अन्य मैच में मालविका बंसोड़ ने कनाडा की वेन यू झेंग को 13-21 26-24 21-13 से हराया, लेकिन तन्वी शर्मा को जापान की हीना अकेची के विरुद्ध 17-21 8-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

विदेशी कोच के लिए मुझे हटाया गया : श्रीजेश

पीआर श्रीजेश, एक्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने विदेशी कोचों को तरजीह देने के हाकी इंडिया के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद जूनियर टीम के कोच के पद से उन्हें हटा दिया गया।

इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को एक पोस्ट में दो बार के ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता श्रीजेश ने लिखा कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें हटाया गया, क्योंकि हाकी इंडिया जूनियर स्तर पर भी विदेशी कोच चाहता है। श्रीजेश ने एक्स पर लिखा कि लगता है कि मेरा कोचिंग करियर डेढ साल के बाद ही खत्म हो गया है जिसमें हमने पांच टूर्नामेंट खेले और जूनियर विश्व कप समेत पांच बार पोडियम पर रहे। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि खराब प्रदर्शन के बाद कोचों को हटाया जाता है लेकिन पहली बार विदेशी कोच की नियुक्ति के लिए मुझे हटाया जा रहा है। श्रीजेश ने कहा कि हाकी इंडिया अध्यक्ष का कहना है कि सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच जूनियर स्तर पर भी विदेशी कोच चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे जूनियर स्तर से सीनियर स्तर पर भारतीय हाकी के विकास में मदद मिलेगी।

इस बीच, हाकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने पीआर श्रीजेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें पद से हटाया नहीं गया है बल्कि उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में ही खत्म हो गया था और उचित चयन प्रक्रिया का पालन करके मेरिट के आधार पर नया कोच चुना गया है।

2027-28 सीजन की शुरुआत मोंटजूइक स्टेडियम से कर सकता है बार्सिलोना

मोटजूइक स्टेडियम ● फाइल फोटो

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : हाल ही में 29वीं बार स्पेनिश फुटबाल लीग ला लीगा का खिताब जीतने वाला बार्सिलोना अपने ऐतिहासिक स्टेडियम कैंप नोउ के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसी वजह से क्लब ने एहतियातन 2027-28 सत्र के शुरुआती हिस्से के लिए एस्तादी ओलिंपिक लुइस कंपनीस (मोंटजूइक स्टेडियम) के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बार्सिलोना ने यह अनुरोध बार्सिलोना सिटी काउंसिल को भेज दिया है। क्लब को आशंका है कि कैंप नोउ का पुनर्निमाण तय समय से अधिक तक खिंच सकता है। इस स्टेडियम में छत लगाने का कार्य 2027 की गर्मियों में शुरू होने की संभावना है। एक आकलन के अनुसार, स्टेडियम की नई छत लगाने की प्रक्रिया पूरी होने में चार से पांच महीने लग सकते और इसका सीधा असर 2027-28 सत्र की शुरुआत पर पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआती महीनों में बार्सिलोना के लिए कैंप नोउ में घरेलू मैच आयोजित करना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण क्लब पहले से वैकल्पिक योजना तैयार कर रहा है। हालांकि क्लब ने साफ किया है कि मोंटजूइक स्टेडियम का विकल्प केवल बैकअप योजना है और अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बार्सिलोना अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इनमें एस्तादी जोहान क्रूइफ स्टेडियम का विस्तार भी शामिल है। वर्तमान में इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 6000 दर्शकों की है और इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस योजना पर करीब 1.4 करोड़ यूरो (लगभग 156 करोड़ रुपये) खर्च होने का अनुमान है।

अंतिम पलों में आत्मघाती गोल ने बढ़ाया रोनाल्डो का खिताबी इंतजार

फुटबाल डायरी

अल हिलाल के विरुद्ध मैच के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ● एएफपी

वाशिंगटन, एपी : क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी प्रो लीग का अपना पहला खिताब जीतने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को अल नस्त्र और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अंतिम क्षणों में हुए आत्मघाती गोल ने अल नस्त्र की जीत छीन ली और मुकाबला 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। अल नस्त्र जीत से कुछ ही सेकेंड दूर था और आठ मिनट के अतिरिक्त समय का अंतिम क्षण चल रहा था और टीम 1-0 से आगे थी। रोनाल्डो उस समय बेंच पर बैठे बेहद तनाव में नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें पहले ही बदला जा चुका था। तभी अल हिलाल ने लंबा थ्रो बाक्स में डाला और अल-नस्त्र के गोलकीपर बेंटो गेंद को पकड़ने की कोशिश में उसे अपने ही गोल में धकेल बैठे।

गोल होते ही अल-हिलाल को बराबरी मिल गई और अल-नस्त्र की खिताब जीतने की उम्मीदें टल गईं। मुकाबले के बाद रोनाल्डो काफी निराश दिखे और टीम के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सांत्वना दी। पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी ने एक्स पर लिखा, सपना अब बहुत करीब है। सिर ऊंचा रखो, अभी एक कदम और बाकी है। अल नस्त्र ने आखिरी बार 2019 में सऊदी लीग का खिताब जीता था। रोनाल्डो 2022 में क्लब से जुड़े थे और उनके आने के बाद सऊदी फुटबाल को वैश्विक पहचान मिली। इसके बावजूद टीम अब तक लीग ट्राफी नहीं जीत सकी है। टीम अगर 21 मई को दमाक को हरा देती है तो खिताब उसके नाम हो जाएगा। वहीं अल-हिलाल के अभी दो मैच बाकी हैं और उसे उम्मीदें जिंदा रखने के लिए दोनों जीतने होंगे।

20 साल बाद चैंपियंस लीग में लौटा रीयल बेटिस

मैड्रिड : स्पेनिश फुटबाल क्लब रीयल बेटिस ने 20 साल बाद यूएफा चैंपियंस लीग में वापसी का टिकट हासिल कर लिया। बेटिस ने मंगलवार को स्पेनिश लीग ला लीगा में एल्चे को 2-1 से हराकर अंक तालिका में पांचवां स्थान पक्का किया, जो अगले सत्र की चैंपियंस लीग के लिए अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान था। रीयल बेटिस ने इससे पहले 2005-06 सत्र में चैंपियंस लीग में हिस्सा लिया था। बेटिस की ओर से कुचो हर्नांडिज ने नौवें मिनट में टीम को बढ़त दिलाई। एल्चे ने हेक्टर फोर्ट के गोल की बदौलत हाफ टाइम से पहले बराबरी कर ली, लेकिन पाब्लो फोर्नाल्स ने 68वें मिनट में विजयी गोल दागकर बेटिस की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कर दी। अन्य मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने ओसासुना को 2-1 से पराजित किया।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दैनिक जागरण **सप्तरंग**

तकनीक की दुनिया का

गुरुवार, 14 मई, 2026

फोटो : मैग्निफिक

इन दिनों

गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। उचित देखभाल नहीं होने, इलेक्ट्रिकल खामियों, अत्यधिक प्रयोग, ओवरहीटिंग और पावर सप्लाई की गड़बड़ी के चलते घरों और कार्यालयों में लगे एसी अक्सर दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। एसी के रखरखाव और इनके प्रयोग के सही तरीकों के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र

क्यों लगती है एसी में आग!

दिल्ली के विवेक विहार और फिर ग्रेटर नोएडा में एसी से आग लगने की घटना बीते दिनों चर्चा में रही। ऐसे में सवाल उठता है कि घरों में लगे उपकरण कैसे और किन किन कारणों से खतरनाक रूप ले लेते हैं, क्या है इनके रखरखाव का सही तरीका, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं न हों। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा, गर्मी और लू के चलते ऐसे उपकरणों के प्रयोग और बिजली की खपत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। बेशक तेज गर्मी में सबसे सुरक्षित जगह एसी युक्त कमरा ही है, लेकिन यह तभी तक सुरक्षित है जब तक आप उसे सही ढंग से मेंटेन करते हैं। घरेलू उपकरणों के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे का रूप ले सकती है।

दिल्ली में एसी में शार्ट सर्किट होने के चलते आग लगी थी, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई। हर साल, एसी यूनिट्स में आग लगने या उसके फटने की खबरें आती हैं। थोड़ी सी भी सतर्कता बरती जाए तो इन्हें आसानी से टाला जा सकता है। ज्यादातर मामलों में तकनीकी कारण ही जिम्मेदार होते हैं। खास बात है कि ये घटनाएं अचानक नहीं होतीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के कारण अचानक दुर्घटना का रूप लेती हैं।

एसी खराब होने के संकेत

बिजली से जुड़ीं समस्याएं : तारों के घिस जाने, कनेक्शन ढीले होने या पुराने पुर्जों के कारण एसी ट्रिप करने लगता है। इसे लगातार नजरअंदाज करने के कारण लोड बढ़ता है और वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने पर चिंगारी निकलती है।

ओवरहीटिंग : एसी लगातार कई घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब अनियंत्रित प्रयोग नहीं होता। बिना ब्रेक लिए लगातार एसी चलाने पर कंप्रेसर और अंदरूनी वायरिंग पर दबाव बढ़ता है। इन्हीं कारणों से एसी के फटने जैसी दुर्घटनाएं होती हैं।

गैस का लीक होना : अगर एसी पर्याप्त ठंडा नहीं कर रहा है तो संभव है कि रेफ्रिजरेंट में लीकेज हो रहा हो। गैस के लीकेज होने से कंप्रेसर का तापमान बढ़ सकता है। एसी की गैस में थोड़ी सी चिंगारी लगी तो वह भयंकर आग का रूप ले सकती है।

कंडेंसर काइल और फिल्टर : अगर आप धूलधुएं वाले इलाके में रहते हैं तो एसी के काइल और फिल्टर में बार बार धूल जमा होने की समस्या हो सकती है। फिल्टर के अवरुद्ध होने पर गर्मी और हवा के बहाव में रुकावट आती है। इससे एसी यूनिट पर दबाव बढ़ता है, जिससे वह गर्म हो जाता है और हादसे का कारण बन सकता है।

पर्याप्त मरम्मत नहीं होना : एसी में कोई भी समस्या आए तो उसकी मरम्मत हमेशा प्रशिक्षित तकनीशियन से ही करानी चाहिए। इसी तरह एसी के अंदरूनी पुर्जे की क्वालिटी अगर ठीक नहीं होगी, तो उससे भी एसी का दबाव बढ़ेगा या उसके फटने की आशंका अधिक रहेगी।

आग लगने के क्या हैं चेतावनी संकेत

एसी से गर्म हवा : अगर एसी से गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब है कि मशीन गर्म हो गई है या फिर उसमें कोई गंभीर तकनीकी समस्या आ रही है।

स्पार्क : अगर एसी आन करने पर स्पार्क या लाइट फ्लिकरिंग होती है तो यह शार्ट सर्किट या वायरिंग की समस्या के कारण हो सकती है।

असामान्य आवाज : आन करने पर एसी से अलग-अलग तरह की आवाज आना इलेक्ट्रिक या मशीन की खराबी का संकेत है।

धुआं निकलना : एसी से धुआं निकलना सबसे गंभीर चेतावनी है। ऐसी स्थिति में एसी को तुरंत बंद कर देना चाहिए और तकनीशियन को दिखाना चाहिए।

आन-आफ होना : अगर एसी बार-बार आन या आफ हो रहा है तो ओवरहीटिंग या फंक्शनिंग में आ रही खराबी के कारण हो सकता है।

जलने की गंध : एसी से जलने की गंध आ रही है तो यह ओवरहीटिंग या तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है।

खतरों से बचने के जरूरी उपाय

फिल्टर को साफ रखें : एसी के एयर फिल्टर को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसके अवरुद्ध होने से कूलिंग पर असर पड़ता है और एसी के अधिक गर्म होने का खतरा भी बढ़ता है।

वेंटिलेशन का ध्यान : आउटडोर यूनिट में हवा आने-जाने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इसे खुली जगह पर लगाएं, जहां से गर्मी आसानी से बाहर निकल सके।

नान स्टाप प्रयोग से बचें : एसी को लगातार चलाने के बजाय हर कुछ घंटों में थोड़ी देर के लिए बंद कर दें या टाइमर का इस्तेमाल करें। इससे एसी की लाइफ भी बढ़ती है।

वोल्टेज स्टेब्लाइजर : यह बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करता है और अचानक वोल्टेज में होने वाले बदलावों से एसी को बचाता है।

सर्विसिंग कराएं : एसी को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है नियमित सर्विसिंग। गर्मी से पहले और गर्मियों के दौरान अच्छे प्रोफेशनल से गैस लीकेज, खराब पुर्जों या खराब वायरिंग जैसी समस्याओं की जांच कराना और उसे ठीक कराना आवश्यक है।

क्या है एसी के प्रयोग का सही तरीका

- हर 2-3 हफ्ते में एसी के फिल्टर को साफ करते रहें।
- एसी को बहुत कम तापमान (जैसे 16-18 डिग्री सेल्सियस) चलाने के बजाय 24-26 डिग्री सेल्सियस पर रखें। इससे ऊर्जा की भी बचत होगी
- कमरे को अच्छी तरह सील रखें। अगर ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी, तो एयर कंडीशनर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
- आउटडोर यूनिट को धूल और धूप से बचाएं, क्योंकि यह पूरे सिस्टम का अहम हिस्सा होता है।

अच्छी तरह मेंटेन एयर कंडीशनर 10 से 15 साल तक चलता है। मशीन पुरानी होने से एफिशिएंसी कम होती जाती है और खराब होने की आंशका बढ़ जाती है। अगर समस्याएं दिखने लगें, तो नया एयर कंडीशनर लेने पर विचार करना चाहिए।

एसी में खराबी होने पर क्या करें

- सुरक्षा प्राथमिकता में रखें।
- खराबी के किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें।
- एसी को तुरंत बंद कर दें और उसे अनप्लग करें।
- दोबारा प्रयोग करने से पहले तकनीशियन से जांच अवश्य कराएं।

टेक टिप्स

नकली फोन एक्सेसरीज से बचने का सही तरीका

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों के मुताबिक मशीनों की मदद से वनप्लस, ओप्पो और स्थिलमी जैसे ब्रांड के नाम गैर-कानूनी तरीके से नकली उत्पाद बनाकर उनकी पैकेजिंग की जा रही थी। अगर आप स्मार्टफोन, ईयरबड्स, चार्जर, पावरबैंक ले रहे हैं तो सही व गलत के बीच फर्क समझना जरूरी है...

नकली फोन/ईयरफोन की कैसे करें पहचान

पैकेजिंग देखें : अक्सर नकली प्रोडक्ट की पैकेजिंग में ही कई सारी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, जैसे स्पेलिंग की गलतियां, धुंधले लोगो, खराब प्रिंट क्वालिटी आदि।

सीरियल नंबर जांचें : आजकल कई सारे ब्रांड क्यूआर कोड, आइएमईआइ वेरिफिकेशन या सीरियल-नंबर लुकअप टूल के जरिये प्रोडक्ट को जांचने की सुविधा देते हैं।

वारंटी चेक करें : नकली डिवाइस और एक्सेसरीज में आफिशियल वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता।

कीमतों से सतर्कता : अगर कोई प्रोडक्ट आपको अविश्वसनीय तौर पर काफी कम कीमत पर मिल रहा है तो वह संदिग्ध हो सकता है। इसे दो-तीन स्रोत से जांचना चाहिए।

आफिशियल स्टोर या ई-कामर्स साइट से खरीदें : आफिशियल स्टोर, वेरिफाइड मार्केटप्लेस लिस्टिंग से प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। अनजान थर्ड-पार्टी विक्रेताओं से बचना चाहिए।

प्रोडक्ट को रिपोर्ट करें : नकली प्रोडक्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रिव्यू लिखकर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं।

टेक अपडेट

एआइ से और स्मार्ट हुआ लैपटाप

चाहे पढ़ाई हो, आफिस वर्क, वीडियो काल या कंटेंट क्रिएशन हो, एआइ अब हर जगह आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं लैपटाप के एआइ फीचर्स और उपयोग के बारे में...

मोबाइल के बाद लैपटाप में भी एआइ फीचर्स आने लगे हैं। ये तकनीक को ही आधुनिक नहीं बनाते हैं, बल्कि काम करने के तरीके को भी बदल रहे हैं। नए लैपटाप टाइपिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग तक सीमित नहीं हैं। ये आपकी आवाज समझ सकते हैं, मीटिंग का सारांश बना सकते हैं, यहां तक कि आपके तरीके को समझकर खुद को उसी हिसाब से ढाल भी सकते हैं। माइक्रोसाफ्ट ने विंडोज 11 लैपटाप में अनेक एआइ फीचर्स जोड़े हैं, जो स्टूडेंट्स, आफिस यूजर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स आदि के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं।

माइक्रोसाफ्ट कोपायलट : यह स्मार्ट एआइ असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो सवालों के जवाब देने के साथ कई कामों में मदद भी करता है। कोपायलट की मदद से आप ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लंबे डाक्यूमेंट का सारांश बना सकते हैं। कोडिंग में भी मदद ले सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए टास्कबार में कोपायलट आइकन पर क्लिक करें या विंडोज+सी दबाएं। इसके बाद माइक्रोसाफ्ट अकाउंट से लागइन करें और टेक्स्ट या आवाज से सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। अगर यह दिखाई नहीं दे रहा, तो सेटिंग्स > विंडोज अपडेट में जाकर सिस्टम अपडेट करें।

वायस एक्सेस : वायस एक्सेस फीचर लैपटाप उपयोग को और आसान बनाता है। इससे यूजर बिना कीबोर्ड या माउस के सिर्फ आवाज से सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। आवाज से एप ओपन कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स ओपन करें, एक्सेसिबिलिटी में जाकर स्पीच विकल्प चुनें और वायस एक्सेस को आन कर दें। इसके बाद वायस एक्सेस वेक अप बोलकर इसे एक्टिव किया जा सकता है। ओपन माइक्रोसाफ्ट वर्ड या शो आल कमांड्स जैसी कमांड देकर सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो हैंड्स-फ्री काम करना चाहते हैं।

विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स : वर्क फ्राम होम और आनलाइन मीटिंग के दौर में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स बेहद उपयोगी फीचर है। यह फीचर बैकग्राउंड ब्लर करता है, चेहरे की लाइटिंग बेहतर बनाता है और आसपास की आवाज कम करता है। इससे वीडियो काल ज्यादा साफ और प्रोफेशनल दिखती है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स > ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस > कैमरा में जाएं और सपोर्टेड कैमरा चुनें। इसके बाद बैकग्राउंड ब्लर, आइ कांटैक्ट या नाइज सप्रेशन जैसे विकल्प आन किए जा सकते हैं।

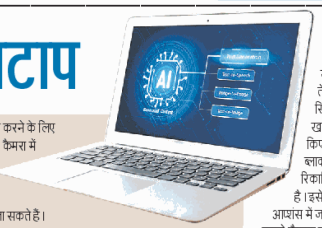

स्नैप लेआउट्स : यह स्क्रीन पर कई विंडो को सेट करने में मदद करता है। इससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। इसके लिए किसी विंडो के मैक्सिमाइज बटन पर माउस ले जाएं। वहां अलग-अलग लेआउट विकल्प दिखाई देंगे। जरूरत के अनुसार लेआउट चुनते ही बाकी एप्स स्वतः स्क्रीन में फिट हो जाएंगे। यह फीचर आनलाइन क्लास और वर्क फ्राम होम के लिए उपयोगी है।

टच जेस्चर्स : एआइ आधारित टच जेस्चर्स एक्सपीरियंस को आसान बनाते हैं। इससे अंगुलियों से एप बदल सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं और स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए सेटिंग्स > ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस > टच में जाएं और थ्री एंड फोर फिंगर जेस्चर्स को आन करें। इसके बाद स्वाइप और जेस्चर की मदद से लैपटाप को कंट्रोल किया जा सकता है।

लाइव कैप्शंस : एआइ फीचर लाइव कैप्शंस किसी वीडियो या आडियो को रियल टाइम में सबटाइटल में बदल सकता है। अलग-अलग भाषाओं में वीडियो देखने के लिए यह उपयोगी है। आन करने के लिए विंडोज+कंट्रोल+एल दबाएं या फिर सेटिंग्स > एक्सेसिबिलिटी > कैप्शंस में जाकर लाइव कैप्शंस को आन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर सबटाइटल दिखाई देने लगेंगे।

कोक्रिएटर और क्लिपचैंप : ये कंटेंट क्रिएशन को आसान बनाते हैं। पेंट कोक्रिएटर टेक्स्ट के आधार पर डिजिटल आर्ट बना सकता है, जबकि क्लिपचैंप वीडियो एडिटिंग को आसान बनाता है। ये फीचर्स क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं।

संतोष आनंद

एआइ से मजबूत हुई सुरक्षा

जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, साइबर खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विंडोज 11 वाले लैपटाप में एआइ आधारित सिक्योरिटी फीचर्स यूजर को मैलवेयर और रैनसमवेयर जैसे खतरों से बचाने में मदद करते हैं। स्मार्ट एप कंट्रोल डाउनलोड किए गए एप्स को स्कैन करता है और खतरनाक एप्स को ब्लाक कर सकता है। वहीं विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट और फेस रिकाग्निशन जैसी सुविधाओं के जरिये सुरक्षित लागइन भी देता है। इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग्स > अकाउंट्स > साइन-इन आप्शंस में जाएं और फेस रिकाग्निशन, फिंगरप्रिंट या पिन सेट करें। इससे लैपटाप ज्यादा सुरक्षित बन जाता है।

आज का भविष्यफल : 14 मई, 2026 गुरुवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी का राशिफल।

आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक।

आज का दिशाशूल : दक्षिण

आज का पर्व एवं त्योहार : प्रदोष व्रत

विशेष : पंचक (रात्रि 10:34 बजे समाप्त), बुध वृष में, शुक्र मिथुन में।

कल 15 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पश्चिम

विशेष : सूर्य वृष में, चतुर्दशी तिथि क्षय।

भद्रा : प्रातः 8:32 बजे से सायं 6:52 बजे तक।

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 08 घंटे 32 मिनट तक, तत्पश्चात चतुर्दशी अश्वनी नक्षत्र 20 घंटे 15 मिनट तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र आयुष्मान योग 14 घंटे 22 मिनट तक, तत्पश्चात सौभाग्य योग मेष में चंद्रमा।

मेष : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

वृष : जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

मिथुन : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क : पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीविका में प्रगति होगी।

सिंह : शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। तनाव समाप्त होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी।

कन्या : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अप्रिय समाचार मिल सकता है। जीविका में प्रगति होगी।

तुला : सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिल सकता है।

धनु : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

मकर : निजी सुख में व्यवधान आएगा। अप्रिय समाचार मिल सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, सम्मान, यश में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।

मीन : आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।

वर्ग पहेली - 3334

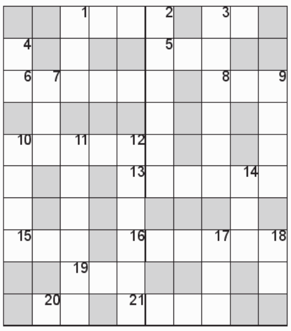

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1. समर्थन या पुष्टि करने वाला (4)।
3. अभी, इस समय (2)।
5. स्वप्न (3)।
6. फणीश्वर नाथ 'रेणु' की एक कहानी (3,3)।
8. नया एवं कोमल पत्ता (3)।
10. अमिताभ बच्चन की एक फिल्म (2,4)। 13. बहुत मामूली, तुच्छ (3,3)। 15. छटपटाहट (3)।
16. प्रबंध करना (3,3)।
19. प्रीति, प्रेम (3)।
20. गलती (2)।
21. स्थानीय होने का बोध या भाव (4)।

ऊपर से नीचे :
1. सवार होने वाला व्यक्ति, सवार का साधन (3)।
2. कुलबुलाहट (6)।
3. आलतू-फालतू (3,3)।
4. पतिव्रता, साध्वी (2)।
7. बलयुक्त, शक्तिशाली (3)।
9. जंगल में जीवन-यापन करने वाला (4)।
10. ललचाया हुआ (4)।
11. बच्चे की चंचलता (2,4)।
12. राज-काज (3,3)।
14. झोपड़ा (3)।
17. रसात्मक काव्य (3)।
18. बर्बाद, नष्ट (2)।

कल का हल

म1	हा	न	त	म2		प3	श्चा	ता	प4
हा				र					र
दे		अ5	व6	ता	र7		कों8		मा
श			क्रि		त9	र	ल		नं
		स10	त	ल11	ज		ता12	की	द
मा13	म	ला		ल14	गा	ता15	र		
था		म16	न	का		ब			स17
टे		त		र18	ग19	ड़	ना		म
क					म				झौ
ना20	म	ज	द		न21	पुं	स	क	ता

सुडोकू - 3334

	5			3		8	7	
	9				1			4
7			6		5		9	
6			5			7		9
		9			8	4		
		1		9				2
9			8			1		7
	2			6			3	
8				1		9		

कल का हल

6	2	3	4	1	9	8	5	7
4	9	5	8	7	2	6	1	3
1	8	7	3	6	5	9	4	2
8	7	6	5	9	3	4	2	1
2	1	9	7	4	6	3	8	5
3	5	4	2	8	1	7	6	9
9	3	8	1	5	4	2	7	6
7	6	1	9	2	8	5	3	4
5	4	2	6	3	7	1	9	8

राष्ट्रीय फलक

अलगाववादी सोच का समर्थन करते हैं मुस्लिम

- दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, मुस्लिमों में राष्ट्रवादी नेता हो गए हैं दुर्लभ
- आरएसएस प्यार का नहीं लव जिहाद का विरोधी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुस्लिम नेतृत्व में किसी नेता का राष्ट्रवादी होना इन दिनों दुर्लभ है। मुस्लिमों में उस नेता को समर्थन मिलता है जो अलगाववादी सोच का होता है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने विशेष साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता होते थे। लेकिन अब उन्हें समर्थन नहीं मिलता है।

होसबाले ने यह बात हाल ही में एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर कही है जिसमें ओवैसी ने मुस्लिमों से अपना धर्म आधारित नेतृत्व खड़ा करने की बात कही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी को लगता कि देश की तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं कर सकती हैं। होसबाले ने कहा, यह आह्वान अलग विचारधारा का द्योतक है। उन्होंने कहा, स्त्री और पुरुष के बीच सच्चे प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है लेकिन जब यह सुनियोजित षडयंत्र के तहत होता है तब उसका विरोध होता है। देश में ऐसे षडयंत्र वाला प्यार हिंदू लड़कियों को मुश्किल में डालने वाला है। संघ इसे लव जिहाद कहता है और इसका विरोध करता है। सर कार्यवाह ने कहा, आरएसएस में बहुत से स्वयंसेवक हैं जिन्होंने धर्म और जाति से बाहर जाकर विवाह किए हैं। उन्होंने सच्चे प्यार से वशीभूत होकर ऐसा किया और संघ ने उन रिश्तों को स्वीकार किया।

दत्तात्रेय होसबाले। फाइल

एक प्रश्न के उत्तर में होसबाले ने कहा, आरएसएस को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है, इसे लेकर किसी को शक नहीं होना चाहिए। देश में रहने वाले गैर हिंदुओं को भी इससे सशंकित होने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे भी हिंदुओं से अलग नहीं हैं। उनके पूर्वज हिंदू थे और उनका डीएनए भी हिंदुओं के समान ही है। आरएसएस नेता ने कहा, देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ खुद को अल्पसंख्यक भी कहते हैं। लेकिन किसी के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार नहीं होता है।

आरएसएस को सुवेंदु अधिकारी पर गर्व : होसबाले ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर गर्व है। संगठन उन्हें अपना पुत्र मानता है। उन्हें संघ में शामिल होने या संगठन की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। जब जो चाहे संघ में शामिल हो सकता है। होसबाले ने कहा, जिस प्रकार से कोई लड़की विवाह के बाद नए परिवार में आकर स्वतः उसका हिस्सा बन जाती है और विकास में योगदान देती है। उसे परिवार का सदस्य बनने के लिए कोई फार्म नहीं भरना होता है।

कर्नाटक के स्कूल-कालेजों में जनेऊ व हिजाब की अनुमति

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कालेजों में यूनिफार्म के साथ जनेऊ, हिजाब समेत कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति दे दी है। सरकार ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि छात्र हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा और रुद्राक्ष जैसे सीमित धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे, बशर्ते इससे अनुशासन, सुरक्षा और पहचान में कोई दिक्कत न हो।

यह फैसला 2022 में भाजपा सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद आया है। कांग्रेस सरकार ने कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक प्रतीक पहनने के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य में जो धार्मिक परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, उन्हें सीमित रूप से अनुमति दी गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो। वहीं भाजपा ने इस फैसले का विरोध किया है।

लाजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली अव्वल

- 11 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में रखा गया
- 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उत्प्रेरक श्रेणी में रखा गया है

नई दिल्ली, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली को 2025 के लिए लाजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग में 'उत्कृष्ट' श्रेणी में रखा गया है। लीड्स (विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक सुगमता) 2025 रिपोर्ट के अंतर्गत जारी लाजिस्टिक सूचकांक चार्ट, निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लाजिस्टिक सेवाओं की दक्षता को बताता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'उत्कृष्ट' श्रेणी उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है जो लाजिस्टिक क्षेत्र में नीति, बुनियादी ढांचा, सेवा वितरण और नियामक आयामों में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शित करते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) का लीड्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाजिस्टिक प्रदर्शन का प्रमुख राष्ट्रीय मूल्यांकन है। यह देशभर में लाजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मानक और सुधार उपाय के रूप में कार्य करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहां यह रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू- कश्मीर तथा पुडुचेरी को 'उच्च प्रदर्शन करने वाले' श्रेणी में रखा गया है।

उच्च प्रदर्शन करने वाले उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहते हैं जो अधिकांश प्रदर्शन संकेतकों में मजबूत और निरंतर परिणाम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'उत्प्रेरक' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं। 'उत्प्रेरक' श्रेणी में वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार की गति और स्पष्ट सुधारवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। 'वृद्धि चाहने वाले' श्रेणी में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

वृद्धि चाहने वाले उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लॉजिस्टिक प्रणाली विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रारंभिक चरण में हैं। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत एकीकृत, आंकड़ा-आधारित लॉजिस्टिक सुधारों पर सरकार के जोर को दर्शाती है।

सोवियत संघ के नेतृत्व में आठ देशों ने की वारसा संधि की स्थापना

1955 में आज ही आठ साम्यवादी देशों ने वारसा संधि की स्थापना की थी। सोवियत संघ के नेतृत्व में पोलैंड की राजधानी वारसा में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो का मुकाबला करना और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

ब्रिटेन में लगाया गया चेचक का पहला सफल टीका

1796 में आज ही इंग्लैंड के डा. एडवर्ड जेनर ने 8 वर्षीय रोगी को चेचक का पहला सफल टीका लगाया था। इसे उन्होंने गाय के चेचक के घाव से प्राप्त सामग्री से विकसित किया था। इसके लिए उन्होंने लैटिन शब्द वक्का से वैक्सीन शब्द गढ़ा जिसका अर्थ गाय होता है।

आजीवन देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहे अरुण चंद्र

अरुण चंद्र गुहा का जन्म 1892 में आज ही अविभाजित भारत के बारीसाल (अब बांग्लादेश में) में हुआ था। 1906 में जुगांतर पार्टी में शामिल होकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और जेल गए। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए सरस्वती लाइब्रेरी नामक पब्लिशिंग हाउस चलाया। साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीनता भी प्रकाशित की, जिसे 1930 में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के तहत गठित संसद की प्राक्कलन समिति (1965-66) के अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यप्रणाली सुधारने में योगदान दिया था।

वजन कम करने के लिए अचानक खाना कम करना खतरनाक

चेतावनी ▶ खराब जीवनशैली, दिनभर बैठकर लगातार काम करते रहना और जंक फूड्स से बढ़ता है वजन

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद को अपनाना है जरूरी

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क: वजन बढ़ना मौजूदा समय की सबसे चिंताजनक समस्याओं में से एक है। यह कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। जिस तरह से बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि खराब जीवनशैली, दिनभर बैठकर काम करते रहना, जंक फूड्स की आदत और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ऐसे में वजन कम करने के लिए कोई खाना लगभग बंद कर देता है तो कोई घंटों व्यायाम करता है पर क्या वास्तव में इससे लाभ मिलता है? विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ तरीके से वजन कम करने का मतलब केवल कम खाना नहीं बल्कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद व लंबे समय तक टिकने वाली आदतों को अपनाना है।

वजन कम करने के लिए क्या गलतियां न करें? : अध्ययनों से पता चलता है कि अचानक खाना कम देने से मेटाबालिज्म धीमा पड़ सकता है, जिससे बाद में वजन और तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं जरूरत से ज्यादा व्यायाम से शरीर में थकान, चोट का खतरा बना रहता है।

बहुत ज्यादा व्यायाम भी खतरनाक : स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वजन घटाने के लिए व्यायाम जरूरी है पर आहार व जीवनशैली भी महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा व्यायाम मांसपेशियों में चोट, थकान और शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ सकता है। इससे तनाव व वसा का भंडारण बढ़ सकती है। बिना आराम दिए व्यायाम करने से मांसपेशियों की रिकवरी नहीं हो पाती।

प्रतीकात्मक

अचानक खाना छोड़ना ठीक नहीं

अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ देने से वजन तेजी से कम हो जाएगा, लेकिन असल में ये तरीका शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

- क्रैश डाइटिंग में लोग जरूरत से बहुत कम कैलोरी लेते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, जब आप खाना कम कर देते हैं तो शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और मेटाबालिज्म धीमा हो जाता है।
- अचानक खाना कम करने वाले लोगों में कमजोरी, चक्कर आने, बाल झड़ने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

सिर्फ कैलोरी कम करने से नहीं चलेगा काम

- वजन कम करने के दौरान लोग पोषण पर ध्यान नहीं देते। प्रोटीन की कमी होना बड़ी समस्या है।
- प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। जब लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो वजन घटने के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं।
- वजन कम को दाल, पनीर, अंडे, दही व हरी सब्जियों को आहार में शामिल करें।
- वजन कम करने के लिए अच्छी नींद और तनाव को कंट्रोल करना भी जरूरी है।
- जब शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं। इससे ज्यादा भूख लग सकती है और कैलोरी इंटेक बढ़ सकती है।

न्यूयार्क की गवर्नर ने भारतीय शेफ विकास खन्ना को किया सम्मानित

विकास खन्ना। फाइल

न्यूयार्क, प्रेट्र : न्यूयार्क की गवर्नर कैथी होचुल ने भारतीय शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया। वह न्यूयार्क में एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीपवासी (एएपीआइ) विरासत माह के दौरान सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

उन्हें पाक कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में खन्ना ने सम्मान को "अत्यंत भावुक और विनम्रतापूर्ण" बताया और कहा, "इस सम्मान को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि न्यूयार्क राज्य के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय हैं।" एएपीआइ अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ता समुदाय है, जो दो करोड़ से अधिक लोगों, संस्कृतियों, कहानियों, संघर्षों और लोगों के सपनों का प्रतिनिधित्व करता है।

विकास खन्ना ने कहा, "यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। यह आशा, पहचान, प्रतिनिधित्व और विविधता की शक्ति का प्रतीक है।" उन्होंने कहा, "एक भारतीय शेफ को इस मंच पर लाना मेरे लिए सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी कहानियां मायने रखती हैं, हमारी संस्कृति मायने रखती है।"

इधर-उधर

चीन के स्कूल में गुड़िया से पाठ पढ़ रहे छात्र

बच्चों की तरह करनी होती है गुड़ियों की देखभाल। इंटरनेट मीडिया

बीजिंग, एजेंसी: चीन के एक स्कूल ने एक अनोखी शिक्षण पद्धति अपनाई है, जिसमें छात्रों को पूरे दिन गुड़िया लेकर घूमना पड़ता है। शुझोऊ का एक स्कूल उन किशोरों को प्रवेश देता है जिन्हें संभालना मुश्किल है, जैसे विद्रोही व्यवहार, आनलाइन गेमिंग की लत वाले छात्र। एक वीडियो में छात्रों को कक्षाओं में 2.5 किग्रा की गुड़िया लेकर चलते और लंच के समय पकड़े हुए देखा जा सकता है ताकि वे बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता द्वारा किए जाने वाले शारीरिक परिश्रम का अनुभव कर सकें।

हड्डियों को मजबूत करने वाला छिपा हुआ आणविक स्विच खोजा गया

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : विज्ञानियों ने हड्डियों को मजबूत करने और आस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए एक छिपा हुआ आणविक स्विच खोजा है। मैकगिल विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने आणविक "स्विच" का पता लगाया है जो ब्राउन फैट में एक शक्तिशाली कैलोरी जलाने वाली प्रणाली को सक्रिय करता है, जो शरीर की गर्मी पैदा करने वाली वसा है और मेटाबालिज्म तथा वजन नियंत्रण से जुड़ी है। यह खोज ग्लिसरोल पर केंद्रित है, जो एक अणु है जो ठंड में वसा के टूटने पर रिलीज होता है, जो एक एंजाइम टीएनएपी को सक्रिय करता है और एक वैकल्पिक गर्मी पैदा करने वाले मार्ग को तेज करता है।

विज्ञानियों ने चूहों में एक आणविक "स्विच" का पता लगाया है जो ब्राउन फैट के अंदर एक छिपी हुई ऊर्जा जलाने वाली प्रणाली को सक्रिय करता है। यह एक खोज है जो अंततः शोधकर्ताओं को हड्डी की बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित करने में मदद करती है। नेचर में प्रकाशित ये निष्कर्ष बताते हैं कि ब्राउन फैट कैसे काम करता है। व्हाइट फैट सफेद वसा के विपरीत, जो ऊर्जा को संग्रहीत करता है, ब्राउन फैट कैलोरी को जलाकर गर्मी पैदा करता है। विज्ञानियों का मानना था कि यह गर्मी उत्पादन एक एकल जैविक मार्ग पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं ने मूल मार्ग के साथ-साथ काम करने वाले एक दूसरे मार्ग की पहचान की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसे क्या सक्रिय करता है। मैकगिल विश्वविद्यालय के रोसलिंड और मारिस गुडमैन कैंसर संस्थान में लारेंस कजाक के नेतृत्व में एक टीम ने अब इस वैकल्पिक प्रणाली के आणविक ट्रिगर की पहचान की है, जिसे फ्यूटाइल क्रिएटिन चक्र के रूप में जाना जाता है।

- शोधकर्ताओं ने आणविक स्विच या सीसीएन3 नामक हार्मोन की पहचान की है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में भूमिका निभाता है
- यह स्विच हड्डियों के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे कमजोर हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है

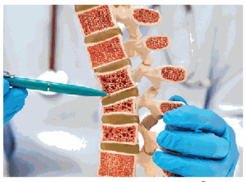

प्रतीकात्मक

विज्ञानियों ने ब्राउन फैट का "आन स्विच" पहचाना : जब शरीर ठंडे तापमान के संपर्क में आता है, तो यह गर्मी पैदा करने के लिए संग्रहीत वसा को तोड़ता है। इस प्रक्रिया में ग्लिसरोल रिलीज होता है, जो वसा के मेटाबालिज्म के दौरान पैदा होता है। मैकगिल के जीवविज्ञानी अल्बा गुआर्न के साथ काम करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्लिसरोल एक एंजाइम टीएनएपी से बंधता है, जिसे उन्होंने ग्लिसरोल पाकेट के रूप में वर्णित किया है। यह इंटरैक्शन वैकल्पिक गर्मी पैदा करने वाले मार्ग को सक्रिय करता है। बायोकैमिस्ट्री विभाग में सहायक प्रोफेसर और एडिपोसाइट बायोलाजी में कनाडा रिसर्च चेयर कजाक ने कहा, यह पहली बार है जब पहचाना है कि एक वैकल्पिक गर्मी पैदा करने वाला मार्ग कैसे सक्रिय होता है, जो पारंपरिक प्रणाली से स्वतंत्र है। यह समझने के लिए दरवाजा खोलता है कि कैसे कई ऊर्जा जलाने वाली प्रणालियां एक साथ काम करती हैं ताकि शरीर को सही तापमान पर गर्म रखा जा सके।"

यह खोज हड्डियों की बीमारियों पर शोध को आगे बढ़ाती है : ब्राउन फैट ने मेटाबालिज्म और मोटापे के शोध में संभावित भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे तत्काल महत्व हड्डी के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है क्योंकि टीएनएपी पहले से ही हड्डी के निर्माण में अच्छी तरह से स्थापित भूमिका निभाता है।

बुजुर्गों में आंतरिक क्षमता से लंबी आयु का लगाया जा सकता है अनुमान

अनुसंधान

द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया पत्रिका में प्रकाशित हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में बुजुर्गों में मजबूत आंतरिक क्षमता (इंट्रिंसिक कैपेसिटी) मृत्यु के जोखिम को कम करने से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से बेहतर बौद्धिक क्षमता, अच्छा पोषण और बेहतर गतिशीलता शामिल है।

आंतरिक क्षमता का मतलब किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के समग्र योग से है, जो उम्र बढ़ने के साथ उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह सक्रिय जीवन जीने की क्षमता का आकलन करती है, जिसमें चलना-फिरना, मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन शक्ति और संवेदी (देखने/सुनने) क्षमताएं शामिल हैं। शोध दल ने भारत में डिमेंशिया के निदान संबंधी आकलन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 4096 बुजुर्ग शामिल थे।

उन्होंने पाया कि मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को मापने वाली आंतरिक क्षमता, मृत्यु दर की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण थी। विशेष रूप से, जीवित रहने के सबसे मजबूत भविष्यवक्ता बौद्धिक क्षमता, पोषण और गतिशीलता क्षमता थे। यह अध्ययन बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों को तैयार करते समय केवल बीमारियों के बजाय कार्यात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को उजागर करता है। निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के ढांचे को भी मान्य करते हैं, जो बताता है कि आंतरिक क्षमता की जांच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुजुर्गों में कमजोरियों का पता लगाने में सहायक हो सकती है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

लोग उम्र को लेकर आपसे ज्यादा परेशान रहते हैं : तब्बू

सिनेमा इंडस्ट्री में पहले उम्र बढ़ने के बाद अभिनेत्रियों के लिए फिल्मों में काम पाना मुश्किल हो जाता था। फिर उन्हें कुछ एक खास गिने चुने रोल ही मिलते थे। हालांकि, अब इंडस्ट्री में काफी बदलाव हो चुका है, लेकिन अभिनेत्री तब्बू का मानना है कि आज भी लोग अभिनेत्रियों को उनकी उम्र याद दिलाना नहीं भूलते।

बढ़ती उम्र को लेकर इंडस्ट्री के व्यवहार पर तब्बू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'लोग आपकी उम्र को लेकर आपसे ज्यादा परेशान रहते हैं। वे आपको आईना दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में आईना ही न हो। अब आप जिस इंसान से उसकी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी उम्र तो रातों रात नहीं बढ़ गई। हम इसे हर दिन महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई 20 साल की उम्र में उठता है और अगले दिन 45 का हो जाता है।' आगे तब्बू ने यह भी बताया कि इंडस्ट्री में अक्सर लोग उन्हें सीधा और सही बोलने से बचने का भी सुझाव देते हैं। फिल्मों को इन्कार करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लोग सुझाव देते हैं कि आपको फिल्म न करने का कोई असली कारण नहीं बताना चाहिए। डेट्स का बहाना बनाओ और आगे बढ़ो। मुझे यह समझ नहीं आया। अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, तो मुझे वह पसंद नहीं है और मैं ऐसे ही कहती हूं।

अगली फिल्म नागार्जुन अक्किनेनी के साथ कर रही हैं तब्बू फाइल

...इस घटना ने तोड़ दिया मेरा अहंकार

रजनीकांत ने फिल्म जेलर 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा उनके पास दो फिल्में हैं।

@rajinikanth.official

सुपरस्टार रजनीकांत के प्रशंसक दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेता ने एक ऐसा किस्सा साझा किया, जब एक सार्वजनिक जगह पर किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं था और इससे उनका अहंकार टूट गया था। हाल ही में एक आध्यात्मिक गुरु के साथ रजनीकांत ने अपने अतीत की उस घटना को याद किया। अभिनेता ने बताया कि करियर के शिखर पर उन्हें उम्मीद थी कि जहां भी जाएंगे, लोग उन्हें पहचानेंगे और सम्मान देंगे। इसी वजह से वह गुरु के साथ आश्रम घूमने जाने में झिझक रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से वहां कोई हलचल मचे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि लोग मुझे पहचानेंगे, मेरा नाम चिल्लाएंगे, फोटो खिंचवाने आएंगे। मैंने वहां कई तमिल लोगों को भी देखा था। वहां हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फोटो और आटोग्राफ तो दूर, किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और न ही मुझसे बात की। इस घटना ने मेरा अहंकार तोड़ दिया।' जब गुरु ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वहां कोई परेशानी नहीं होगी, तो रजनीकांत ने मजाकिया अंदाज में सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इधर डिस्टर्ब हो गया। यही अध्यात्म की असली ताकत है।

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

मां के लाडले शरद को पसंद हैं खलनायक वाले रोल

ज्यादातर कलाकार हीरो का रोल ही करना चाहते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा हो, लोग उनसे प्यार करें। हालांकि अभिनेता शरद मल्होत्रा ऐसा नहीं सोचते हैं। शरद ने कई धारावाहिकों में हीरो वाले रोल ही किए हैं, जहां वह एक अच्छे इंसान के साथ सब कुछ सही करते हैं। लेकिन जहां तक एक्टिंग में परफार्म करने की बात है, तो शरद वहां, हीरो के पाजिटिव रोल की बजाय निगेटिव रोल को अहमियत देते हैं। एसीपी विक्रांत वेब सीरीज में नजर आए शरद कहते हैं कि मैंने अपने करियर में कभी खुद को किसी रोल को करने से रोका नहीं। लेकिन अब मुझे खलनायक वाले रोल करने हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास निगेटिव रोल ज्यादा आते नहीं हैं, जबकि वह पात्र मुझे ज्यादा उत्सुक करते हैं। ग्रे रोल आते हैं, जिसमें बहुत सी परतें होती हैं, लेकिन वह खलनायक नहीं होता है। (हंसते हुए) मैं अच्छा लडका हूं, मां का लाडला भी हूं, लेकिन जब डार्क और परतदार रोल मिलते हैं, तो मजा आता है। मैंने अपना अगला प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है, जिसकी शूटिंग भी चल रही है।

ओटीटी पर काफी काम कर रहे हैं शरद फाइल

राका के सिग्नेचर मूव अधिकार सुरक्षित करने पर विचार

फिल्म पुष्पा में अभिनेता अल्लू अर्जुन के स्टाइल और संवादों के साथ श्रीवल्ली.. गाने में एक पैर घसीटते हुए डांस करने वाला स्टाइल भी खूब लोकप्रिय हुआ था। फिल्म का संवाद झुकेगा नहीं साला के देश के साथ-साथ विदेश में भी खूब रील्स और अलग-अलग क्रिएटिव वीडियो बनाए गए। हालांकि, अब अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म राका के निर्माता ऐसे सिग्नेचर मूव्स के अधिकार सुरक्षित कराने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन के दमदार स्टाइल को देखते हुए फिल्म राका के निर्माता भी इन मामलों में कुछ बड़ी और अनोखी योजनाएं बना रहे हैं। खासतौर पर फिल्म के सिग्नेचर मूव को लेकर टीम काफी तैयारी कर रही है, जिससे उसे दर्शकों के बीच सही तरीके से पेश किया जा सके। इसीलिए राका के निर्माताओं और अल्लू अर्जुन ने फिल्म के सिग्नेचर मूव्स के अधिकार सुरक्षित कराने का निर्णय लिया है। निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राका के सिग्नेचर स्टेप का कमर्शियल गलत प्रयोग न हो। बता दें कि एटली कुमार के निर्देशन में बन रही राका में अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में हैं।

फिल्म राका में केंद्रीय भूमिका में होंगे अल्लू अर्जुन फाइल

धुरंधर के लिए एक करोड़ बोनस मिलने पर बोले राकेश बेदी...

धुरंधर में सराहा गया था राकेश का काम फाइल

फिल्म हिट होती है, तो उसका फायदा उसमें काम करने वाले कलाकारों को भी मिलता है। फिल्मकार आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट ने भी उसमें काम करने वाले कलाकारों के लिए कई रास्ते खोले। खासकर अभिनेता राकेश बेदी के लिए जिनका अभिनय काफी सराहा गया था। उसके बाद खबरें कि निर्माताओं ने उनके काम से खुश होकर उन्हें फीस से इतर एक करोड़ रुपये बोनस में दिया। अब एक साक्षात्कार में राकेश ने कहा कि जो अफवाहें उड़ी एक करोड़ वाली उसको सच करने का मेरे पास तरीका है। सब मेरा नाम का प्रयोग कर रहे है, मीम्स बना रहे हैं। कार्टून बना रहे हैं। उसका फायदा मुझ भी तो होना चाहिए ना। राकेश का यह मजाकिया जवाब उनकी उस प्रतिक्रिया के बाद आया है, जब उन्होंने कहा था कि उनके अकाउंट में अब तक एक करोड़ की रकम जमा नहीं हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में जल्द 50 साल पूरे करने वाले राकेश ने कहा कि जो आना होगा आ जाएगा, मैं वैसा एक्टर नहीं हूं जो यह सोचकर निराश हो जाऊं कि क्यों मुझे वैसे रोल नहीं मिले, जो मिलने चाहिए थे। जीवन में मुझे जब जो मिला, मैं उससे खुश रहा हूं।

नो एंट्री की सीक्वल में शाहिद!

@shahidkapoor

साल 2009 में प्रदर्शित हुई सलमान खान, फरदीन खान और अनिल कपूर अभिनीत फिल्म नो एंट्री की सीक्वल की चर्चा सिनेमाई गलियारों की में पिछले कई वर्षों से है। हालांकि, बीच-बीच में फिल्म की राह में कोई न कोई रोड़ा आ जा रहा है। निर्देशक अनीस बज्मी पहले इस फिल्म को सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान के साथ ही बनाना चाहते थे। हालांकि, सलमान के साथ उनकी बात न बन सकी और फिर उन्होंने यह फिल्म वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ के साथ बनाने के निर्णय लिया। फिर दिलजीत और वरुण के भी यह फिल्म छोड़ने की खबरें आईं जिससे फिल्म फिर लटक गई। अब अनीस ने एक बार फिर से नो एंट्री की सीक्वल के लिए कमर कसी है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस फिल्म के लिए अभिनेता शाहिद कपूर से संपर्क किया है। शाहिद ने भी इस फिल्म में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। शाहिद की एंट्री से इस फिल्म को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वरुण और दिलजीत फिल्म से दोबारा जुड़ चुके हैं।

मुझे फिल्म बेचना नहीं आता है: पुलकित

@justpulkit

पिछले साल प्रदर्शित राजकुमार राव अभिनीत फिल्म मालिक टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं कर पाई थी जिसके बाद हाल ही में इसके निर्देशक पुलकित को लेकर खबरें आईं कि वह मालिक के फाइनल कट से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि, पुलकित इसमें निर्माताओं या फिल्म की टीम के हस्तक्षेप को कारण नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं मालिक के फाइनल कट से नहीं, बल्कि वो सिनेमाघरों में जिस तरह से दिख रही थी, उससे खुश नहीं था। आजकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सिनेमाघरों में क्या बिकता है। मेरी सेल्समैन वाली सोच नहीं है, मुझे फिल्म बेचना नहीं आता है, मैं बस ईमानदारी से फिल्म की कहानी सुना सकता हूं। सिनेमाघरों में रिलीज करने को लेकर मैं भी कुछ चीजों को लेकर असमंजस में पड़ गया था, जिससे कुछ चीजें लिखते समय तो कुछ और थी, लेकिन फिल्म बनाते समय कुछ और हो गई। मैं उसे अपनी हार नहीं, बल्कि अपनी सीख मानता हूं। आगे से जब मैं सिनेमाघरों के लिए भी कोई फिल्म बनाउंगा तो कुछ बेचूंगा नहीं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस फिल्म के क्रिएटिव मामलों में किसी का हस्तक्षेप नहीं था।'

मौनी राय ने की लोगों से निजता की अपील

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन : शिवा और गोल्ड फिल्म की अभिनेत्री मौनी राय इन दिनों अपने व्यवसायी पति सूरज नांबियार से अलगाव की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। मौनी और सूरज अक्सर इंटरनेट मीडिया पर खुलकर अपना प्यार व्यक्त करते रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खूब तस्वीरें भी साझा करते रहे। इस बीच दोनों के बीच अलगाव की खबरों ने तब हवा पकड़ी जब दोनों ने पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करना बंद कर दिया। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को अनफालो भी कर दिया। हालांकि, सूरज और मौनी दोनों की तरफ से इस बार में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। बुधवार को मौनी ने पहली बार इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी और फैंस से जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालने की गुजारिश की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'सभी मीडिया हाउस से विनम्र निवेदन है कि गलत खबरें ना छापें। कृपया हमें एकांत और निजता प्रदान करें।' इसके साथ ही मौनी ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में लोगों से चर्चा बंद करने के लिए हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी साझा की। बता दें कि मौनी और सूरज साल 2018 में पहली बार नए साल की पार्टी के दौरान मिले थे। दोनों ने जनवरी, 2022 में एक दूसरे से शादी की। उनके पति सूरज नांबियार एक उद्योगपति हैं।

@imouniroy